खण्ड–507, अंक–04
शुक्रवार, 19 माघ, शक संवत् 1940
(08 फरवरी, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2019)

(खण्ड 507 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी) ...	7
प्रश्नोत्तर	8-43
सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना (क्रमागत)	43-44
श्री मो0 फईम इरफान द्वारा व्यवस्था के अन्तर्गत उनका व्यक्तिगत प्रकरण ...	44-45
सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना	45-55
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	55
विधान भवन में स्मोकिंग जोन बनाए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30 अगस्त, 2018 को नियम-300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	55-56
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	56-58
जनपद महोबा के विकास खण्ड चरखारी के अन्तर्गत बम्हौरी कला से इमिलिया सम्पर्क मार्ग में रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बसे गांवों के तटबन्धों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद बहराइच के सरयू नहर खण्ड-5 के अन्तर्गत ग्राम अमदापुर व मल्लव के निकट नहर पट्टी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी के प्रेम नगर, बागराजपुर चुंगी क्षेत्र में नालियों एवं गलियों का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
प्रदेश में आवास विकास परिषद् द्वारा आवास आवंटियों को ब्याज मुक्त समाधान योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59-60

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के पेंशन निर्धारण एवं कैरियर प्रोन्नयन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
जनपद मिर्जापुर के ब्लाक सीटी के अन्तर्गत टांडा फाल से निकाली गयी हरई माइनर का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय मार्गों का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन रेहड़ी रजबहे के दोनों ओर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम पंचायत पतेई एमन के मजरों एवं गांवों को गंगा की धारा से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद उन्नाव के सफीपुर एवं मियागंज में आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर फण्ड ऐक्ट बनाकर सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक रूप से प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
माननीय विधायकों को विकास हेतु दिये गये 5 करोड़ रुपये के सापेक्ष उनके प्रस्ताव पर विचार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद रायबरेली के ब्लाक अमावां अन्तर्गत जिला पंचायत की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज को नगर पालिका घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64
जनपद श्रावस्ती में खनन माफियाओं एवं खनन अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के ग्रीन बेल्ट में कालोनाइजरों द्वारा किये गये अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65-66

विषय	पृष्ठ-संख्या
मुजफ्फरनगर सदर के गांधी राजकीय पालीटेक्निक में पेपर टेक्नोलाजी का नया विषय प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
लखनऊ मेट्रो रेल सेवा का विस्तार लखनऊ विश्वविद्यालय से ए0के0टी0यू0 परिसर तक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद बागपत के ग्राम इब्राहिमपुर मजरा में श्मशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का दशम् प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	67
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का ग्यारहवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	67-68
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का बारहवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	68
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का तेरहवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	68
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का चौदहवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	68
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	68-69
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का सोलहवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	69
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का सत्रहवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	69
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	69
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का उन्नीसवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	69-70
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का बीसवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	70

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का इक्कीसवां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया) ...	70
उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-2018) का 143वां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया)	70
उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 144वां प्रतिवेदन ... (प्रस्तुत किया गया)...	70-71
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं .... (उपस्थित की गईं)	71-72
श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका ..... (स्थगित)	72
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका .... (उपस्थित की गई)	72
श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका .... (उपस्थित की गई)	73
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका .... (उपस्थित की गई)	73
भूलवश श्री मनीष असीजा द्वारा अपना संकल्प प्रस्तुत किया जाना ...	73
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ... (जारी)...	74-127
भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)	127
बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना कराये जाने विषयक डॉ0 अरुण कुमार द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प (समाप्त)	127-128
जनपद-फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध काँच उद्योग में गर्म काँच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)	128

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-शाहजहांपुर, विकास खण्ड-खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी काण्ड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प... (समाप्त)	128
जनपद-कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)	128
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)	129
जनपद-फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी) ...	129
जनपद-प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापन कराये जाने विषयक डॉ0 आर0के0 वर्मा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)	129
जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)...	129
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना कराये जाने विषयक श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)	129-130

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत नगर पंचायत कटरा को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प..(जारी)	130
प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी) ...	130
जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)	130
औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री फतेह बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)	130
जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प... (जारी)	130
जनपद सीतापुर के गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु महमूदाबाद सहकारी समिति, सीतापुर द्वारा संचालित रामगढ़ चीनी मिल, रामगढ़, सीतापुर एवं दि सेकसेरिया शुगर फैक्ट्री बिसवाँ, सीतापुर द्वारा समानुपातिक रूप से गन्ना क्रय किये जाने की नीति निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प ... (समाप्त)	131
खेती में प्रयोग किये जा रहे खतरनाक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाले भयंकर रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं पक्षाघात की जागरूकता विषयक जानकारी शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प .... (जारी) ...	131
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उप-मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प .... (जारी) ...	131

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग के अधीन राज्य योजना के अन्तर्गत चैनेज 150.3 से 174.1 गोड़रिया से तमकुहीराज तक 04 वर्ष से अधूरे पड़े बी0एम0सी0टी0 मार्ग के चौड़ीकरण की कार्यवाही शासन द्वारा शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प .... (व्यपगत)... ...	131
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	132-134
जनपद जौनपुर में तहसील मड़ियाहूं में फर्जी निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लीना तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	134
जनपद अलीगढ़ में कटपुला रसलगंज जीटी रोड व लल्लामल बगीची शाहजमाल के मध्य प्राइवेट बसों का संचालन रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य	133-136
उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... (स्थगित)	136
जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 को बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं उनके ड्राइवर की हत्या के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	136-138
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत सरकारी राशन की दुकानों में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	138-139
जनपद शाहजहांपुर में दुर्घटना बीमा का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा, श्री मानवेन्द्र सिंह तथा प्रिंस वीर विक्रम सिंह सदस्यगणों द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	139-142

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के कतिपय ग्रामों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	142-143
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लीना तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	143-144
नत्थियां	...	...	...	145-151

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 08 फरवरी, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-277

1.	अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत	
2.	अजय कुमार, डॉ0	इलाहाबाद	
3.	अजय कुमार लल्लू, श्री	कुशीनगर	
4.	अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री	सम्भल	
5.	अजीत पाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	
6.	अजीत पाल सिंह, श्री	कानपुर देहात	
7.	अतुल गर्ग, श्री	गाजियाबाद	
8.	अदिति सिंह, सुश्री	रायबरेली	
9.	अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज	
10.	अनिल पाराशर, श्री	अलीगढ़	
11.	अनिल सिंह, श्री	उन्नाव	
12.	अनीता, श्रीमती	अम्बेडकरनगर	
13.	अनीता लोधी राजपूत, डॉ0	बुलन्दशहर	
14.	अनूप प्रधान, श्री	अलीगढ़	
15.	अबरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर	
16.	अमर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	
17.	अमर सिंह चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर	
18.	अमिताभ बाजपेई, श्री	कानपुर नगर	
19.	अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री	लखनऊ	
20.	अरूण कुमार, डॉ0	बरेली	
21.	अर्चना पाण्डेय, श्रीमती	कन्नौज	
22.	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	खीरी	
23.	अविनाश त्रिवेदी, श्री	लखनऊ	
24.	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	
25.	असलम अली, श्री	हापुड़	
26.	आजाद अरिमर्दन, श्री	आजमगढ़	
27.	आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री	बलिया	
28.	आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती	प्रतापगढ़	
29.	आलमबदी, श्री	आजमगढ़	
30.	आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री	हरदोई	
31.	आशुतोष उपाध्याय, श्री	देवरिया	
32.	आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री	लखनऊ	
33.	इकबाल महमूद, श्री	सम्भल	
34.	इकराम कुरैशी, हाजी	मुरादाबाद	
35.	इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर	
36.	उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद	
37.	उदयभान सिंह, चौ0	आगरा	
38.	उपेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी	
39.	उमाशंकर सिंह, श्री	बलिया	
40.	ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	
41.	ओमकुमार, श्री	बिजनौर	
42.	ओम प्रकाश राजभर, श्री	गाजीपुर	

43. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
44. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
45. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
46. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
47. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
48. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
49. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
50. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
51. काली प्रसाद, श्री देवरिया
52. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
53. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
54. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
55. केसर सिंह, श्री बरेली
56. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
57. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
58. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
59. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
60. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
61. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
62. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
63. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
64. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
65. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
66. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
67. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
68. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
69. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
70. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
71. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
72. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
73. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
74. डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
75. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
76. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
77. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
78. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
79. दल बहादुर, श्री रायबरेली
80. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
81. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
82. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
83. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
84. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
85. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
86. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
87. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
88. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
89. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
90. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
91. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
92. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
93. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
94. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
95. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
96. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
97. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
98. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
99. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
100. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
101. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
102. नाहिद हसन, श्री शामली

103. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
104. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
105. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
106. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
107. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
108. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
109. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
110. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
111. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
112. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
113. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
114. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
115. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
116. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
117. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
118. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
119. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
120. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
121. फागू चौहान, श्री मऊ
122. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
123. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
124. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
125. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
126. बावन सिंह, श्री गोण्डा
127. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
128. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
129. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
130. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
131. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
132. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
133. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
134. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
135. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
136. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
137. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
138. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
139. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
140. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
141. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
142. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
143. महबूब अली, श्री अमरोहा
144. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
145. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
146. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
147. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
148. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
149. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
150. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
151. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
152. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
153. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
154. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
155. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
156. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
157. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
158. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
159. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
160. योगेश धामा, श्री बागपत
161. योगेश वर्मा, श्री खीरी
162. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
163. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर

164. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
165. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
166. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
167. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
168. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
169. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
170. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
171. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
172. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
173. राजबाला, श्रीमती रामपुर
174. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
175. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
176. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
177. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
178. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
179. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
180. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
181. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
182. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
183. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
184. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
185. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
186. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
187. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
188. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
189. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
190. राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
191. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
192. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
193. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
194. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
195. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
196. रितेश पाण्डेय, श्री आम्बेडकरनगर
197. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
198. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
199. लाखन सिंह, श्री औरैया
200. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
201. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
202. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
203. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
204. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
205. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
206. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
207. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
208. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
209. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
210. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
211. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
212. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
213. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
214. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
215. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
216. वीरेन्द्र, श्री एटा
217. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
218. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
219. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
220. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
221. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
222. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
223. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर

224. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
225. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
226. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
227. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
228. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
229. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
230. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
231. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
232. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
233. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
234. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
235. संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
236. संजय, श्री बुलन्दशहर
237. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
238. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
239. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
240. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
241. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
242. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
243. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
244. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
245. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
246. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
247. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
248. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
249. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
250. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
251. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
252. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
253. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
254. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
255. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
256. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
257. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
258. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
259. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
260. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
261. सुरेश राही, श्री सीतापुर
262. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
263. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
264. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
265. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
266. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
267. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
268. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
269. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
270. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
271. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
272. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
273. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
274. हरीराम, श्री सोनभद्र
275. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
276. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
277. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। कृपया हमें सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल जी, पहले आप प्रश्नकाल हो जाने दीजिये। उसके बाद अपनी बात कह लीजियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने सुनियोजित तरीके से पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का आरक्षण समाप्त कर दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगो के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में शुरू से है, जिसे खत्म किया जा रहा है। पिछड़ी जाति के लोगों को जो बाद में आरक्षण दिया गया है उसको भी सरकार द्वारा खत्म किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार तानाशाही पर उतर आई है। आप संविधान भिज्ञ और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और आपका हमें संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्नकाल हो जाने दीजिये, हम उसके बाद आपकी बात सुन लेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल जो बात कह रहे हैं, वह इन्हीं की सरकार के जमाने का किया हुआ है। एक शासनादेश वर्ष 2015 का श्री आलोक रंजन जी का है और दूसरा शासनादेश वर्ष 2016 का है। इनके द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरीके से मिथ्या और बेबुनियाद है। इनको यह बात कहने का अधिकार किसी भी तरीके से नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जिस शासनादेश की बात कर रहे हैं। उस समय केन्द्र में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, बल्कि वहां पर इनकी ही सरकार थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जितनी भी नौकरियां लगाई हैं सबमें आरक्षण का पूरे तरीके से पालन किया है। हमने शासनादेश को लागू नहीं किया है, बल्कि आपने इसे लागू किया है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया अभी आप बैठ जाईये और प्रश्नकाल होने दीजिये। अब हम अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 लेते हैं।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत मांग के सापेक्ष हो रहे बिजली उत्पादन एवं खरीदी जा रही बिजली के सम्बन्ध में

****1-श्री पारस नाथ यादव तथा श्री संजय गर्ग-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत मांग के सापेक्ष कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन वर्तमान समय में हो रहा है तथा कितने मेगावाट बिजली की खरीद की जा रही है ? क्या सरकार प्रदेश के किसानों को विद्युत सप्लाई समयबद्ध तरीके से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

जी हां।

वर्तमान में प्रतिदिन 11,000 से 14,500 मेगावाट विद्युत मांग के सापेक्ष विभिन्न स्रोतों से औसत उपलब्धता 14,250 मेगावाट है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-जलीय (जल निगम + विष्णु प्रयाग + अलकनन्दा) 450 मेगावाट,

2-तापीय 3800 मेगावाट,

3-आयात (केन्द्रीय विद्युत गृह) 4500 मेगावाट,

4-को-जनरेशन 900 मेगावाट,

5-रोजा तापीय 550 मेगावाट,

6-अनपरा-सी (लैन्को) 1050 मेगावाट,

7-बजाज इनर्जी 0.00 मेगावाट,

8-बारा 1200 मेगावाट,

9-ललितपुर 600 मेगावाट,

10-सोलर 400 मेगावाट,

11-एल0टी0ए0 एण्ड एम0टी0ओ0ए0 1300 मेगावाट,

12-शुद्ध उपलब्धता (1 से 11 तक) 14750 मेगावाट का योग,

13-द्विपक्षीय अनुबन्ध (-) 500 मेगावाट,

14-कुल उपलब्धता (12+13)

कुल योग 14250 मेगावाट।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 119051.44 मिलियन यूनिट तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह नवम्बर, 2018 तक समस्त ऊर्जा स्रोतों से कुल 82825.55 मिलियन यूनिट विद्युत क्रय की गई।

जी हां।

प्रदेश में किसानों के निजी एवं सरकारी नलकूपों में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु ''11 के0वी0 फीडर सेपरेशन'' का कार्य प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत स्वीकृत 39 जनपदों में कुल 1766 नग नये 11 के0वी0 फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है। दिनांक 25-01-2019 तक लक्षित 1766 नग फीडर निर्माण के सपेक्ष 1054 नग फीडरों का निर्माण किया जा चुका है। अवशेष 712 नग 11 के0वी0 फीडरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो माह मार्च, 2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष क्षेत्रों में फीडर सेपरेशन की योजना एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रस्तावित लोन से बना दी गई है जिसके अन्तर्गत 1678 नग नये 11 के0वी0 फीडरों का निर्माण ए0डी0बी0 द्वारा प्रस्तावित ऋण धनराशि रु0 4000.00 करोड़ की लागत से आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री श्रीकान्त शर्मा, ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत साफ था। माननीय मंत्री जी बहुत योग्य हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं। मेरा सवाल था कि प्रदेश की विद्युत मांग के सापेक्ष कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन वर्तमान समय में हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर बताया उसमें आयात को भी जोड़ा गया है। मेरा एक अनुपूरक प्रश्न यह है कि वर्ष 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के बाद दो साल में आपकी सरकार ने कितने मेगावाट का विद्युत उत्पादन शुरू किया है। हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने डिमाण्ड और सप्लाई के गैप को पूरा करते हुए निजी क्षेत्र में बारा, ललितपुर, श्रीनगर विद्युत परियोजनाओं से 4000 मेगावाट तथा राज्य सेक्टर की अनपरा-डी परियोजना से 1000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की थी। मेरा यह प्रश्न है कि उसके बाद हमारे योग्य माननीय मंत्री जी ने क्या एक मेगावाट भी बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का कार्य किया है अथवा नहीं किया है ? मेरा दूसरा प्रश्न इस बात के साथ है कि किसानों को जो बिजली सेप्रेशन में दी जा रही है। पहले वर्ष 2016-2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में किसान से नलकूप में प्रति हार्स पावर 100 रुपये फिक्स चार्ज और आवासीय मकान में 630 रुपये फिक्स चार्ज किया जाता था। मेरे सवाल की गम्भीरता तब और बढ़ जाती है जब

मेरे जनपद में छह महीने पहले अपने बिजली के बिल को सही करवाने के लिए लगातार चक्कर काटने के बाद बिजली के दफ्तर में सरसावा के सनौली गांव का एक किसान अपनी जान गवां देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से इस तरह की घटनायें प्रदेश में और भी जगह हुई होंगी और उसका कारण साफ है कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बिल कई गुना बढ़ा है। आपने 02 फरवरी, 2019 को डेढ़ सौ हार्स पावर का शासनादेश जारी कर दिया है जिसमें 100 की बजाय 150 हार्स पावर का चार्ज बढ़ा दिया गया है। यह अनावश्यक बोझ उस किसान पर पड़ा है जिसे पहले ही फसल का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसे पहले ही गन्ने का बकाया नहीं मिल पा रहा है। घर से मीटर की बिलिंग करने की जो व्यवस्था हुई है उसमें आई0डी0एफ0 के आधार पर वह संविदा कर्मचारी जिन्हें बिजली का बिल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई वह अनपढ़ किसान का उत्पीड़न करते हैं और उल्टे-सीधे कई-कई हजार के बिल उनके नाम पर बनाने का काम कर रहे हैं जिससे कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। उसमें भी आपने मिनिमम चार्ज को 840 रुपये करने का काम किया है। यह सब तब है जब आपकी सरकार किसानों की हितैषी बनती है और किसानों के लिए तमाम चीजें करने का दावा भी करती है। यह बात अलग है कि 36000 करोड़ के जिस लोन को दो साल में वापस करने का प्राविधान किया गया था, उसे आप अभी तक वापस नहीं कर पाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने पर विचार करेगी अथवा जो रेट बढ़ाया गया है क्या उसे कम करेगी। मेरा यह भी प्रश्न है कि किसानों का आई0डी0एफ0 के नाम पर जो उत्पीड़न हो रहा है क्या उसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री संजय जी हमारे बहुत काबिल मित्र हैं। प्रदेश में विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए जो पावर प्लाण्ट लगते हैं उनको चालू होने में पांच से छः साल की अवधि लगती है। अभी हमनें पनकी में 600 मेगावाट यूनिट की शुरुआत की है और वर्ष 2022 में यह आ जायेगी। 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट मेजा शुरू हो चुका है और यह एक शाश्वत प्रक्रिया है। सरकारें आती हैं और जाती हैं लेकिन प्रदेश के हित के लिए जो इन्सेन्टिव्स लिये जाते हैं वह लगातार रहते हैं। कुछ ऐसी यूनिट हैं जिनका उल्लेख माननीय संजय जी कर रहे थे। यदि माननीय सदस्य चाहें तो कौन सी यूनिट किस साल में आयेगी इसका मैं जिक्र कर सकता हूं।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी इसे बता दें तो अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि आपकी सरकार ने कौन-कौन से प्लाण्ट शुरू किये हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य दो चीजें पूछ रहे हैं। पहला तो यह कि हमने कितना उत्पादन शुरू किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि 500 मेगावाट की हमारी मेजा यूनिट आ चुकी है। जो आने वाली इकाइयां हैं तो उसमें मेजा की जो दूसरी इकाई है उसके अगस्त, 2019 तक आने की सम्भावना है। उसके बाद घाटमपुर की 660 मेगावाट की तीन इकाई हैं जिसकी एक इकाई नवम्बर, 2020 तक आने की सम्भावना है। दूसरी इकाई 02 मई, 2021 में आने की सम्भावना है और तीसरी इकाई भी 2021 में आने की सम्भावना है। तीसरी इकाई हरदुआगंज जो 660 मेगावाट की इकाई है वह सितम्बर, 2020 में आ जायेगी। ओबरा-सी की पहली इकाई जुलाई, 2021 में आ जायेगी और इसकी दूसरी इकाई नवम्बर, 2021 में आयेगी। जवाहरपुर की 660 मेगावाट की दो इकाइयां हैं, जिसमें पहली इकाई जुलाई, 2021 और दूसरी इकाई नवम्बर, 2021 में आ जायेगी। 660 मेगावाट की पनकी इकाई के 31 जनवरी, 2022 तक आने की सम्भावना है। माननीय संजय जी ने किसानों के बारे में बात की है तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार में किसी का उत्पीड़न नहीं है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और 150 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से उनको बिल दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय संजय जी को बताना चाहता हूं कि सरकार सरचार्ज माफी की योजना भी लेकर आई है, जिन किसानों पर बिजली का बिल बकाया है उनका सारा ब्याज सरकार ने माफ किया है। यह सरचार्ज योजना 15 फरवरी, 2019 तक लागू है। किसानों के मूल बिल का 30 प्रतिशत 15 फरवरी, 2019 से पहले जमा करा दीजिये और बाकी का जो बिल है वह 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं। माननीय संजय जी अनमीटर्ड के फिक्स चार्ज का उल्लेख कर रहे थे। हमने आप सबके सहयोग से 100 प्रतिशत मीटरिंग की व्यवस्था की है। जो अनमीटर्ड हैं वह अपने घरों में मीटर लगवा लें तो उन्हें फिक्स चार्ज से मुक्ति मिलेगी। किसी का उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा कि बिल में पहले के जो 100 यूनिट हैं उन पर सरकार बिल के रूप में 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल ले रही है। सरकार की तरफ से उपभोक्ता के हित के लिए व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। अगर कहीं संजय जी के माध्यम से, विपक्ष के हमारे मित्रों के माध्यम से या फिर हमारे सत्तापक्ष के मित्रों के माध्यम से कोई त्रुटि है, कमी है या उत्पीड़न है तो यदि आप उसकी जानकारी हमें दे देंगे तो हम उसमें कार्यवाही करायेंगे। उत्पीड़न इस सरकार में किसी का नहीं है और बिना किसी भेदभाव के सबको बिजली उपलब्ध कराने की हमारी मंशा है। हम चाहेंगे कि उसमें आप सब लोग हमारा सहयोग करें और अगर कहीं पर कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसका उल्लेख करें हम उसे दूर करायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने यह कहा कि किसानों के निजी और सरकारी नलकूपों में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने हेतु 11 केवीए फीडर सेपरेशन किया जा रहा है। मतलब कि 11 केवीए का सेपरेशन है। सब-स्टेशन जो 33000/11 का है वह एक ही है। जब उस सब-स्टेशन पर ही बिजली नहीं रहेगी मान्यवर जो कटौती के तहत वह ग्रामीण क्षेत्रों में है। जब उस पर ही नहीं रहेगी तो कैसे अलग से सेपरेशन करने के बाद भी किसान को कैसे मिल जाएगी। इस पर मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसानों के लिए अलग से सब-स्टेशन बनाकर जिससे केवल निजी नलकूपों को इस सेपरेशन लाइन से जोड़ने का कोई विचार मा0 मंत्री जी के संज्ञान में है। मा0 मंत्री जी करना चाहते हैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

हाजी इरफान सोलंकी-

अध्यक्ष जी, एक सवाल पूछना है मंत्री जी से जो यह पनकी और घाटमपुर का आपने जिक्र किया। वह हमारे नेता मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश जी ने स्थापित कराई थी, कानपुर के वरिष्ठ मंत्री महाना जी को मालूम होगा, उसमें इन्होंने क्या बढ़ोत्तरी की है। दूसरा, जो पनकी का आपने जिक्र किया पेज 22 में तो पनकी तो पहले से बिजली देता है, उसमें कौन सा नया काम, दो नाम तो लिए पर बताया नहीं कि आप करने क्या जा रहे हैं ?

श्री संजय गर्ग-

मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है कि मा0 मंत्री जी ने कहा 1 लाख 19 हजार 51.44 मिलियन यूनिट 2017-18 में आपने क्रय की और 82 हजार 8 सौ 25.55 यूनिट 18-19 नवम्बर माह में क्रय की। डिमाण्ड और सप्लाई की गैप आबादी के बढ़ने के साथ लगातार बढ़ रहा है। जो आपने 14 हजार 250 मेगावाट का उत्पादन दिखाया यह कितना यूनिट उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है। बहुत साफगोई के साथ एक तो कैटेगेरली यह पूछना चाहता हूं। दूसरा एक सवाल मेरा इस बात के साथ है कि कौन सा नया प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन के लिए आपके द्वारा शुरू किया गया। मैं केवल उस योजना के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि यह डिमाण्ड और गैप की सप्लाई हो सकती है सेण्ट्रल पूल से इसमें आप क्रय कर रहे हो और वह आपको सस्ती पड़ रही हो, परन्तु सेण्ट्रल पूल से किस समय कीमत ज्यादा हो प्रदेश की निर्भरता और आपकी निर्भरता के आधार पर यह स्वाभाविक है कि डिमाण्ड और सप्लाई के गैप को कम से कम किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से मा0 अखिलेश यादव की तारीफ करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा विद्युत के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो बाद वाली सूचना है, प्रश्न नहीं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

अभी जो मा0 वर्मा जी ने कहा है श्रीमन् जो मीटर हमारे फीडर सेपरेट हो गए हैं वहां किसानों को निर्बाध दस घण्टे बिजली देने की हमारी व्यवस्था है और जो वितरण का जिक्र कर रहे हैं उसमें सरकार इस बात की चिन्ता कर रही है कि रोस्टर के अनुसार स्थित केन्द्र पर बिजली उपलब्ध रहे। दूसरा संजय जी का मैंने बहुत विस्तार से जवाब दे दिया है और संजय जी उसको थोड़ा पहले डिसाईड करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री संजय गर्ग-

आपने अपनी योजनाओं के बारे में जिक्र किया था कि फाइव ईयर प्लान में आती हैं तो वह कब पूरी होंगी पांच साल में या दस साल में या बीस साल में। आपने कौन सी नई योजना शुरू की या नहीं की।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने पूरा विवरण पढ़ दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमने यह पूछा था कि क्या किसानों को निर्बाध गति से बिजली देने के लिए जो आप सेपरेशन लाइन बना रहे हैं तो क्या उसके लिए सब-स्टेशन भी अलग से बनाएंगे ?

श्री अध्यक्ष-

हालांकि इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, उत्तर नहीं दिया है, हम लोगों ने नहीं सुना है। अभी दो विषय थे। किसानों वाला मामला वर्मा जी का था और मा0 संजय गर्ग जी का मामला यह था और वे यह कहना चाहते थे कि जब से यह सरकार आई है तब से क्या सरकार ने बिजली पैदा करने के लिए अपना कोई नया विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट लगाया है कि नहीं लगाया है ? क्योंकि ये हर जगह कहते हैं कि हम 24 घण्टे इतनी बिजली दे रहे हैं। मामा के घर का पुआ सबको ठीक लगता है। मा0 अखिलेश यादव जी ने बिजली व्यवस्था ठीक की थी और ये कह रहे हैं कि हम इतनी बिजली दे रहे हैं, उतनी बिजली दे रहे हैं। कभी यह नहीं कहते कि पिछली सरकार के कारण बिजली दे रहे हैं। मा0 सदस्य का स्पष्ट प्रश्न था कि वर्तमान सरकार जब से आई है तब से क्या उसने कोई भी नया विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट लगाया है जिससे बिजली की एक भी यूनिट पैदा हो सके।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बहुत विस्तार से सभी सवालों का जवाब दिया है। मा0 नेता प्रतिपक्ष बहुत वरिष्ठ हैं, मैं इनको भी एक बार पुनः बताना चाहता हूं। आदरणीय वर्मा जी का

जवाब मैं दे चुका हूं कि जो रोस्टर है उसके अनुसार उप केन्द्रों पर बिजली उपलब्ध रहेगी। हमने जो फीडर किसानों के लिए सेपरेट किए हैं, वे इसलिए किए हैं ताकि उनको निर्बाध रूप से 10 घण्टे बिजली मिलती रहे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनको बिजली मिलती रहे। रात को ठिठुरने की जरूरत किसी को नहीं है। पहले पता नहीं होता था कि बिजली कब आएगी और कब जाएगी ? मा0 अध्यक्ष जी, अब उसका रोस्टर तय हो गया है। नम्बर दो, ये अपनी पीठ बहुत थपथपा रहे हैं कि हमने इतने बिजली के उत्पादन केन्द्र स्थापित किए लेकिन सरकार प्रदेश की जनता की होती है। यदि आपने उपकेन्द्र, जेनरेशन के प्लाण्ट लगाए तो आपने जनता पर कोई रहमोकरम नहीं किया। यह आपका दायित्व बनता था कि आप वह करें। यह हमारा प्रबन्धन है, हमारी सरकार की यह प्रबन्धन कुशलता है कि आज गांव में 18 घण्टे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। यह हमारा प्रबन्धन है कि जिले में 24 घण्टे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। यह हमारा प्रबन्धन है कि तहसील में 20 घण्टे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये लोग केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ये लोग पावर प्लाण्ट्स के अन्दर फायर सुरक्षा के उपकरण तक नहीं लगा पाए।

(हाजी इरफान सोलंकी द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक ही सवाल पर 25 मिनट हो गया है। मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, ये जानकारी कराएं कि घाटमपुर और पनकी की पावर यूनिट किसने लगवाई थी ? ये सबको गुमराह कर रहे हैं, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। घाटमपुर और पनकी के प्रोजेक्ट अखिलेश यादव जी ने लगवाए थे। इनको मालूम ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, अब अगला प्रश्न होगा।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में किसानों के ऊपर निजी नलकूपों के बकाया बिलों की धनराशि को वसूलने/जमा कराने के लिये की जा रही एफ0आई0आर0 को बन्द कराने के सम्बन्ध में

***1-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में किसानों के ऊपर निजी नलकूपों के बकाया बिलों की धनराशि को वसूलने/जमा कराने के लिये पुलिस में की जा

रही एफ0आई0आर0/प्रथम सूचना रिपोर्ट को बन्द कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की धनराशि की वसूली के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्युत अधिनियम, 2003 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 उन्हीं मामलों में दर्ज कराई जाती है जहां विद्युत चोरी का मामला प्रकाश में आये अथवा विद्युत संयोजन के विच्छेदन के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा बिना धनराशि का भुगतान किये अनाधिकृत रूप से अपने संयोजन को जोड़ लिया जाना प्रकाश में आये। विद्युत चोरी के मामलों में छापे के दौरान पारदर्शिता के उद्देश्य से वीडियो रिकार्डिंग भी करने के निर्देश हैं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 ने निजी नलकूपों तथा छोटे घरेलू व व्यावसायिक की श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की धनराशि में राहत देने के लिये सरचार्ज समाधान योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता लाभ उठा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, जो लिखित उत्तर है उसके अलावा मुझे सदन को अवगत कराना है कि लगभग 14 लाख उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 2 लाख 50 हजार पी0टी0डब्लू0 यानि की किसानों ने इस योजना का लाभ लिया है। दो किलोवाट के जो कनेक्शन हैं चाहे वह शहर के हैं, चाहे वह गांव के हैं, चाहे वह व्यावसायिक हैं उनमें सरचार्ज माफी है। उनका जितना भी सरचार्ज है वह सब सरकार की तरफ से माफ किया गया है। वहीं किसानों का भी सरकार ने सरचार्ज माफ किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दिलायें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि नियमानुसार निजी नलकूप पर एफ0आई0आर0 नहीं होनी चाहिए लेकिन धरातल की स्थिति यह है कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वह अपने रिकार्ड में तो कनेक्शन कटा हुआ दिखा देते हैं और बाद में जाकर उसका वीडियो बनाकर उस पर चोरी की एफ0आई0आर0 कर देते हैं। इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से घरों में जो मीटर लगाये जा रहे हैं वहां पर जैसे बिजली कर्मचारी मीटर लगाकर गये और यह कहा कि दो दिन में मीटर का कनेक्शन कर दिया जायेगा। मैं अपने जनपद सिकन्दराबाद की बात करना चाहती हूं कि वहां ककोण के जो जे0ई0 हैं वह

जाकर उन मीटरों की और उन तारों की वीडियोग्राफी करते हैं और एफ0आई0आर0 करवा देते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान से बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप एक महिला विधायक को सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कृपया शान्त रहिए।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब इसकी शिकायत वहां के एम0डी0 से की जाती है तो वह एम0डी0 सीधे-सीधे हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि शैलेन्द्र शर्मा यूनियन का अध्यक्ष है। मैं माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में शिकायत दे चुकी हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए क्या आप कार्रवाई करेंगे ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, किसी एक कर्मचारी के सरकार की मंशा के अनुसार काम न करने के कारण इस तरह का मामला प्रकाश में आया है, निश्चित रूप से इसे हम गम्भीरता से लेंगे। ऐसे जितने भी लोग हैं और जहां-जहां भी शिकायतें मिलेंगी उसमें सरकार कठोरता से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

प्रदेश में वर्ष 2018 में निरस्त राशन कार्ड को पुनः बहाल कर राशन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***2-श्री शैलेन्द्र यादव ललई तथा श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018 में कितने राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं ? क्या सरकार निरस्त किये गये राशन कार्ड धारकों के कार्ड बहाल कर राशन उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, बांट-माप राज्य मंत्री (श्री अतुल गर्ग)-

वर्ष 2018 में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक कुल 4388515 राशन कार्ड निरस्त किये गये।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु अधिसूचना संख्या-3121/29-6-2014-104सा/09, टी0सी0-10, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में एक्सक्लूजन व इन्क्लूजन क्राइटेरिया की व्यवस्था के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करते हुए राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं, जिसका समय-समय पर सत्यापन किया जाता है।

सत्यापन में पात्रता-अपात्रता के मापदण्ड पर कोई व्यक्ति पात्र पाया जाता है तो उसको पात्रता सूची में सम्मिलित करने तथा अपात्र को पात्रता सूची से कार्ड निरस्त करते हुए बाहर करने की कार्रवाई की जाती है।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूं। उसके बाद संजय गर्ग जी का जो सवाल है उस पर गौर करियेगा। पहला मा0 अध्यक्ष जी, बड़ी संख्या में गांव के जो पात्र व्यक्ति हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, दलित, पिछड़े व शोषित समाज के लोग हैं। गांव के दबंग और प्रभावशाली लोग राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से पात्रता सूची में पात्र होने के बावजूद उनके नाम कटवा दे रहे हैं। बड़ी संख्या में शिकायतें हम लोगों को रोज अपने क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदार अधिकारियों को लगा करके विशेष अभियान चला करके क्या इस बात को दिखवाने का काम करेंगे कि जिन पात्र लोगों के नाम अपात्र बताकर काट दिये गये हैं उनको दुबारा सूची में लाने का काम करेंगे और जिन लोगों ने जानबूझकर ये गड़बड़ियां की हैं क्या उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने का काम करेंगे ? मा0 अध्यक्ष जी कियोस्क मशीन के जरिये राशन का वितरण हो रहा है। बहुत से गरीब आज भी जानते हैं, गांव से हम भी हैं। गांव के गरीब लोग, जो परिवार के मुखिया हैं वह अपनी कमाई के लिए महानगरों की तरफ चले जाते हैं। घर में उनके न होने के कारण उनका अंगूठा लग नहीं पाता जिसके कारण उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग राशन नहीं पाते हैं और उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग हैं, उनके अंगूठे उस मशीन में फिट नहीं बैठते जिसके कारण उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार इसका सरलीकरण करने का काम करेगी ? जैसे यदि कोई मुखिया नहीं है तो भी उसके परिवार का कोई सदस्य जाकर अपने हक का राशन ले सके। ये दोनों सवाल मा0 मंत्री जी से मैं करना चाहता हूं।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, 43,88,515 राशन कार्ड निरस्त किये गये। मेरा केवल यह सवाल है मा0 शैलेन्द्र जी ने जो सवाल किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए कि पात्र गृहस्थियों के चयन के आधार पर इस समय दो तरह के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अन्त्योदय के आधार पर बने हुए हैं। आपने कहा कि बार-बार उसका सत्यापन करा लें। इसी अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि प्रदेश स्तर, जिला स्तर और नगरीय स्तर पर इसमें सतर्कता कमेटियां बनायी जायेंगी। मेरा एक सवाल है कि क्या 75 के 75 जनपदों में सतर्कता कमेटियां बनी हैं या नहीं बनी हैं ? दूसरी बात चूंकि राशन कार्ड गृहस्थी महिला मुखिया के नाम है। पूरे उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश की जो सतर्कता कमेटी 11 सदस्यों की है उसमें एक भी महिला नहीं है। क्या उसमें किसी महिला को रखने पर सरकार विचार करेगी अथवा नहीं

करेगी ? जनपद और नगरीय स्तरों में भी जो सत्यापन कमेटी न होने के कारण यह अव्यस्था फैल रही है। अभी 19 जिलों का इपॉक्स मशीन में गैर जरूरी इस्तेमाल करके सुनियोजित ढंग से 19 जिलों में पी0डी0एस0 का घोटाला पिछले दिनों पकड़ा गया। उस पी0डी0एस0 के घोटाले में, जैसा कि मा0 शैलेन्द्र जी ने कहा यह समाज के सबसे आखिरी श्रेणी के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में व्यवस्था करने की बात कही गयी है। उन लोगों के लिए जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। जिनके रूरल एक्सपर्ट भी कई बार उनसे इम्प्रेशन नहीं ले पाते, जिनकी हथेलियां मजदूरी करते-करते घिस जाती हैं, निश्चित रूप से इपॉक्स कमेटी में भी वो चीजें नहीं आ पातीं तो क्या इसका सरलीकरण करने की आवश्यकता सरकार महसूस करेगी ? एक और सवाल मेरे जनपद के सम्बन्ध में है, मेरे जनपद में है तो मैं समझता हूं कि और जनपदों में भी होगा। मैं पिछले सत्र में इस सवाल को नहीं उठा सका पर मैंने जनपदीय स्तर पर शिकायत की, मा0 मंत्री जी को भी कहा कि सत्यापन हुआ है। परन्तु अभी भी हमारे जनपद में इस तरह के राशन कार्ड होल्डर लोग पात्र हैं जिसमें गृहस्थी मुखिया का नाम हिन्दू हैं और बाकी मेम्बर मुसलमान हैं या गृहस्थी मुखिया का नाम मुसलमान है और बाकी मेम्बर हिन्दू है। अगर कोई भी नेट पर जाकर देख ले तो उसे निरस्त करने का काम कर सकता है और सबसे शर्मनाक बात तो तब थी जब 6 महीने पहले तक हमारे यहां सहारनपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम का भी राशन कार्ड बना हुआ था। ऐसी स्थिति में किस तरह से राशन कार्ड होल्डर, किस तरह से इपॉक्स मशीन का बहाना लेकर सरकार को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इस बारे में सरकार क्या कोई प्रभावी योजना बनाने पर विचार करेगी ?

श्री अतुल गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधान सभा सदस्य ने जिस मार्मिकता से इस विषय को पेश किया तो मेरे तो आंखों में आंसू आते-आते रह गये। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। एक करोड़ 70 लाख लोगों के, जो अपात्र थे, जिनकी मृत्यु हो गयी थी, जो विस्थापित हो चुके थे, ऐसे लोगों के राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करके, आधार कार्ड एक ऐसी आइडेंटिटी है जो प्रमाणित मानी जाती है, उनको हटाकर 2 करोड़ लोगों से ज्यादा के नये राशन कार्ड इस योगी सरकार ने बनवाये हैं। इन दो करोड़ लोगों पर इन्हें पहले तरस नहीं आया। पहले भी मैंने यह सवाल किया कि कभी-कभी अपने जमीर से यह तो पूछो कि यह डेढ़ करोड़ लोगों के राशन कार्ड, जो नकली थे, जो कटे, वह राशन कार्डों का राशन जा कहां रहा था। मान्यवर, वह व्यवस्था हमने की और मैंने पहले भी कहा अपने विधान सभा सदस्यों से कि जब हम विधान सभा में होते हैं तभी हम विधान सभा सदस्य होते हैं क्या हम बाकी 365 दिन विधान सभा सदस्य नहीं होते हैं। क्या इन्होंने किसी ने 10-5 ऐसे उदाहरण हमको दिये कि इसे ठीक करा दो और हमने ठीक न कराये हों। ऐसे विषय भी सामने यहां आप रखिये। अगर इस तरह आधारहीन बातें होंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि अंगूठा नहीं मिलता। अरे साहब 90 प्रतिशत लोगों के अंगूठे मिल रहे हैं।

(विपक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर-व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिये, ऑन रिकार्ड है। वरना रिकार्ड आप लाइये अन्यथा मैं देता हूं। 90 प्रतिशत लोगों के अंगूठे मिल रहे हैं और उसके ऊपर भी सरकार ने राइटिंग में पोर्टल पर यह दिया है कि अंगूठा मिलना कोई जरूरी नहीं है, यदि अंगूठा मैच नहीं करता है तो कोई भी प्रमाण-पत्र किसी भी तरह का दिखा करके, अब तो हमने राशन कार्ड भी बंटवा दिये हैं, वह अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना आइडेन्टिटी कार्ड दे सकते हैं, अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, किसी भी तरीके से यह वह कह सकते हैं कि हां मैं वही हूं, तो किसी को भी बिना अंगूठा मिले राशन हम लोग दे रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

यह तो प्रसन्नता की बात है कि एक मंत्री ऐसे हैं जो गरीबों के लिये आंसू बहा रहे हैं और हाउस में भी बहा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। हमारे जनपद में राजभर जाति है। हम जानते हैं कि वह 99 प्रतिशत गरीब हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक मनियर, बांसडीह विधान सभा क्षेत्र का गांव चेकऊर, अभी हाल में पूरे राजभर बस्ती का लाल कार्ड वहां काट दिया गया और कौन काटा, विधायक मैं वहां का हूं। कैसे हुआ, यह गरीब लोग हैं, आप इसका सर्वे कराइये। मेरा आपसे यही कहना है कि एस0डी0एम0 के यहां हमने गांव के लोगों को कई बार भेजा, महिला एस0डी0एम0 हैं हमारे लोगों ने उनसे कहा, मैनें भी एक दिन कहा। लेकिन आज तक ऐसा इसलिये हो रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ दबाव में कार्ड नहीं बनने दिया जाता है। तो आप इसे दिखवा लें। यह कार्ड कोई गड़बड़ी से नहीं कटे हैं वह एकदम गरीब लोग हैं तो चेकऊर गांव, ब्लाक मनियर, विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के कटे हुये राशन कार्डों को आप पुनः बहाल करवा दीजिये, यही मेरा आपसे कहना है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, माननीय मंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से कह दिया कि माननीय सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं और मैं इन्हें उसके प्रूफ ला कर दे दूंगा कि जहां पर मुसलमान मुखिया और हिन्दू सदस्य और हिन्दू मुखिया महिला और मुस्लिम सदस्य, तो इस बात की जांच के लिए हमने पहले कहा, तो भी 30 परसेण्ट कटे और 40 परसेण्ट अभी भी पोर्टल में मौजूद हैं और सहारनपुर के पोर्टल को माननीय मंत्री जी स्वयं चेक करा लें। अगर 700-800 राशन कार्ड ऐसे न मिलें तो निश्चित रूप से इस बात को कहने का आप दावा कर सकते हैं। परन्तु अनावश्यक रूप से इस तरह का आरोप लगाना, हम कभी भी सदन में रहते हुए मर्यादित रूप में यह बात नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हम कोई गलत बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपने गलत बात नहीं कही, आपने प्रश्न पूछा है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, दूसरी बात हमने यह पूछने की कोशिश की कि प्रदेश की सतर्कता कमेटी में एक भी महिला सदस्य नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में महिला गृहस्थियों के नाम से राशन कार्ड पूरे उत्तर प्रदेश में हैं तो क्या जिला सतर्कता कमेटी, नगरीय सतर्कता कमेटी और प्रदेश सतर्कता कमेटी में किसी महिला सदस्य के होने पर क्या सरकार विचार करेगी, इसका कोई जवाब नहीं मिला।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र वाला।

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, ऐसा है कि आपके लिए पूरे सदन में बहुत श्रद्धा का भाव रहता है और दो-तीन दिन पहले मुझे पता चला कि आप जे0पी0 आन्दोलन से जुड़े हुऐ हैं तो मेरा मन बहुत गदगद हुआ (सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)। मैंने कहा कि जो लड़ाई आपने और हमने एक साथ लड़ी थी, उसका नेता मेरे सामने प्रतिपक्ष के रूप में बैठा है, पर हमारा नेता रहा है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अतुल गर्ग-

सर, मेरी बात सुन लीजिए और मैं बहुत जूनियर सदस्य हूं, इस तरह की कोई भी बात तो मेरे घर आना आपके लिए शान के खिलाफ है, लेकिन मैं आपके घर जाऊं यह मेरे लिए शान की बात है। आप मुझे अपने घर बुलाइये, मैं आपके गांव में आऊंगा, तारीख भी आप तय कर दीजिए, जगह भी आप तय कर दीजिए, वहां मैं आपके सामने आ जाऊंगा। (सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर प्रश्न पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप देखिये, दो ही प्रश्नों में एक घण्टा हो गया है, अब आप बैठिये। प्रश्न संख्या-3 लेते हैं। यह माननीय लाल जी वर्मा जी का प्रश्न है। एक ही सवाल लम्बा नहीं चलेगा।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर प्रश्न पूछने का प्रयास करते रहने पर)

आप सब बैठिये, इस प्रश्न पर एक घण्टा हो गया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्री जी के घर जाने वाले हैं, यह उत्सव की बात है कि नहीं है ? (हंसी)

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, क्या महिला सदस्यों के मनोनयन पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

अब जब वह वहां जायेंगे तो सारी बातें हो जायेंगी। (हंसी)

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, हमारे प्रश्न का जवाब आने दें।

श्री अध्यक्ष-

अब हमने अगले प्रश्न के लिए बुला लिया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, एक छोटा सा मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी, आप बैठिये। आप पूछ लेना, आप सीनियर आदमी हैं, आप मंत्री रहे हैं।

प्रदेश में सीमान्त एवं लघु किसानों को 5 हार्स पावर तक नलकूप हेतु निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने विषयक

***3-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीमान्त एवं लघु किसानों को 5 हार्स पावर तक नलकूप हेतु बिजली कनेक्शन लेने पर 300 मीटर तक की विद्युत लाइन निःशुल्क देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

निजी नलकूप के विद्युत संयोजन के लिये आवेदन प्राप्त होने पर प्राक्कलन बनाया जाता है, जिसमें कृषकों को 7.5 हार्स पावर तक रु0 68,000.00 की अधिकतम अनुदान राशि की छूट प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय अध्यक्ष जी, निजी नलकूप के विद्युत संयोजन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्राक्कलन बनाया जाता है, जिसमें किसानों को 7.5 हार्स पावर तक सरकार की तरफ से 68,000 की अधिकतम छूट प्रदान की जा रही है। माननीय सदस्य ने केवल 300 मीटर तक की बात कही है, यह सरकार तो जो भी पी0टू0डब्ल्यू0, जो किसान कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, उन सबको जो 7.5 हार्स पावर तक का कनेक्शन लेना चाहते हैं। उन सबको सरकार की तरफ से 68,000 का अनुदान यानि छूट दी जा रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया था कि क्या माननीय मंत्री जी लघु किसानों और सीमान्त किसानों को, लघु किसान का मतलब 5 एकड़ और सीमान्त किसान का

मतलब ढाई एकड़, इनसे केवल 300 मीटर की दूरी का अगर कनेक्शन है तो उसको पहले की भांति, जैसे पहले होता था, निःशुल्क 300 मीटर तक का निजी नलकूप का कनेक्शन दिया जाता था, तो उस पर इन्होंने कहा 68,000 तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, यह सरकार किसान की हितैषी होने की बात बार-बार करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 300 मीटर अगर निजी नलकूप के लिए विद्युत लाइन देना है तो उसका प्राक्कलन कितना होता है, नम्बर एक और क्या वह प्राक्कलन इस 68,000 के बराबर है कि इससे कई गुना ज्यादा है, क्या उस निजी नलकूप, जो ढाई एकड़ वाला किसान है या 5 एकड़ का किसान है, उस प्राक्कलन के अनुसार धन जमा करने की उसकी हैसियत है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। 300 मीटर का प्राक्कलन क्या है, पहले यही बता दें, फिर मैं दूसरा प्रश्न कर लूंगा।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा विधान सभा क्षेत्र अजगरा भी सम्पूर्ण रूप से किसान बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे यहां भी बहुत बड़ी यह समस्या है कि जो पहले से नलकूप के कनेक्शन किसानों को दिये गये थे वह कनेक्शन अब काट करके, क्योंकि उसको घरेलू घोषित कर दिया गया है, जो कि 100 मीटर तार से ही उनके यहां कनेक्शन है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप अपने विधान सभा क्षेत्र का पूरा विवरण लिख करके मा0 मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जो कनेक्शन पहले से लगे हुए थे उसको काट करके अब उसको अलग कर दिया गया है और उसके फिर से दो-दो लाख तक के इस्टीमेट बनाये गये हैं जबकि जो किसान पहले से आच्छादित थे उनको फ्री में कनेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि दोबारा इस्टीमेट बना करके दो-दो, ढाई-ढाई लाख के इस्टीमेट बन रहे हैं जिसमें 68 हजार की सब्सिडी के बावजूद वह लोग कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ही परेशान हैं। कम से कम सैकड़ों किसान इस तरह से हमसे शिकायत कर रहे हैं। मैंने एक साल पहले भी पत्र लिखा है लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख करके मंत्री जी को दे दीजिएगा, इस प्रश्न से आपका प्रश्न नहीं जुड़ा हुआ है। मा0 मंत्री जी, आप मा0 वर्मा जी के प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार किसानों की हितैषी सरकार है यह जो मैं आंकड़े देने वाला हूं यह इस बात को प्रमाणित करने वाले हैं। हमारी सरकार ने जो डार्क जोन के नाम पर

किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिये जाते थे उन डार्क जोन को हमने खोलकर प्रदेश के सभी किसानों को कनेक्शन देने का काम किया है। दूसरा, पूर्व का अगर हम जिक्र करें तो केवल 19 हजार किसानों को ही कनेक्शन दिये गये थे यह उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली सरकार है जिसने 50 हजार से ज्यादा प्रतिवर्ष किसानों को कनेक्शन देने का काम किया है। जो मा0 सदस्य का सवाल है 300 मीटर का इस्टीमेट लगभग 88000 का आता है और हमने इसमें सभी को जो 300 मीटर के आगे वाले भी किसान हैं उनको भी मदद देने की हमारी सरकार ने मंशा रखी है कि कोई भी किसान जो कृषि उपयोग के लिए कनेक्शन लेना चाहता है उन सभी किसानों को 68 हजार रुपए की छूट सरकार की ओर से दी जा रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि 300 मीटर का केवल 88000 हजार का इस्टीमेट आता है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अगर 300 मीटर का या इससे अधिक का कहीं इस्टीमेट बनता है तो क्या उस इंजीनियर के खिलाफ मा0 मंत्री जी कार्रवाई करने का विचार करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 300 मीटर का लगभग दो लाख रुपए का इस्टीमेट बनता है और जो सीमान्त या लघु किसान हैं जिसके पास ढाई एकड़ जमीन है अगर वह अपनी सम्पूर्ण फसल जितना उसके पास उत्पादन होता हो वह बेच दे तो भी वह इस कास्ट को जमा करने की हैसियत नहीं रखता है तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए सीमान्त और लघु किसानों को, अगर 88000 तक का इस्टीमेट बनता है तो 68 हजार छूट के बाद उसे बहुत कम देना पड़ेगा और उतना देने के लिए वह सक्षम है हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 2 लाख का इस्टीमेट बनता है और 68 हजार के बाद भी उसको सवा लाख रुपया अलग से देना पड़ता है और वह अपनी सारी फसल बेचने के बाद भी सवा लाख रुपया देने की क्षमता नहीं रखता है तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर 88 हजार से ज्यादा का इस्टीमेट आता है तो क्या उस पर कार्रवाई करने पर विचार करेंगे और दूसरा यह कि अगर दो लाख का इस्टीमेट आता है तो क्या केवल लघु और सीमान्त किसान को, जिसका सम्पूर्ण उत्पादन उसके बराबर नहीं होता है तो क्या उनको 300 मीटर तक फ्री कनेक्शन देने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

68 हजार रुपए की तो छूट दे रहे हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में लम्बे समय तक सपा-बसपा की सरकारें रही हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कल कहा था कि बैठे-बैठे कोई कमेंट्री नहीं करेगा, लेकिन उनके पीछे जो लोग बैठे हैं, वह लगातार कमेंट्री कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। आपको हमने बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में 15 साल तक, लम्बे समय तक सपा-बसपा की सरकारें रही हैं और कांग्रेस पार्टी भी उनको समर्थन करती थी। यह सरकार बीमारियों से ग्रस्त थी, क्योंकि सपा-बसपा की सरकारों में बीमारी जल्दी घुसती थी और उसी के कारण उत्पीड़न करने वाली बीमारी कर्मचारियों में भी घुस गयी। इस बीमारी को धीर-धीरे हम ठीक कर रहे हैं। मा0 वर्मा जी ने कहा है कि अगर 300 मीटर तक रु0 88,000/- का जो हमारा प्राक्कलन है, अगर उसके ऊपर किसी ने इस्टीमेट बनाया है तो मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, अब आपकी पूरी बात आ गयी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर 300 मीटर के इस्टीमेट में 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगता है, तो केवल ट्रांसफार्मर की ही उतनी लागत आ जायेगी। मा0 मंत्री जी ट्रांसफार्मर को शामिल करते हुए यह निर्धारित/निश्चित (फिक्स) कर दें कि 300 मीटर दूरी तक का इस्टीमेट रु0 88000/- से अधिक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

चन्देल जी क्या आप प्रश्न करेंगे ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मा0 अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जब से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुख्य मंत्री हुए थे, तबसे रु0 160/- प्रति हार्स पावर किसानों से लिया जाता था, इस सरकार ने पूरे प्रदेश के किसानों के लिए रु0 100/- प्रति हार्स पावर समान विचार धारा में लागू किया।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न कहां है ? मा0 ऊर्जा मंत्री जी उत्तर दे रहे है या आप दे रहे हैं। यह प्रश्नकाल है आप बैठ जाइये। आप कल भी ऐसा कर रहे थे। मा0 मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का बार-बार जवाब आ रहा है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि

सदन को अवगत करा दें कि धनराशि रु0 68,000/- की छूट कबसे मिल रही है और इनकी सरकार आने के बाद कितने रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। दूसरा सवाल यह है कि अगर रु0 88,000/- से ऊपर का इस्टीमेट बनता है तो रु0 88,000/- के बाद जो धनराशि होगी, उस पर सरकार अनुदान देने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मा0 अध्यक्ष जी, जिन किसानों के कनेक्शन काट दिये गये हैं और पुनः उनको इस्टीमेट बनाकर दिये हैं, उनको निःशुल्क कनेक्शन दिये जायेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इस पर कह चुके हैं, अब आप बैठ जाइये।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने मा0 सदस्य के विषय का संज्ञान लिया है। निश्चित रूप से उस पर हम लोग गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी पूछता हूं कि क्या सरकार ट्रांसफार्मर सहित 300 मीटर दूरी तक रु0 88,000/- के इस्टीमेट पर कनेक्शन देना सुनिश्चित करेगी।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से इसका जवाब दिया है। किसान, किसान होता है चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। उसको रु0 68,000/- की छूट का प्रावधान सरकार की तरफ से है। वर्मा जी ने कहा कि अधिकारियों के द्वारा गलत इस्टीमेट बनाया जा रहा है। मैंने उस पर कहा कि अगर आप मुझे कोई कॉपी उपलब्ध करा दें, जहां 300 मीटर पर गलत इस्टीमेट किसी ने बनाया है, तो कठोर कार्रवाई सरकार उस अधिकारी के खिलाफ करेगी।

प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवारों के हितार्थ प्रचलित समस्त योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु विशेष अभियान चलाने के सम्बन्ध में

***4-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत श्रमिक परिवारों को लाभान्वित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोई विशेष अभियान सरकार चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य खन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर विशेष कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाता है। उक्त के साथ-साथ जनपदों में कैम्पों का आयोजन करके श्रमिकों के पंजीयन एवं हितलाभ का सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जवाब दिया है कि 'उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर विशेष कैम्पों का आयोजन किया जाता है।' मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि बीते दो वर्षों में जिलेवार कितने पंजीकरण कैम्प लगाये गये तथा कितने नये पंजीकरण कराये गये ? चूंकि खासतौर पर मेरी विधान सभा क्षेत्र बिलारी में बुनकर समाज, अल्पसंख्यक, अति-पिछड़े और श्रमिक बहुतायत में हैं और मेरे यहां बुनकर समाज से मुतालिक बहुत ज्यादा गरीब बसते हैं और उनके लिए यह जरूरी है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पंजीकृत कितने श्रमिक परिवारों को साईकिल, औजार, इलाज हेतु सहायता, आवास निर्माण हेतु सहायता, बच्चों की पैदाइश पर सहायता, बेटियों की शादी आदि योजनाओं का लाभ बीते दो वर्षों के मध्य दिया गया ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 श्रम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पंजीकृत श्रमिक परिवारों को प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि तक रोजगार देने और पेंशन आदि का लाभ देने की भी कोई योजना लागू करेगी ? एक बात और मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं ? क्योंकि बेरोजगारों की भरमार है और बेरोजगारों में पंजीकरण का मामला ऐसा है माननीय श्रम मंत्री जी आप देखिये, आपके जो कैम्प लगते हैं उसमें मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो कैम्प के माध्यम से पंजीकरण कराने के लिए आते हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए होती है कि आपके कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से या कोई कारण होगा वो कैम्प समय से नहीं लग पाते जिससे खासतौर से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पंजीकृत बेरोजगारों को निश्चित अवधि में रोजगार देने, आयु सीमा बढ़ाने और बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना बनायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि अब तक दो सालों में कितने कैम्प लगे हैं। मान्यवर, 19 मार्च, 2017 को हम लोगों ने शपथ लिया था, उसके बाद अप्रैल, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2018 तक आगरा मण्डल में 322 कैम्प, और 2018-2019 में 499 कैम्प लगे हैं। इसी के सापेक्ष 2017-2018 में आगरा मण्डल में 17692 तथा

2018-2019 में 18898 श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित कराया गया है। इसी प्रकार से 2017-18 में अलीगढ़ में 86 कैम्प, 2018-19 में 66 कैम्प आयोजित किये गये और 2017-18 में 11067 और 2018-19 में 4446 श्रमिकों के पंजीयन किये गये। प्रयागराज में 2017-18 में 51 कैम्प, 2018-19 में 72 कैम्प, 2017-2018 में 6976 और 2018-19 में 9579 श्रमिकों के पंजीयन हुये हैं। इसी प्रकार से आजमगढ़ में कुल 32 कैम्प और कुल 2834 पंजीयन हुये हैं।

बरेली में कुल कैम्प 121 और श्रमिकों का पंजीयन 13143, बस्ती में कुल कैम्प 103 और कुल पंजीयन 5762, बांदा चित्रकूट धाम में कुल कैम्प 309 और कुल पंजीयन मजदूरों का 14099, इसी प्रकार से गोण्डा देवी पाटन मण्डल में कुल कैम्प 126 और कुल श्रमिकों का पंजीयन 5819, फैजाबाद अयोध्या मण्डल में कुल कैम्प 356 और पंजीयन 12389, नोएडा गौतमबुद्ध नगर में कुल कैम्प 581 और कुल मजदूरों का पंजीयन 52,422, इसी प्रकार से गाजियाबाद में कुल कैम्प 113 और पंजीयन 9472, गोरखपुर में कुल कैम्प 374 और पंजीकृत मजदूर 14087 .....

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा हुआ तो तब मान सकते हैं जब आपके पास कागज हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसी प्रकार झांसी मण्डल में कुल कैम्प 28 और पंजीकृत मजदूर 3797, कानपुर में कुल कैम्प 620 और मजदूरों का पंजीयन 72,170 लखनऊ में कुल कैम्प 424 और मजदूरों का पंजीयन 33017, मेरठ मण्डल में कुल कैम्प 156 मजदूरों का पंजीयन 12688, पिपरी सोनभद्र में कुल कैम्प 183 और पंजीयन 19207, मुरादाबाद में कुल कैम्प 443 और मजदूरों का पंजीयन 5714, सहारनपुर में कुल कैम्प 310 और कुल मजदूरों का पंजीयन 71920, इसी प्रकार से वाराणसी मण्डल में कुल कैम्प 226 और मजदूरों का पंजीयन 36638 इस तरीके से इन दो सालों में कुल कैम्प लगे हैं 5,551 जिसमें कुल पंजीयन हुआ है 4 लाख 53 हजार 929 और मान्यवर श्रमिकों को पंजीयन के मामले में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए हमने आन लाइन पंजीयन भी शुरू कर दिया है जो पहली बार हुआ है और इसके साथ ही साथ पूरे देश में मैं पहला श्रम मंत्री हूं जो पहली बार लेबर चौराहों पर जाने का सिलसिला जारी किया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

पहली बार लेबर अड्डों पर जाने की मैंने सूचना जारी करवाई। मान्यवर, मैं जिन लेबर अड्डों पर गया जिसमें से अब तक जनपद कुशीनगर, बाराबंकी में लेबर अड्डा, बरेली बीसलपुर चौराहा, निगोही लेबर अड्डा, खजान्ची चौराहा लेबर अड्डा, गोरखपुर, देवरिया में लेबर अड्डा, गोरखपुर में लेबर अड्डा, दक्षिण दरवाजा चौराहा लेबर अड्डा बस्ती, फतेहपुर लेबर अड्डा गांधी मैदान, फैजाबाद लेबर अड्डा नवीन मंडी, नोएडा में लेबर अड्डा, आगरा में लेबर अड्डा का कार्यक्रम, लखनऊ में लेबर अड्डा का कार्यक्रम, हरदोई बिलग्राम चुंगी लेबर अड्डे का कार्यक्रम, फिरोजाबाद में लेबर अड्डे का कार्यक्रम, मथुरा में लेबर अड्डे का कार्यक्रम, बदायूं में लेबर अड्डे का कार्यक्रम, कन्नौज, हापुड़, आजमगढ़, झांसी, कानपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, मथुरा, कौशाम्बी, लखनऊ इतने जिलों में खुद मैं एक-एक लेबर अड्डे पर स्वंय गया हूं और वहां पर सामूहिक रूप से मजदूरों का न केवल पंजीयन कराया है बल्कि हित लाभ योजनाओं को बांटने का भी काम किया है। माननीय सदस्य को अवगत करा देना चाहता हूं जब से इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली लगभग पौने दो साल हो रहे हैं इसके दौरान मान्यवर, 12 लाख 68 हजार 453 कुल मजदूरों का पंजीयन कराया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जबसे बी0ओ0सी0 बोर्ड का गठन हुआ है, मेरी सरकार बनने से पहले तक इतने लम्बे अन्तराल में कुल 34,27,104 पंजीयन हुए थे और मैंने पौने दो साल के अन्दर ही 12,68,453 पंजीयन करा दिये हैं। वर्तमान में कुल 47 लाख पंजीयन हुए हैं, वर्तमान में जहां पंजीयन 34 लाख था, वहां 47 लाख हुआ है यानि 13 लाख श्रमिकों का पंजीयन हमारी सरकार में हुआ है। चूंकि 'सबका साथ, सबका विकास' के तहत श्रमिकों के चेहरे पर भी मुस्कान आए, वह भी विकास की मुख्यधारा में खड़े हों। इस चिन्ता के साथ मैंने लेबर अड्डों पर भी जाना शुरू किया। इसके साथ-साथ हमने श्रम विभाग में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठ जायें। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, इनको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया है, हम उसका भी रिकार्ड तोड़ करके उससे ज्यादा श्रमिकों के लिए योजनायें चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका हो गया। अब हम प्रश्न संख्या-5 लेते हैं।

(सदस्य श्री मो0 फईम इरफान द्वारा बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें आपका उत्तर आ गया है।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, क्या बिल्कुसूस काबिले ऐतराम मंत्री जी यह बताने की कोशिश करेंगे कि बुनकर समाज के श्रमिकों के लिए आपकी कोई स्पेशल योजना है ? मैंने आपसे बहुत छोटा सा प्रश्न किया है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब बुनकर समाज है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी पूरे प्रदेश का बता चुके हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हर चीज का जवाब है। अभी कहेंगे कि यह भी पहली बार है। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन सन् 2008 से लम्बित था। अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों ने इस बोर्ड का गठन नहीं किया था। मंत्री बनने के एक साल के अन्दर हमने इस बोर्ड का गठन किया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य केवल बुनकर के बारे में पूछ रहे हैं। आप केवल बुनकर का बता दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, वह भी इसी में है। बोर्ड का पहला गठन है। पूरा हाउस बैठा हुआ है। मा0 सदस्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए एक बात और बता देना चाहता हूं। इस बोर्ड का जो गठन हुआ है, इसमें सभी प्रकार के कर्मकार आयेंगे। इसमें बुनकर, मोची, नाई, धोबी, पटरी दुकानदार, ठेलिया वाला, मूंगफली बेचने वाला, चाट बेचने वाला, इक्का, तांगा, बैलगाड़ी, रिक्शा यह सभी शामिल हैं। यही नहीं खेत-खलिहान में काम करने वाला मजदूर, जिसको अभी तक कोई नहीं पूछता था, वह भी इसमें शामिल है और सभी प्रकार के मजदूरों को इसमें शामिल किया गया है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन एवं जले ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ाने विषयक

***5-सुश्री अदिति सिंह**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है ? यदि हां, तो इन कनेक्शनों से प्रदेश के अधिकांश ग्राम सभाओं में स्वीकृत क्षमता से ज्यादा लोड हो जाने के कारण ट्रांसफार्मरों की ट्रिपिंग एवं बार-बार जलने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि

हां, तो क्या सरकार ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हेतु बजट का प्राविधान करते हुए उन्हें बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

ग्रामीण क्षेत्र के अविद्युतीकृत घरों को विद्युत संयोजन निर्गत करने के लिये सौभाग्य योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर गरीब परिवारों को निःशुल्क संयोजन एवं नॉन पूअर परिवारों को विद्युत बिल में रु0 50 प्रति माह कुल 10 मासिक किस्तों पर संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।

सौभाग्य योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत संयोजनों के कारण विद्युत प्रणाली पर आने वाले विद्युत भार को वहन करने के लिये 1775 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 90750 ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा 245 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 251 सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुश्री अदिति सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि योजना तो आप जो भी ले आएं जो मीटर रीडर्स होते हैं जो रीडिंग लेने जाते हैं जो मीटर गरीब परिवारों के घरों में लगे होते हैं वह आप टेंडर पर देते हैं कान्ट्रेक्ट पर देते हैं किसी ठेकेदार को मिल जाते हैं। ऐसे लोग वहां पर जाकर वसूली करते हैं महीनों-महीनों मीटर का बिल नहीं आता है जब बिल आता है तो वह इतना ज्यादा आ जाता है कि जब उसको करेक्ट कराने का प्रयास किया जाता है तो गरीबों से वसूली करी जाती है उनकी क्या एकाउन्टेबिलटी है सबसे पहले आप उन कम्पनियों को कैसे कन्ट्रोल कर रहे हैं जो आपके बिहाफ पर वहां जाकर वसूली कर रहे हैं जिनके घर में एक या दो बल्व लगे हुए हैं उन लोगों से मेरा दूसरा प्रश्न जो ट्रांसफार्मर का था एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अपने कनेक्शन बढ़ाते जा रहे हैं दूसरी तरफ अभी ट्रांसफार्मर उस हिसाब से लग नहीं पाए हैं। जो फुंक जाते हैं, जो जल जाते हैं, जहां नए ट्रांसफार्मर चाहिए होते हैं, जहां क्षमता वृद्धि करानी होती है वहां ट्रांसफार्मर लग नहीं पाते हैं तो यह किसी भी तरीके से आफसेट नहीं हो पा रहे हैं इनफैक्ट जो एक्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर हैं वह भी जले जा रहे हैं इट इज ए काउन्टर प्रोडक्टिव थिंग इट इज ए काउन्टर प्रोडक्टिव योजना तो इसका आपका क्या निस्तारण है और जो आपने कहा है कि आप 90750 ट्रांसफार्मर लगवाएंगे इसकी क्या समय-सीमा है। क्योंकि जैसे-जैसे कनेक्शन बढ़ते जा

रहे हैं ट्रांसफार्मर फुंकते जा रहे हैं तो यह लेने के देने पड़ रहे हैं तो हम घाटे में जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के मामले में।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जिस तादात में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं और जिस गति से लोड बढ़ रहा है उसी के अनुसार मैंने अपने जवाब में इसका उल्लेख किया है कि 1775 करोड़ की लागत से 90750 ट्रांसफार्मरों की स्थापना उसी के साथ-साथ 245 करोड़ की अनुमानित लागत से 251 सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का कार्य कराया जा रहा है। और यह जो पूरी कार्य योजना है 31 मार्च तक पूर्ण होने की सम्भावना है यानि कि पूर्ण हो जाएगी। तो माननीय अध्यक्ष जी हम यह आपके माध्यम से सबको सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि जो नए कनेक्शन दिए हैं जिसके सापेक्ष जो लोड बढ़ा है उसके एकार्डिंगली हमारा जो ओमिटेशन का कार्य है वह भी बहुत तेज गति से चल रहा है, 31 मार्च तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

अब तो सब बात आ गई मंत्री जी ने नीति बता दी नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं।

सुश्री अदिति सिंह-

क्या माननीय मंत्री जी इस चीज का आश्वासन देंगे कि 31 मार्च तक यह 90 हजार 750 ट्रांसफार्मर और 245 करोड़ से 251 सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का आश्वासन मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह तो दे दिया है।

श्री सुखदेव राजभर-

अभी बी0पी0एल0, ए0पी0एल0, लाभार्थियों को निःशुल्क कनेक्शन देने की आपने स्कीम चलाई मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिन बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 लोगों को यह कनेक्शन दिया जा रहा है आप निःशुल्क दे रहे हैं उनकी रसीदें भी कट गई हैं क्या उनको कनेक्शन दे दिया गया है उनके घर में बल्व जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं अगर नहीं जल रहे हैं तो उनका जो बिल आया है उसको आप माफ कर देंगे।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

यह जो कनेक्शन देने की प्रक्रिया है उसको हमने तकनीकी के साथ जोड़ा है जितने भी कनेक्शन दिए जा रहे हैं सबको ऐप पर हमारे जो सम्बन्धित कर्मी हैं वह इसको अपलोड करते हैं उसी के आधार पर इनका बिल जनरेट होता है माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं अगर

इस तरह का कोई मसला उनके संज्ञान में है और हमें वह देंगे तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मंत्री जी यह जनरल है आप केवल पता लगा लें हो सकता है कि आप तक बात न पहुंची हो हम लोग गांव में रहते हैं अगर आप कहें तो मैं सैम्पल के तौर पर पांच गांव, दस गांव दे दूंगा जहां पर उनको बिल दे दिया गया है कैम्प लगाकर आपने कनेक्शन दिया है लेकिन आज तक उनके घर में बल्व नहीं जला है अगर आप इतना एस्योर्ड हैं तो मैं आपको 10 गांव दे दूंगा और भेज दूंगा कि आपने इन 10 गांवों में कनेक्शन दे दिया लेकिन इन घरों में बल्व नहीं जल रहा है, कनेक्शन जोड़ा नहीं गया है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, घर-घर बिजली देने की यह जो योजना है, वह वर्ष 2002 में पं0 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से शुरू हुई थी, लेकिन इसको इतना लटकाया और भटकाया गया कि जो अन्तिम व्यक्ति है जिसको उसका लाभ मिलना चाहिये वह इससे वंचित रहा। हम अपने मा0 प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन करेंगे कि वह सौभाग्य योजना लेकर आए और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 95 लाख लोगों को, 95 लाख उपभोक्ताओं को 21 महीने में मुफ्त में कनेक्शन देने का काम किया है। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) उसमें भी मैं सभी का सहयोग चाहूंगा।

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन के सभी मा0 सदस्यों का सहयोग चाहूंगा, क्योंकि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है और यह पूरे उत्तर प्रदेश में सबको मिले, ऐसी हमारी सरकार की मंशा है। इसमें सभी लोग सहयोग करें। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत अगर मा0 सदस्यों के विधान सभा क्षेत्र के किसी गली-मोहल्ले में कहीं भी कोई त्रुटि है तो लिखित में वह हमें उपलब्ध करा दें, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको भी करेक्ट करने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। मा0 सदस्य श्री रितेश पाण्डेय जी उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनमीटर्ड बिजली उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लगाने पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ अधिकारियों द्वारा हड़पने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

***6-श्री रितेश पाण्डेय (अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनमीटर्ड बिजली उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लगाने पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या

सरकार को जानकारी है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देश का पालन विद्युत वितरण निगम नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन समस्त विद्युत वितरण निगमों द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 रितेश पाण्डेय जी उपस्थित नहीं हैं इसलिये अनुरोध है कि मेरा प्रश्न ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 रितेश पाण्डेय जी उपस्थित नहीं हैं तो अब अगला प्रश्न संख्या-7 मा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा जी का है।

प्रदेश में बेरोजगारों की नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में

***7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में विगत 2 वर्षों में कुल कितने बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं ? क्या सरकार प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या के सापेक्ष रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होने के कारण बेरोजगारों की नियुक्ति की उम्र बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित आयोगों के माध्यम से किया जाता है।

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 06-06-2012 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्याधीन समस्त सेवाओं में और पदों में भर्ती के सम्बन्ध में अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को उक्त निर्धारित 40 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट प्रदान

की गई है। अतः राज्याधीन सेवाओं और पदों में भर्ती के सम्बन्ध में आयु सीमा बढ़ाये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

(इस मध्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने स्थान पर खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, आप प्रश्न पढ़ेंगे या पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हम सप्लीमेंट्री पूछ लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिये। मा0 मौर्या जी, आप बैठ जाइये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल कितने सरकारी पद रिक्त हैं ? नम्बर दो, सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु कितने पदों का अधियाचन विभिन्न आयोगों को भेजा गया है ? नम्बर तीन, विगत दो वर्षों में आयोगों द्वारा कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ?

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न भी ले लीजिये अन्यथा समय नहीं रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राइनी जी, पहले मा0 वर्मा जी के प्रश्न का उत्तर आ जाए। मा0 श्रम मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 वर्मा जी बहुत वरिष्ठतम सदस्यों में हैं। यह जगजाहिर है कि लोक सेवा आयोग में अन्य विभागों से जो भी अधियाचन भेजे जाते हैं उसका संग्रह कार्मिक विभाग के पास होता है, इसका श्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है और वर्तमान सेवायोजन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सेवायोजन से वर्तमान में जो भर्तियां होती हैं उसका लेखा-जोखा मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और जहां आयोगों में विभिन्न प्रकार की भर्तियों की जो चयन प्रक्रिया है, कहीं लोक सेवा आयोग है, कहीं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, कहीं उच्च शिक्षा चयन बोर्ड है, कहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, कहीं पुलिस भर्ती बोर्ड है और यद्यपि यह सेवायोजन से इतर हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि आज वर्तमान में 02 वर्षों

में सेवायोजन से संबंधित बेरोजगार नौजवानों को जो इम्प्लायमेंट मिला, उसमें 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक 63,152 और 01 अप्रैल, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक 97,229 यानि कुल मिला करके सेवायोजन से 1,60,381 और इसी से संबंधित कौशल विकास से 2,72,768 यानि सेवायोजन एवं कौशल विकास के माध्यम से लगभग 04 लाख बेराजगार नौजवानों को रोजगार दिया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आप हमारा प्रश्न देख लीजिये। हमने सरकारी नौकरियों के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष-

सरकारी नौकरियों के बारे में बताया है कि लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचन का वर्तमान श्रम एवं सेवायोजन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया है। आपके माध्यम से मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कितने पद रिक्त हैं, नम्बर एक ? नम्बर दो, कितने पदों का अधियाचन भेजा गया ? नम्बर तीन, इस सरकार के कार्यकाल में कितनी सरकारी नौकरियां दी गयीं ? मेरे इन तीन प्रश्नों का उत्तर मा0 मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये। अभी आधा मिनट शेष है, मा0 मंत्री जी, आप अन्तिम वाक्य बोल सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसके अतिरिक्त अगर आपने जिज्ञासा जाहिर की है तो आपको जानकारी दे सकूं। इसलिए आपके माध्यम से पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित है, बेसिक शिक्षा में 41,556 शिक्षकों का चयन हो गया है, 68,500 शिक्षकों का चयन होना था, जिसमें से इतने का हो गया है, आगे प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है, वर्तमान में चल रही। 1,23,619 पुलिस की भर्ती होनी है, जिसमें 27 प्रतिशत पूरा हो गया है और 42 हजार की परीक्षा पूर्ण कर लिए हैं, अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है और 50 हजार परीक्षार्थियों की परीक्षा लिया जाना है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। †

† नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या-07 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में ट्रकों की ओवरलोडिंग रोकने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

***8-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रकों की ओवरलोडिंग रोकने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

जी हां।

केन्द्रीय मोटर अधिनियम, 1988 की धारा-113 के अन्तर्गत माल वाहनों में क्षमता से अधिक माल ढोना निषिद्ध है। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा-114 में भार क्षमता से अधिक लदान पाये जाने पर उसे वाहन से उतारे जाने का भी प्राविधान है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-194 में यह प्राविधान है कि अधिनियम की उक्त धारा-113 एवं 114 के उपबन्धों का उल्लंघन करके संचालित किये जा रहे वाहनों को न्यूनतम रुपये 2000/- जुर्माना और आधिक्य भार के लिये प्रति टन रुपये 1000/- की अतिरिक्त धनराशि से दण्डित किया जायेगा।

विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों का संचालन बन्द कराने हेतु प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निरन्तर चेकिंग की कार्यवाही की जाती है और समय-समय पर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाये जाते हैं। जांच के दौरान ओवरलोडिंग वाहनों के संचालित पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार बन्द करने/चालान की कार्यवाही निरन्तर की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 75099 वाहनों का चालान किया गया, 61144 ओवरलोड वाहनों का अधिक माल उतारा गया एवं प्रशमन शुल्क की राशि के रूप में 9338.41 लाख रुपये की वसूली की गई। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 (माह अप्रैल, 2018 से माह दिसम्बर, 2018 तक) कुल 52695 वाहनों का चालान किया गया, 40690 ओवरलोड वाहनों का अधिक माल उतारा गया एवं प्रशमन शुल्क की राशि के रूप में 7883.17 लाख रुपये वसूल किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सड़कों को क्षतिग्रस्त करने के कारण ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध प्रिवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी ऐक्ट 1984 (पीडीपीपी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में कुल 483 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में (माह अप्रैल, 2018 से माह दिसम्बर, 2018 तक) प्रदेश में कुल 296 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित धान क्रय केन्द्रों एवं गोरखपुर मण्डल व जनपद महराजगंज के धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से हुए धान क्रय के विवरण की जानकारी

***9-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वर्ष में कितने धान क्रय केन्द्र संचालित हुए तथा गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना धान क्रय किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर मण्डल तथा जनपद महाराजगंज में वर्तमान वर्ष में धान के कितने क्रय केन्द्र खोले गए तथा उनमें गत वर्ष के सापेक्ष कुल कितना धान क्रय किया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

खरीद विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 3107 धान क्रय केन्द्र संचालित हैं तथा दिनांक 30-01-2019 तक प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य 50 लाख मी0टन के सापेक्ष 41.19 लाख मी0टन धान की खरीद हुई है। गतवर्ष प्रदेश में तद्दिनांक तक 38.76 लाख मी0टन धान की खरीद हुई थी।

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गोरखपुर सम्भाग में विभिन्न क्रय एजेन्सियों के कुल 377 धान क्रय केन्द्र संचालित किये गये हैं तथा सम्भाग हेतु निर्धारित लक्ष्य 387000 मी0टन के सापेक्ष दिनांक 28-01-2019 तक कुल 339402.32 मी0टन धान की खरीद हुई है। गतवर्ष सम्भाग में दिनांक 28-01-2018 तक कुल 274296.62 मी0टन धान खरीद हुई थी तथा सम्पूर्ण खरीद अवधि अर्थात् दिनांक 28-02-2018 तक कुल 314133.47 मी0टन खरीद हुई थी।

सम्भाग के जनपद महाराजगंज में वर्तमान वर्ष में कुल 120 धान क्रय केन्द्र संचालित हैं तथा जनपद महाराजगंज हेतु निर्धारित लक्ष्य 173700 मी0टन के सापेक्ष दिनांक 28-01-2019 तक कुल 149589.10 मी0टन धान खरीद हुई है। जनपद महाराजगंज में गतवर्ष दिनांक 28-01-2018 तक कुल 130572.62 मी0टन धान खरीद हुई थी तथा सम्पूर्ण खरीद अवधि अर्थात् दिनांक 28-02-2018 तक कुल 148199.33 मी0टन धान खरीद हुई थी।

दिनांक 30-01-2019 तक गोरखपुर सम्भाग की कुल धान खरीद 343762.77 मी0 टन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रत्येक जनपदों में मौरंग बालू के खनन में आवंटित पट्टों के सम्बन्ध में

***10-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में कितनी-कितनी मात्रा में बालू-मौरंग के खनन के पट्टे किन-किन व्यक्तियों/फर्मों को

कितने-कितने समयावधि के लिये दिये गये हैं एवं 20 जनवरी, 2019 तक उनके द्वारा कितना-कितना खनन कर लिया गया है ? क्या यह सही है कि जनपद श्रावस्ती, बहराइच आदि सहित प्रदेश के सभी जनपदों में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर खनन वर्तमान में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर रोक लगाने हेतु कोई ठोस नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

सूची संलग्न है।[†]

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

खनन कार्य शासन द्वारा प्रख्यापित खनिज नीति-2017 के अन्तर्गत नियमानुसार स्वीकृत खनन पट्टों से किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-2778/2017, दिनांक 08-02-2017 के दिशा-निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में

1-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-2778/2017, दिनांक 08-02-2017 के क्रम में जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप शामली-पानीपत, मुजफ्फरनगर-करनाल, हरिद्वार-रोहतक, मेरठ-अम्बाला, सहारनपुर-जगाधरी अन्तर्राज्यीय मार्गों के उपान्तरण प्रस्ताव में याचीगणों को सरकार शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-2778/2017 सतीश गुर्जर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-02-2017 के क्रम में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-145 पर।

प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के बायोमेट्रिक वितरण प्रणाली में सेंध लगाकर हुई खाद्यान्न घोटाले की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

2-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018 में खाद्य एवं रसद विभाग के बायोमेट्रिक राशन वितरण प्रणाली में आधार संख्या बदल कर एक हजार केन्द्रों पर खाद्यान्न घोटाला किए जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

राशन वितरण प्रणाली में ई-पास मशीनों में आधार अथेन्टिकेशन सुविधा के दुरुपयोग करने का प्रकरण संज्ञान में आने पर समस्त जिलापूर्ति अधिकारियों को दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

जनपदों की संख्या	आधार दुरुपयोग द्वारा किये गये ट्रांजेक्शन की संख्या	दुरुपयोग किये गये आधार की संख्या	जनपदों में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या
43	186737	859	517	1670

वर्तमान में उक्त प्रकरण की जांच एस0टी0एफ0 द्वारा की जा रही है। एस0टी0एफ0 की जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मार्टिनगंज के ग्राम खासडीह में पावर हाउस से जनसामान्य को विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

3-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मार्टिनगंज के ग्राम खासडीह में पावर हाउस से जनसामान्य को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो किस तिथि से ? यदि नहीं, तो कब तक विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मार्टिनगंज के ग्राम खासडीह (कवरागहनी) में पावर हाउस से जन सामान्य को विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है। उक्त विद्युत उपकेन्द्र के लिये निर्माणाधीन 33 के0वी0 पोषक के निर्माण कार्य में अनेकों स्थान पर स्थानीय अवरोध उत्पन्न हो जाने से कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। उपकेन्द्र खासडीह (कवरागहनी) का नया प्रस्ताव बिजनेस प्लान (2019-20) में सम्मिलित किया जा रहा है। आवश्यक धनराशि प्राप्त होने पर कार्य सम्पादित करवाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

4-श्री सुखदेव राजभर-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में नेशनल हाई-वे, स्टेट हाई-वे, अन्य सड़क मार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

5-श्री सुखदेव राजभर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नेशनल हाई-वे, स्टेट हाई-वे तथा अन्य सड़क मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

सरकार द्वारा बनाई गई कार्य योजना के मुख्य बिन्दु का विवरण निम्नवत् है :-

- मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन किया गया, जिसकी बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों का अनुश्रवण करते हुए उसमें सुधार हेतु निर्णय लिया जाता है। सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटनाओं की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- मण्डल एवं जिला स्तर पर क्रमशः मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मण्डलीय एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया, उक्त समितियों की नियमित बैठक कराना।

- रोड इंजीनियरिंग में सुधार किये जाने हेतु रु0 5 करोड़ से अधिक की सड़क निर्माण परियोजनाओं के थर्ड पार्टी आडिट का अनिवार्य प्राविधान तथा सड़कों पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए सुधार की कार्यवाही कराना।
- ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस प्रक्रिया में सुधार हेतु ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथा ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण तथा परिवहन यानों के निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र की स्थापना।
- सुरक्षित वाहन एवं सुरक्षित चालक हेतु समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे- कार्यशाला, भाषण प्रतियोगिता, सिनेमा/मल्टीप्लेक्स में लघु फिल्मों का प्रदर्शन, होर्डिंग्स पम्पलेट का वितरण, निबन्ध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं गोष्ठियों आदि का आयोजन/अभियान करना/चलाना।
- परिवहन विभाग द्वारा परिवहन यानों में स्पीड गवर्नर के उपयोग को अनिवार्य किया गया। उक्त का अनुपालन कराना।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय का समावेश किया गया।
- डंकन ड्राइविंग/ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध जांच हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र को एक-एक इन्टरसेप्टर वाहन तथा प्रत्येक अधिकारी को ब्रेथ एनालाइजर का आवंटन एवं प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही करना।
- हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य किये जाने के दृष्टिगत पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा नियमित जांच/प्रवर्तन की कार्यवाही करना तथा जागरूकता भी फैलाना।
- दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों (नेक आदमी) को सुरक्षा तथा पुलिस जांच से संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाना।
- दुर्घटना बाहुल्य स्थानों एवं चौराहों को चिन्हित करते हुए रम्बलिंग स्ट्रिप एवं जेब्रा क्रासिंग का निर्माण।
- स्कूली वाहनों की नियमित चेकिंग करना।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के ब्लाक कैराना के कतिपय ग्रामों में विद्युत विभाग द्वारा खेल आदि में स्थापित परिवर्तक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

6-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी भूमि, प्लाट, खेत आदि में सम्पत्ति के मालिक की अनुमति के बिना विद्युत विभाग द्वारा परिवर्तक स्थापित किया जा सकता

है ? यदि नहीं, तो जनपद शामली के ब्लाक कैराना के ग्राम एरटी तथा झाड़खेड़ी में विद्युत विभाग द्वारा कतिपय भू-स्वामियों की निजी भूमि में उनकी अनुमति के बिना अधिष्ठापित परिवर्तक को चिन्हित कर सरकार अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

विद्युत लाइन एवं डबल पोल स्थापित परिवर्तक आदि के निर्माण हेतु भू-स्वामी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यदि भू-स्वामी की सम्पत्ति में कोई क्षति होती है तो उसके लिये भू-स्वामी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। इसी प्रकार के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वाद संख्या-14712/2007 के निर्णय में ऐसी व्यवस्था दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के हित में 7.5 हार्स पावर के नलकूपों पर दी जा रही छूट की भांति ही 3 हार्स पावर के नलकूपों पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में

7-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को 7.5 हार्स पावर के नलकूपों पर दी जा रही छूट की तरह उन्हें 3 हार्स पावर के नलकूपों पर भी छूट देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वर्ष 2017-18 व 2018-19 में विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजन के सम्बन्ध में

8-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में दिनांक 22-01-2019 तक जिन-जिन उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन दिये गए हैं उनके नाम, पिता का नाम व पता क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वितरित विद्युत संयोजनों की कीमत क्या है ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में दिनांक 22-01-2019 तक 1,14,371 उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन दिये गये हैं। इन उपभोक्ताओं की सूची (नाम, पिता का नाम व पता) वृहद् है जिसे मा0 विधायक जी को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उक्त वितरित संयोजनों की कीमत रु0 24.91 करोड़ है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्रामों में पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कितने मूल्य का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

9-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं योजना) व 12वीं योजना ग्राम स्वराज योजना (प्रथम चरण) एवं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों एवं मजरों में कितने मूल्य का कार्य पूर्ण कराया गया है तथा कितने खम्भे व ट्रांसफार्मर कितने के0 वी0 ए0 के लगे हैं ? क्या सरकार उक्त का ग्रामवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद शाहजहांपुर में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं योजना) में 1940 ग्राम/मजरों में व 12वीं योजना ग्राम स्वराज योजना (प्रथम चरण) में शून्य ग्रामों/मजरों एवं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 1547 ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण कराया गया। जिनका मूल्य रु0 131.11 करोड़ है।

उक्त योजनाओं में 103068 खम्भे व 25 के0वी0ए0 के 480.63 के0वी0ए0 के 4, 10 के0वी0ए0 के 2285 तथा 16 के0वी0ए0 के 2589 ट्रान्सफार्मर लगे हैं।

सूचना वृहद् है जिसे ग्रामवार तैयार कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(नेता प्रतिपक्ष, श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

[12:20] सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

हम आपको ही बुलाने जा रहे थे। प्रातःकाल जब आपने कोई बात कही थी, उसी पर मैं आपको बुलाने जा रहा था।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मुझे प्रातःकाल नियम-311 के अन्तर्गत एक नोटिस माननीय नेता प्रतिपक्ष व अन्य सदस्यों का मिला था। सामान्यतः मैं 311 को नहीं सुनता, लेकिन प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए जब माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्न काल के समय वह विषय उठाने की कोशिश की तो मैंने कहा था कि प्रश्नोत्तर काल के बाद इसे सुन लेंगे। यह भविष्य के लिए कोई नजीर नहीं मानी जायेगी, इस विशेष उल्लेख के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहें।

श्री मो0 फईम इरफान द्वारा व्यवस्था के अन्तर्गत उनका व्यक्तिगत प्रकरण

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी परसों एक नगर अध्यक्ष ने ...

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो कोई नहीं खड़ा होता है। नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बाधा नहीं डाली जाती है। अब आप बैठ जायें।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हाथ जोड़ने की बात नहीं है, आप इस सदन के सदस्य हैं, मेरे लिए माननीय हैं, आदरणीय हैं, इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है ?

श्री मो0 फईम इरफान-

अध्यक्ष जी, मेरा नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज को जाऊंगा, मेरी जरा 02 मिनट बात सुन लीजिए, वरना हाथ जोड़ कर मैं माफी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह के कई मामले हैं, मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री मो0 फईम इरफान-

अध्यक्ष जी, मुझे जान से मारने की सीधी-सीधी धमकी है, मेरे पास रिकार्डिंग है, अध्यक्ष जी, अगर विधायकों के साथ इस तरह की बात हो रही है, अगर हम आपको नहीं बतायेंगे तो किसे बतायेंगे ? मेरा व्यक्तिगत मामला है। अध्यक्ष जी, एक नगर अध्यक्ष जी ने मेरे खिलाफ यह कहा कि दो दिन के अन्दर विधायक को मार दिया जायेगा, उसकी रिकार्डिंग है। मेरी क्या खता है, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

खता नहीं है, अगर आपके पास ऐसी सूचना है तो आप उसे संसदीय कार्य मंत्री जी को दे दीजिए, वह उसकी जांच करा लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इनका मसला बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने हमको भी सुनाया। एक आदमी, एक पत्रकार को और हमारे माननीय सदस्य को भी जान से मारने की धमकी बार-बार दे रहा है, पत्रकार को दी और उन्हीं के साथ इनको भी दी। यह मामला गम्भीर है, इसका आप स्वयं संज्ञान लें और जिसने इस तरह की कार्यवाही की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारे माननीय सदस्य की सुरक्षा की व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ये एक लिखित प्रार्थना-पत्र माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को दे देंगे और उसकी कापी मुझे दे देंगे, संसदीय कार्य मंत्री जी इसे देख लेंगे। अब आप अपने विषय पर आइये।

सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 की सूचना (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि भारी मन से इस मसले को उठाने की आपने अनुमति दी। देश का जब संविधान बना और उस संविधान में शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी।

मान्यवर, डॉ0 भीमराम आम्बेडकर जी जिस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बिल हुआ उसी समय पिछड़ों का भी वह बिल लेकर आना चाहते थे, लेकिन उस समय संविधान सभा के संवाद में जो बहस हुई उसमें यह आया कि यह जातियां बहुत हैं इसलिए पहले इन जातियों के लिए आयोग बना दिया जाए उसके बाद आरक्षण लागू किया जाए पर आयोग नहीं बना। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसमें बहुत दिन तक तो बना ही नहीं फिर जनता पार्टी की सरकार में मण्डल आयोग बना और उसने 27 फरवरी को आरक्षण लागू किया। वर्तमान केन्द्र सरकार से लेकर यहां तक आरक्षण व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। हमारे एक व्यक्तिगत मित्र भी हैं और विद्वान भी हैं। वह सदन के पुराने सदस्य भी हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बार-बार दिखा रहे हैं कि यह वर्ष 2016 का है। मान्यवर, वर्ष 2016 में केंद्र में किसकी सरकार थी ? मान्यवर, वर्ष 2016 में केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। यू0जी0सी0 किसके अंडर में रहता है ? आपकी सरकार के अंडर में तो यू0जी0सी नहीं है। मान्यवर, यू0जी0सी0 केंद्र सरकार के अंडर में रहता है। अगर यह वर्ष 2016 का भी है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर यह आप ही की सरकार का है, दूसरा यह आया कि उच्च शिक्षा में शिक्षक नियुक्ति के लिए पदों की वितरण प्रणाली में पुराने रोस्टर को ले करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशात्मक आदेश को आधार मानकर मानव संसाधन

विकास मंत्रालय ने पत्र संख्याः 01-07-2017/सी0वी0 06 सितम्बर, 2017 लिखकर यू0जी0सी0 को निर्देश दिया जिसके परिणामस्वरूप यू0जी0सी0 ने एक सर्कुलर पत्र संख्याः 815/2006(सी0ए0सी0टी0) 5 मार्च, 2018 को जारी करके देश भर के विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि एक महीने के अन्दर सभी शैक्षणिक संस्थानों में विधिवार रोस्टर बनाया जाए। विधिवार रोस्टर के लागू होने से आरक्षित पदों की सीटें 50 प्रतिशत से घटकर लगभग 5 प्रतिशत मात्र रह जाती हैं। जिसका उदाहरण 5 मार्च के बाद आए दर्जनों विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के विज्ञापनों में देखा जा सकता है। विधिवार रोस्टर होने के बाद सड़क से सदन तक आन्दोलन के दबाव में एच0आर0डी0 और यू0जी0सी0 ने सुप्रीम कोर्ट में एस0एल0पी0 (स्पेशल लीव पिटीशन) दायर की। साथ ही 19 जुलाई, 2018 को यह बताते हुए कि नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन विगत 22 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दोनों एस0एल0पी0 खारिज कर दी है। वह इसलिए खारिज कर दी कि उसमें इस तरह के वितरण प्रस्तुत किये गये थे जिसे खारिज होना ही था। यू0जी0सी0 और मानव विकास संसाधन मंत्रालय दोनों ने मिलकर वहां कोई साक्ष्य ही नहीं दिया जिससे वह एक तरफा हो गया। ऐसे में 5 मार्च, 2018 को पत्र के अनुसार विधिवार रोस्टर स्वतः लागू हो गया।

इस रोस्टर को लेकर कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मान्यवर, इसे सुन लीजिएगा। यह प्रदेश और देश का मामला है। विधिवार रोस्टर बनाए जाने में किसी भी विभाग में आरक्षण नहीं बचा है। आरक्षण विरोधी विधिवार रोस्टर की यह नीति इंदिरा साहनी से ले करके आर0के0 सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्यांग और सबसे महत्वपूर्ण ए0नाथ राजन बनाम भारत सरकार 19 अक्टूबर, 2006 के निर्णयों में संविधान पीठ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक आरक्षण वह हिस्सेदारी के प्राविधानों का उल्लंघन करती है।

यह संवैधानिक प्राविधान के विरुद्ध है। आरक्षण लागू होने के बाद से रोस्टर में प्रत्येक 15 वां पद एस0सी0 को, 14वां पद एस0टी0 को और चौथा पद ओ0बी0सी0 को निर्धारित किया गया है। जिसका आधार आरक्षण का आनुपातिक वितरण है। जिसमें एस0टी0 7.5 प्रतिशत, एस0सी0 15 प्रतिशत और ओ0बी0सी0 27 प्रतिशत होगा। जिसे सीटों में तब्दील करने की व्यवहारिकता के कारण डी0ओ0पी0 में रोस्टर को 200 प्वाइंट का निर्धारित किया। इसको खत्म करने के लिए विश्वविद्यालय को इकाई मानकर 200 प्वाइंट रोस्टर बनाने पर लगभग 50 प्रतिशत मिलता जबकि विभागवार रोस्टर में आरक्षण लगभग 05 प्रतिशत रह जायेगा। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब है कि अभी सवर्ण जाति के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू हुआ। सभी ने उसका समर्थन किया। लेकिन जब मण्डल कमीशन लागू हुआ तो देश में सवर्ण जाति वालों ने घनघोर आन्दोलन किया। आपको यह आशंका रही होगी कि यदि सवर्ण जाति के लोगों के लिए आरक्षण किया तो पिछड़े और दलित के लोग भी सड़क पर जाकर आन्दोलन करेंगे। लेकिन नहीं पिछड़े और एस0सी0 जाति के लोग बड़े हृदय के लोग हैं। लेकिन जो भी गरीब है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए।

सपा-बसपा सारे दल के लोगों ने उसका समर्थन किया लोक सभा में, हम सड़क पर नहीं गये, हमारा हृदय देख लीजिए और आप अपना हृदय देखिये, आप हमारा आरक्षण रहते हुये उसमें काट-छांट कर रहे हैं। श्रीमन्, अगर इन्होंने विभाग को यूनिट मान लिया, तो चार या पांच अध्यापक की एक विभाग में नियुक्ति निकलती है, तो उसमें तो आरक्षण की सीट ही नहीं आयेगी। अगर विश्वविद्यालय यूनिट माना जाता था तो उसमें आरक्षण लागू होता था। हम लोग पिछली बार भी संसदीय कार्य मंत्री जी उठाये थे, तो हम लोग इनसे आग्रह करते रह गये कि जो नियुक्तियां हो गयी हैं उसको कैंसिल कर दीजिए और फिर इसको सुधारिये। पूरे देश में यह लागू हो गया है। जो लोगों में भय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है वह हमेशा से इसके खिलाफ रहा है, तो मैं इसमें अधिक कुछ न कहकर आपसे प्रार्थना करूंगा कि संविधान की आत्मा को मारा न जाये। गरीब, बेबस व लाचार के पेट पर लात न मारी जाये। अगर एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 के लोग प्रोफेसर, वाइस चांसलर, कलेक्टर, एस0पी0, प्रमुख सचिव, सचिव, डाक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक हो रहे हैं तो उसको देखकर जला न जाये। यह देश सबका है। आजादी की लड़ाई में सब मिलकर इस देश को आजाद कराये और हमारे पुरखों ने एक संविधान बनाया और उस संविधान से देश चलेगा। अभी मैंने कल कहा कि जो ओरिजनल संविधान की बात होती थी उसको मैंने सौ बार पढ़ा। सौ बार तो नहीं पढ़ा है लेकिन दिल्ली में जाते-जाते तीन खण्ड में तीन बार हम पढ़े हैं। तीन बार गये तो एक बार पूरा हुआ। हमारे यहां चन्द्रशेखर जी कहे थे कि वहां है, जा करके तुम वहां उसको पढ़ो तो उसमें बातें दूसरी। केवल बैकवर्ड, हरिजन तो उसमें थे नहीं। हर जाति धर्म के लोग संविधान सभा में थे। एक-एक प्वाइंट पर उसमें बहस हुआ और सारी बहस के बाद जो निचोड़ निकला उसको बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में रखा। आज विधान सभा में यह सब देख कर आम्बेडकर जी की भी आत्मा दुखी होगी।

मान्यवर, गांधी जी की आत्मा दुखी होगी और उस समय जितने संविधान सभा के सदस्य थे सबकी आत्मा रोयेगी। एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया है कि यही कारण से मैं दोष नहीं देता हूं क्योंकि जो मैं पढ़ता हूं वही कह जाता हूं। एक प्रसंग में मैने पढ़ा कि पटेल जी एवं एक कांग्रेस के नेता एस0सी/एस0टी0 के खिलाफ थे तो कांग्रेस के नेता आम्बेडकर के यहां गये और कहा कि इस काम को छोड़ दीजिए क्योंकि पटेल जी नाराज हैं। इसके बाद वह गांधी जी एवं जवाहर लाल नेहरू जी के यहां गये तो उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं और यह होना चाहिए। इसके बाद फिर जब वह पटेल जी के यहां गये तो उन्होंने पटेल जी से कहा कि गांधी जी एवं देश के सर्वोच्च ब्राह्मण परिवार के सदस्य जवाहर लाल नेहरू राजी हैं तो फिर आप क्यों राजी नहीं हैं, इसके बाद पटेल जी भी राजी हो गये। इतनी बड़ी आत्माओं के द्वारा बनाये गये संविधान को इस द्वेष से कि जो हजारो-लाखों वर्ष से हम लोग पीड़ित रहे हैं, दबे रहे हैं, न शिक्षा में रहे हैं, न आर्थिक स्थिति में रहे हैं, न खेत में रहे हैं, न खलिहान में रहे हैं, लोगों के खेतों में मजदूरी किये हैं, गाय-भैंस-बकरी चराये हैं। अगर लोग कलेक्टर,

एस0पी0, इंजीनियर एवं जज हो जायें तो उससे लोगों को जलना नहीं चाहिए। आइये हम सब मिल करके सबका साथ, सबका विकास करने का काम करें। यह आरक्षण की व्यवस्था खत्म न हो। यह व्यवस्था पहले जैसी थी वैसी ही रहे और सब लोग मिल-जुल करके एक भाई-चारे का वातावरण बना करके इस देश में चलने का काम करें। अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैं संविधान सभा की बहस में हिस्सा नहीं ले रहा हूं। संविधान सभा में मा0 सरदार पटेल जी ने आरक्षण समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और वह अल्पसंख्यक आरक्षण समिति के सभापति थे। उसमें उन्होंने अनुसूचित जातियों के आरक्षण का पक्ष लिया था। अब आप वर्मा जी बोलिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से चर्चा की है इसलिए मैं उस पर विस्तार से जाना नहीं चाहूंगा लेकिन मा0 संसदीय कार्य मंत्री कभी-कभी कहते हैं कि यह गलती वर्ष 2015-2016 की है अगर पहले यह गलती हो गई है तो क्या हम आज भी उसी गलती पर चलते रहें। मान लीजिए वह प्रदेश में नहीं थी। अगर उस समय गलती हो गई तो उस गलती को सुधारने के लिए प्रदेश की जनता ने आपको अवसर दिया है अगर आप उस गलती को दोहराते रहें तो फिर अन्तर क्या रह गया। मेरा आपसे निवेदन है कि जो 13 प्वाइंट रोस्टर है। देश के स्तर पर जो रिजर्वेशन का रोस्टर है वह 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत एस0सी0/एस0टी0 का और 27 प्रतिशत ओ0बी0सी0 का है लेकिन उत्तर प्रदेश में रोस्टर दूसरा है। उत्तर प्रदेश में एस0सी0 21 प्रतिशत और एस0टी0 का 2 प्रतिशत और पिछड़ी जाति का 27 प्रतिशत है। पहली बात केन्द्र का जो रोस्टर है वह हम पर वैसे भी लागू नहीं होगा। हमें उसके लिए अलग से अपना पक्ष प्रस्तुत करके काट करने की आवश्यकता है जो कि हम नहीं कर रहे हैं। जो 1, 4, 7, 14 गया है वह हमारा अपने आप पीछे आयेगा। इसलिए यह सरकार जान-बूझकर पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन लागू न होने पाये, इन्होंने हर विश्वविद्यालय स्तर पर अलग-अलग विभाग वाइज करके और उसमें अलग-अलग पद विज्ञापित करके उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके साथ कुठाराघात है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से चर्चा की।

मान्यवर, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी हमारे पांच मेडिकल कॉलेज, जो अयोध्या, बस्ती, शाहजहांपुर, बहराइच और फिरोजाबाद में हैं, इसमें भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इसी महीने की चार तारीख से इण्टरव्यू भी शुरू हो गया है इसलिए यह बहुत ही आवश्यक, तात्कालिक और अविलम्बनीय है। मान्यवर, इसमें 360 पदों पर भर्ती हो रही है

उसमें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उसमें से 105 पद प्रोफेसर के हैं, 140 पद एसो0 प्रोफेसर के हैं और 115 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। अगर हम रिजर्वेशन के नियमों का पालन करें तो 97 पद पिछड़ी जाति के लिए, 76 पद अनुसूचित जाति के लिए और 7 पद अनुसूचित जनजाति के लिए होते हैं लेकिन पूरी तरह आरक्षण का जो नियम है उसको काटने के लिए विज्ञापन भी अलग-अलग पदों के लिए दिया गया है। मान्यवर, एक तो अलग-अलग तरह के तीन विज्ञापन दिए गए, प्रथम विज्ञापन में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सात-सात पद प्रोफेसर के भर्ती हों, दूसरे विज्ञापन में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सात-सात नामित प्रोफेसर के पद कर दिए। प्रोफेसर और नामित प्रोफेसर अलग-अलग कर दिया। इसी तरह से एसो0 प्रोफेसर और नामित एसो0 प्रोफेसर कर दिया और तीसरे विज्ञापन में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सात-सात प्रोफेसर के पद कर दिए। इस तरह से अलग-अलग ढंग से निकाल कर तीन बार विज्ञापन करके निकाला और 360 में एक भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के, चिकित्सा शिक्षक के पद का जिक्र विज्ञापन में नहीं किया गया है। न उसमें उन्हें आयु में छूट देने का काम किया गया, अनुसूचित जाति-जनजाति को आयु में छूट देने का नियम है, उसका उल्लेख भी नहीं किया गया है। इस तरह से पूरे प्रदेश के इन वर्गों को, जिनके बड़े संघर्षों के बाद, बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने, अनुसूचित जाति को, अछूत समाज के नाम से जाना जाता है, प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, संघर्ष किया। जिसके आधार पर 1928 में लार्ड डि लिथीयन कमेटी बनी, 17 अगस्त, 1932 को कम्युनल एवार्ड को ब्रिटिश हुकूमत ने घोषणा करने का काम किया। आजादी के बाद उसी आधार पर अनुसूचित जाति-जनजाति को रिजर्वेशन देने का काम किया गया। बड़े संघर्षों के बाद काका कालेलकर आयोग बना, उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में गयी, फिर मण्डल आयोग बना उसने एक रिपोर्ट दी। लम्बे संघर्षों के बाद 80 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, 89 में जाकर लागू करने का विचार हुआ और 90 में जाकर घोषणा हुई। बड़े संघर्षों के बाद हमें जो अधिकार मिला, आज ये सरकार किसी न किसी तरीके उस अधिकार को छीनने का काम कर रही है।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर पूरे दिन डिबेट कराने की आवश्यकता है। सभी सदस्यों को इसमें हिस्सा लेने की आवश्यकता है, ताकि इसे तत्काल निष्प्रभावी किया जा सके, 04 फरवरी से इण्टरव्यू हो रहा है सबकी नियुक्ति हो जाएगी फिर बाद में हम क्या कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर तात्कालिक रोक लगाई जाए ताकि जिससे इस पर अन्याय-अत्याचार न होने पाए। इसलिए मैं चाहूंगा तत्काल इसे स्वीकार कर लें, ग्राह्य कर लें और कम से कम पांच घण्टे की चर्चा कराएं, इसमें पक्ष-विपक्ष के सारे लोग शामिल हों और कैसे आरक्षण को निष्प्रभावी करने का काम किया जा रहा है उसे प्रभावी किया जा सके। इस पर एक अच्छा निर्णय आए इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे ग्राह्य करने का काम करें। मान्यवर, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा और केंद्र का अलग-अलग विषय है। केंद्र सरकार में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है और उत्तर प्रदेश में

30 प्रतिशत है, इसलिए उनका रोस्टर अपने आप हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए हम अलग से निर्णय लें, हम उनके निर्णय को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। हम उसके लिए अपना निश्चित रूप से कार्य कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग को केवल 14 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलता है तो निश्चित रूप से वहां 14 प्रतिशत है तो वहां 27 प्रतिशत कैसे हो पाएगा। वहां अनुसूचित जनजाति का 33 प्रतिशत है तो उस स्टेट में अनुसूचित जनजाति का और हमारा अलग-अलग होगा, इसलिए मैं चाहूंगा इस पर पूरी तरह से चर्चा कराने की कृपा करें जिससे हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोका जा सके, धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय दीजिए। वर्मा जी ने पांच घण्टे चर्चा की बात कही और यह मामला भी बहुत बड़ा है। शेड्यूल कास्ट, एस0टी0 के पक्ष में भी बोल रहे और विपक्ष में भी बोल रहे, तो सबकी भावना आ जाए बाद में जो कहेंगे वह करेंगे, क्योंकि सबकी भावनाएं इसमें आनी चाहिए, जो पांच घण्टे का उन्होंने कहा है अगर बहुत तेजी हो तो चार घण्टा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

विपक्ष की भावना को प्रतिनिधित्व आपने दे दिया। विपक्ष के बड़े दल की भावना को प्रतिनिधित्व मा0 वर्मा जी ने दे दिया। सरकार की भावना का प्रतिनिधित्व मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे। पूरा सदन तो अवगत हो गया। हम हैं ही आपके साथ। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

*** संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**-

मा0 अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप घड़ी देख लें 12 बजकर 20 मिनट से यह बहस शुरू हुई। ग्राह्यता पर मा0 राम गोविन्द चौधरी जी 15 मिनट बोले। 10 मिनट आप भी बोल लिए। 25 मिनट तो ग्राह्यता पर ही हो गया मान्यवर, आपने जो बात कही थी उस पर रहिये, आपने अध्यक्ष जी से यह कहा था कि हम 311 में अपने दो मिनट उठा लेंगे, 25 मिनट तो हो गए जिसकी वजह से कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय यह नहीं होगा। मा0 अध्यक्ष जी ने कृपा पूर्वक सुन लिया तो हम आपकी बात का उत्तर देंगे। अब आप सुनें। मा0 अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान सम्मत आरक्षण है, उसके प्रति पूरी तरह से पक्षधर है और सौ परसेण्ट मान्यवर उसका पालन करेंगे। एक परसेण्ट भी उसमें कोई कोताही ना मन में है और ना ही व्यवहार में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप सब लोग कृपया बैठें। आपके वरिष्ठ नेता सदन में नेता प्रतिपक्ष का एक महत्व है, वह बोल रहे हैं तो बीच में आप लोग क्यों बोल रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बहुत कुछ कहा। मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया, वह हमने दिया। यह आपके ऊपर कृपा नहीं की, यह हमारी पार्टी और हमारा संकल्प है इसलिए किया। हमने देखा है बहुत से पिछड़े वर्ग के हमदर्दों को कि पीछे से क्या बात करते हैं। मान्यवर, यह दोनों लोग गठबन्धन के नाम पर लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

जब आप लोग कह रहे थे तो हमारी तरफ से किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब आप सुनिये उसे। 25 मिनट तक हमने सुना अब आप सुनिये। देखिए जहां तक मा0 आम्बेडकर जी का सवाल है, आम्बेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर और उनके निर्वाण स्थान तक जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी और एन0डी0ए0 की सरकार ने किया है इसका जवाब हम नहीं देंगे तो और कौन देगा। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने आम्बेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर, जहां लन्दन में उन्होंने पढ़ाई की, नागपुर में जहां दीक्षा ली, बाम्बे और दिल्ली जहां उनका निर्वाण हुआ। पांचों को तीर्थ स्थान घोषित भारतीय जनता पार्टी ने किया और एन0डी0ए0 की सरकार ने किया और उनके ऊपर भव्य स्मारक बनाया। आप दिल्ली में जाकर देख लें भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। बार-बार किसी बात को कहने से वह बदल नहीं जाता।

मान्यवर, वर्ष 2010 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और एक चिकित्सा शिक्षा मंत्री मा0 श्री लाल जी वर्मा यहां पर बैठते थे, उनकी सरकार थी और छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए विशेष रूप से एक शासनादेश जारी हुआ। मान्यवर, मैं आपके पास भेजे देता हूं। यह शासनादेश वर्ष 2010 का है जब मा0 लाल जी वर्मा यहां पर बैठते थे। वह शासनादेश मैं आपके पास भेजे देता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसकी लाइनें पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पढ़िए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अतएव चिकित्सा विश्वविद्यालय के जिन विभागों में एक से तीन पद सृजित हैं, वहां प्रतिशत के आधार पर आरक्षण की अनुमन्यता नहीं होगी। अतः उक्त पद अनारक्षित श्रेणी में

रहेंगे। मा0 श्री लाल जी वर्मा उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे यह उस वक्त का है। दूसरा जी0ओ0 वर्ष 2010 में दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 का है, मैं उसे भी आपके पास भेजे देता हूं। यह एस0जी0पी0जी0आई0 के लिए है। जैकब थॉमस उस समय प्रमुख सचिव थे। यह भी मैं आपके पास भेजे देता हूं कि **संस्थान में प्रत्येक विभाग में सृजित विभिन्न पदों को अलग-अलग यूनिट मानकर प्रत्येक पद पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए।** जिसका यहां विरोध हो रहा है। जब आप सत्ता में थे तो आप इसको सही ठहरा रहे थे, जो आपके द्वारा जारी किया गया था। मान्यवर, मैं ये दोनों शासनादेश आपके पास भेजे देता हूं। ये दोनों बसपा काल के हैं।

मान्यवर, अब बारी आती है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के समय का एक शासनादेश प्राविधिक शिक्षा विभाग का है। इसे भी हम आपके पास भेजे देते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है। विषय सिर्फ इतना है कि विभाग को यूनिट माना गया या पूरे विश्वविद्यालय को। मान्यवर, जो अभी इसमें स्थिति आई कि एक शासनादेश है दिनांक 15 जनवरी, 2016 का जब प्रदेश के अन्दर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इनका शासनादेश भी यही है, यह भी यही कहता है। हम इसमें आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। **उक्त दृष्टिगत इन संस्थाओं के पदों का समूहीकरण किया जाना समीचीन नहीं है। अतः पृथक-पृथक संस्था इकाई के अन्तर्गत ट्रेडवार पदों की संख्या को देखते हुए आरक्षण प्रतिशत के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।** मान्यवर, साथ ही साथ आपके जमाने में श्री आलोक रंजन जी एक हमारे मुख्य सचिव थे। उन्होंने दिनांक 28 अगस्त, 2015 को यह शासनादेश जारी किया कि **अगर गुणांक में 1.5 और 1.99 तक भी आता है तो भी उसका एक ही माना जाएगा।** यह भी एक शासनादेश है। हम तीनों शासनादेश आपके पास भेजे देते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था कि-

एक उम्र तक सियासत-ए-साकी से बेखबर
अपना ही लहू पीते रहे अपने जाम में।

यह पूरी तरह से इन पर लागू है। अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुंह मोड़ना अपने वक्त पर वह काम करना और जब विपक्ष में बैठे तो उसकी आलोचना करना। मान्यवर, जिसने स्वयं शासनादेश जारी किया हो, वह इसके ऊपर कैसे प्रश्न चिह्न लगा सकता है। समाजवादी पार्टी और बसपा इन दोनों लोगों ने अपने-अपने समय में विभागवार आरक्षण इन्होंने ही लागू किया है। हमने इसमें अभी तक कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया है। आपने आज जो यह विषय उठाया है इसलिए मैं आपके माध्यम से फैक्ट्स पर आना चाहता हूं। इसमें 360 पद नहीं हैं, पद केवल 235 हैं। 22 विभागों में 235 पद हैं और इन 235 पदों पर जो भी आरक्षण नियमानुसार बनेगा, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हम उसका परीक्षण करवा कर जितना एस0सी0 का निकलेगा उतना एस0सी0 को देंगे, जितना ओ0बी0सी0 का निकलेगा उतना

ओ0बी0सी0 को देंगे। न कोई कंजूसी करेंगे, न कोताही करेंगे, न किसी प्रकार की कोई लापरवाही करेंगे। जो विभाग में व्यवस्था है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको हम लागू करने का काम करेंगे।

मान्यवर, आपकी सदाशयता थी जो आपने कृपापूर्वक इनको सुन लिया। हम विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि इनको सिवाए प्रचार की भूख और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अपने-आप सत्ता में रहकर जो काम स्वयं कर गये उसके लिए हमको दोषी ठहराते हैं इसलिए अगर कोई दोषी है तो वह आप लोग हैं। मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि यह नियम-311 में नहीं आता है और पूरी तरह से यह सूचना अग्राह्य होने योग्य है। आपने चूंकि मुझे बुलाया इसलिए मैंने उसका जवाब दिया अब मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा किसी बात की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हम नहीं समझते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा भी निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप तो बोल चुके हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने मेरा नाम लिया है। बिना रिजर्वेशन के एक भी नियुक्ति हमारी सरकार के समय नहीं होने पायी थी। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं न तो छत्रपति शाहू जी महाराज में और न ही एस0जी0पी0जी0आई0 में।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, 360 पद का मैंने विवरण दिया, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 235 पद हैं। मैं कह रहा हूं कि 105 पद प्रोफेसर के, 140 पद एसोसिएट प्रोफेसर के और असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 115 पद। मान्यवर, यह 360 पद हुए। 360 पद का जो विज्ञापन निकला है उस विज्ञापन पर ही इण्टरव्यू शुरू हुआ। उसमें रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं है तो लागू कब कर देंगे ? क्या उस विज्ञापन पर जो इण्टरव्यू शुरू हुआ है उसे रोक रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 235 पद हैं मेरा कहना है 360 पद हैं। पहली बात, उसमें 04 तारीख से इण्टरव्यू चल रहा है। जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें किसी भी रिजर्वेशन का उल्लेख किसी भी कालेज का नहीं है। क्या मेडिकल कालेजों का जो विज्ञापन निकला है जिसमें न तो आयु सीमा

पर छूट देने का उल्लेख है, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि हम जो अनुमन्य हो पाएगा वह लागू करेंगे इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब 04 तारीख से इण्टरव्यू है, विज्ञापन पहले से निकला है।

श्री अध्यक्ष-

जो अनुमन्य होगा वह करेंगे यह तो कहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

जब विज्ञापन में आपने चर्चा ही नहीं की तो लागू कैसे कर देंगे इसका मतलब है कि यह सदन को गुमराह कर रहे हैं इसलिए इस पर माननीय मंत्री जी पूरा जवाब दे दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो चिट्ठी का हवाला दिया है। मैं आपसे पहले से आग्रह कर चुका हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यू0जी0सी0 दोनों केन्द्र सरकार के अण्डर में रहते हैं। यहां से कोई आर्डर नहीं होता है। शिक्षा विभाग में जो भी जी0ओ0 आता है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय से या यू0जी0सी0 से आता है। अध्यक्ष जी, आप भी यह जानते हैं और हम भी यह जानते हैं कि अगर किसी केन्द्र के आर्डर को कोई स्टेट गवर्नमेण्ट नकारती है तो उस पर उसको भंग करने की तलवार लटकती रहती है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के इस सदन में जो दोनों पत्र आपने दिखाये उसका न तो सपा की सरकार ने संज्ञान लिया और न ही बसपा की सरकार ने संज्ञान लिया, आरक्षण के हिसाब से नियुक्तियां हुईं। जो नियुक्तियां हुईं उसको निकलवा कर देख लीजिए कोई अंधेरे में तो नहीं है लेकिन आपने थोड़ा-सा बहाना लेकर हजारों नियुक्तियां कर ली है। गोरखपुर में भी कर ली, यह चल रहा है, रोडवेज में बैकलॉग हो गया उसमें आरक्षण नहीं जारी हुआ। इलाहाबाद में हो गया हमने तो आरक्षण के बिना भले ही सरकार भंग हो गयी लेकिन हमने उसको लागू नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब तो पूरी बात आ गयी, आपका भी पूरा पक्ष आ गया और इनका भी पूरा पक्ष आ गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें संशोधन होगा, आरक्षण लागू होगा और जो नियमानुसार होगा वह होगा।

श्री अध्यक्ष-

इस पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही है, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो इण्टरव्यू हो रहे हैं उनको रोकेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें संशोधन जारी करके आरक्षण लागू होगा।

[12:59] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-300 की सूचनायें लेते हैं।

पहली सूचना है-श्रीमती संगीता यादव जी की, सदन में विभिन्न नियमों के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के सन्दर्भ में अधिकारियों की उदासीनता के कारण कोई जवाब न दिये जाने के सन्दर्भ में। इस विषय में अगर जवाब समुचित नहीं आता है तो उसके लिए नियमों में व्यवस्था है आप सन्तुष्ट नहीं हैं। भिन्न-भिन्न नियमों में 301 में, 51 में तो आप लोगों ने यहीं पर सदन में एक समिति बनायी है उसे आप भेज सकते हैं।

दूसरी सूचना है मा0 श्री उमाशंकर जी की, 300 में, विधान भवन में स्मोकिंग जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में। पहले भी ये बात कहे थे कि सिगरेट पीने में लोगों को कठिनाई होती है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, पीने में नहीं कठिनाई हो रही है। पिछली बार 30 अगस्त, 2018 को मैंने इस बात को उठाया था। आप उसकी कार्यवाही देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हम तो कह रहे हैं कि उठाये थे।

विधान भवन में स्मोकिंग जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30 अगस्त, 2018 को दी गई सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उमाशंकर सिंह-

आपने उसमें यह व्यवस्था दी थी कि हम दलीय नेताओं के साथ बैठ करके जो असुविधा मा0 सदस्यों को होती है या महिला सदस्यों को लॉबी में जाते समय होती है। अब तो स्थिति यह भी हो जाती है कि इतना स्मोक (धुंआ) होता है कि वह शरीर के अन्दर भी आ जाता है। मैंने कहा था कि इसके लिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए या फिर स्मोकिंग को बन्द कराईये।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर हमारे सदन के भीतर या सदन की लॉबी में तो सिगरेट नहीं पी जा सकती और नहीं पी जानी चाहिए। हां आप अपने घर से पीकर आवें और यहां आवें, मस्ती में आवें, तो अच्छा लगेगा।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने यह भी कहा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा समय-समय पर लोक सभा का भी अनुसरण करता है, तो अगर मा0 सदस्यों का आप ख्याल रखना चाहते हैं, तो स्मोकिंग को बन्द कराइये।

श्री अध्यक्ष-

आप तो पीते नहीं।

श्री उमाशंकर सिंह-

बिल्कुल नहीं, मा0 अध्यक्ष जी। हम नहीं पीते। हमारी महिला सदस्यों को दिक्कत होती है, इसीलिए कह रहा हूं। यह एक अच्छा काम होगा।

[01:01] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

चलिए, इस पर विचार कर लेंगे। नियम-301 के अन्तर्गत आज कुल 44 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें 20 मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं। जिनका विवरण निम्नवत् है :-

आज नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 44 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें 20 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के विकास खण्ड चरखारी के अन्तर्गत बम्हौरी कला इमिलिया सम्पर्क मार्ग में रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य "पप्पू भइया" की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बसे गांवों के तटबन्धों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट की जनपद बहराइच के सरयू नहर खण्ड-5 के अन्तर्गत ग्राम अमदापुर व मल्लव के निकट नहर पट्टी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना डॉ0 जी0एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी के प्रेम नगर, बागराजपुर चुंगी क्षेत्र में नालियों एवं गलियों का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

पांचवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रदेश में आवास विकास परिषद् द्वारा आवास आवंटियों को ब्याज मुक्त समाधान योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

छठीं सूचना डॉ0 अरूण कुमार की उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के पेंशन निर्धारण एवं कैरियर प्रोन्नयन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है,

सातवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या की जनपद मिर्जापुर के ब्लाक सीटी के अन्तर्गत टांडा फाल से निकाली गयी हरई माइनर का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है,

आठवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय मार्गों का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

नवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन रेहड़ी रजबहे के दोनों ओर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

दसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम पंचायत पतेई एमन के मजरों एवं गांवों को गंगा की धारा से बचाये जाने के सम्बन्ध में है,

ग्यारहवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के सफीपुर एवं मियागंज में आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है,

बारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर फण्ड ऐक्ट बनाकर सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक रूप से प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है,

तेरहवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की माननीय विधायकों को विकास हेतु दिये गये 5 करोड़ रुपये के सापेक्ष उनके प्रस्ताव पर विचार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

चौदहवीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली के ब्लाक अमावां अन्तर्गत जिला पंचायत की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

पन्द्रहवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज को नगर पालिका घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है,

सोलहवीं सूचना श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती में खनन माफियाओं एवं खनन अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

सत्रहवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के ग्रीन बेल्ट में कालोनाइजरों द्वारा किये गये अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है,

अट्ठारहवीं सूचना श्री कपिल देव अग्रवाल की मुजफ्फरनगर सदर के गांधी राजकीय पालीटेक्निक में पेपर टेक्नोलाजी का नया विषय प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है,

उन्नीसवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की लखनऊ मेट्रो रेल सेवा का विस्तार लखनऊ विश्वविद्यालय से ए0के0टी0यू0 परिसर तक कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा

बीसवीं सूचना श्री सहेन्द्र सिंह चौहान की जनपद बागपत के ग्राम इब्राहिमपुर मजरा में शमशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

सभी स्वीकृत 20 सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद महोबा के विकास खण्ड चरखारी के अन्तर्गत बम्होरी कलां से इमिलिया सम्पर्क मार्ग में रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भईया-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद महोबा के विकास खण्ड चरखारी अन्तर्गत बम्होरी कलां से इमिलिया सम्पर्क मार्ग में लगभग 15 मीटर रपटा का निर्माण जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है। इस रपटे के निर्माण से क्षेत्रीय जनता को बहुत सुविधा होगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बसे गांवों के तटबन्धों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया''-

[महोदय, जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बसे गांव अक्सर बाढ़ की चपेट में आते रहते हैं इन गांव के किनारे बने तटबन्धों का बनाया जाना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भुंडी परियोजना एवं जोरी नगला परियोजना शासन स्तर पर लम्बित है।

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर गंगा नदी किनारे बसे गांवों के तटबन्धों के मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]**

जनपद बहराइच के सरयू नहर खण्ड-5 के अन्तर्गत ग्राम अमदापुर व मल्लव के निकट नहर पट्टी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-247, पयागपुर, जनपद बहराइच, सरयू नहर खण्ड-5 के अन्तर्गत सरयू नहर गोण्डा ब्रान्च ग्राम अमदापुर व मल्लव के निकट लगभग 500 मीटर नहर

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की पटरी कच्ची है तथा जगह-जगह गड्ढे बन गये हैं, जिससे आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवशेष पक्की नहर पटरी बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी के प्रेमनगर बागराजपुर चुंगी क्षेत्र में नालियों एवं गलियों का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जी0एस0 धर्मेश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी में प्रेमनगर बागराजपुर चुंगी क्षेत्र में नाली एवं गलियों की स्थिति अत्यन्त खराब है। गलियां पूरी तरह कच्ची हैं। जिसके कारण गलियों में कीचड़ भरा पड़ा है। जल भराव होने के कारण क्षेत्र में दुर्गन्ध का आलम है। काफी समय से क्षेत्र की जनता द्वारा जिला स्तर पर काफी प्रयास किये गये परन्तु अभी तक नालियों एवं गलियों का पक्का निर्माण कराये जाने से जनमानस में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नालियों एवं गलियों के पक्का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

प्रदेश में आवास विकास परिषद् द्वारा आवास आवंटियों को ब्याज मुक्त समाधान योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा अल्प आय एवं दुर्बल आय वर्ग के आवंटित आवासों का समय से किश्त जमा नहीं करने के कारण परिषद् द्वारा आवंटियों के आवास पर दण्ड ब्याज भी लगा दिया जा रहा है। किस्त के साथ दण्ड ब्याज बढ़ने के कारण आवंटी न ही अपना मूल धन जमा कर पाता है, न ही परिषद् को समय से राजस्व ही मिल पाता है। पूर्व में पिछली सरकारों ने भवनों पर लगाये गये दण्ड ब्याज माफ किये जाने का प्रस्ताव तो दिया परन्तु विभाग की शिथिलता के कारण दण्ड ब्याज माफ किये जाने का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका जिसके कारण हजारों आवंटी ब्याज के कारण अपना मूल धन भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। भवनों पर लगे दण्ड ब्याज का बोझ इतना अधिक हो जाता है कि आवंटी दण्ड ब्याज के बोझ से उबर नहीं पाता। मूल धन के साथ दण्ड ब्याज न जमा कर पाने की स्थिति में आवंटी के ऊपर भवन के निरस्तीकरण का भय लगातार सताता रहता है। भवन के निरस्तीकरण हो जाने पर आवंटी के द्वारा जमा किये गये समस्त धनराशि को भी परिषद् द्वारा

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जब्त कर लिया जाता है। मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता की सहूलियत के लिए प्राइवेट बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए रेरा जैसा कानून बनाया गया है, जो आवंटियों के हितों की रक्षा करती है। वहीं दूसरी तरफ आवास विकास परिषद् आवंटियों को सुविधा देने के बजाय उल्टे ब्याज के रूप में आवंटियों के ऊपर अतिरिक्त भार डालने का काम कर रही है जो उचित नहीं है। आवास आवंटियों के निरस्तीकरण कार्य में आवास माफियाओं का भी बड़ी भूमिका रहती है ताकि निरस्तीकरण के बाद भवन का एलाटमेण्ट अपने नाम पर करा सकें। आवास आवंटियों पर लगाये गये ब्याज के रूप में अतिरिक्त भार विद्युत बकाया, कृषि ऋण तथा अन्य योजनाओं में सरकार द्वारा लागू की गयी समाधान योजना की भांति आवास विकास परिषद् द्वारा भी आवंटियों को ब्याज मुक्त हेतु समाधान योजना लागू किया जाना आवंटियों के हित में होगा ताकि भवन आवंटी योजना का लाभ लेते हुए अपने समस्त ऋणों के भुगतान की सुविधा प्राप्त कर सकें तथा प्रकरण के निस्तारण तक भवन निरस्तीकरण का कार्य रोका जाना अति आवश्यक है। इससे सरकार एवं भवन आवंटी दोनों को लाभ होगा। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के पेंशन निर्धारण एवं कैरियर प्रोन्नयन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि उ0प्र0 के पुलिसकर्मी प्रदेश की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण पूरी कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कर रहे हैं। इसमें इनके प्राणों का जोखिम होता है एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जोखिम स्वरूप इनके प्राण भी चले जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में उ0प्र0 शासन द्वारा इनके परिवारों को असाधारण पेंशन प्रदान की जाती है। अत्यन्त खेद का विषय है कि ऐसे प्रकरणों में पुलिसकर्मियों की अधिवर्षता तिथि के उपरान्त पेंशन निर्धारण सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए उ0प्र0 सरकार सक्षम है। इससे इनकी विधवाओं को आर्थिक हानि हो रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए असाधारण पेंशन नियमावली में अधिवर्षता तिथि के उपरान्त पेंशन धनराशि निर्धारित करने में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के ब्लाक सीटी के अन्तर्गत टांडा फाल से निकाली गयी हरई माइनर का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां, जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत ग्राम हरई के निवासी हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के सीटी ब्लाक के अन्तर्गत टांडा फाल से निकली हरई माइनर पूर्व में लगभग 50 गांवों की सिंचाई का माध्यम हुआ करती थी। हरई माइनर ब्रिटिश काल में निर्मित हुई थी, जो धीरे-धीरे देखभाल के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गयी है। उक्त माइनर बहुत लम्बे समय से बन्द पड़ी है। उक्त माइनर के क्रियाशील न रहने के कारण क्षेत्र के हजारों किसानों की स्थिति अत्यन्त खराब हो रही है। स्थानीय लोगों द्वारा निरन्तर उक्त माइनर के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की मांग की जाती रही है, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनहित में उक्त माइनर का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय मार्गों का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के बाला के बास से अरेला व आलगढ़ी से कल्याणगढ़ी तक सम्पर्क मार्ग कच्चा है। उक्त मार्ग स्थानीय निवासियों, किसानों, छात्रों एवं व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उक्त मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन रेहड़ी रजबहे के दोनों ओर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र 06-रामपुर मनिहारन (सहारनपुर) के कस्बे रामपुर मनिहारन के बीच से गुजर रहे रेहड़ी रजबहे पर शहरी पुल से देवबंद मार्ग की पुलिया तक लगभग 500 मीटर रजबहे के दोनों तरफ खुले होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थीं। उक्त रजबहे के दोनों तरफ दीवार का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नियम-301 के अन्तर्गत रेहड़ी रजबहे पर शहरी पुल से देवबन्द मार्ग की पुलिया तक लगभग 500 मीटर रजबहे के दोनों तरफ दीवार का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम पंचायत पतेई एमन के मजरों एवं गांवों को गंगा की धारा से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत पतेई एमन का मझरा दारा नगर व ग्राम पंचायत शीशोवाली के मझरे टीकोवाली, मन्दिर वाली, झांगीर वाली, गंगा की धाराओं के बीच में बसे हैं। उपरोक्त गांवों को गंगा की धाराओं के बची से निकालकर सुरक्षित पर बसाने के लिए वन विभाग की भूमि भी उपलब्ध है। भूमि परिवर्तन हो सकता है। जनहित में प्रत्येक वर्ष उपरोक्त ग्राम पंचायतों में होने वाली जनधन हानि से बचाने के लिए उक्त भूमि पर बसाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त ग्राम पंचायतों को होने वाली जनधन हानि से बचाने के लिए गंगा नदी की धारा से बचाकर रिक्त वन विभाग की भूमि पर बसाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के सफीपुर एवं मियांगंज में आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत **सफीपुर व मियांगंज, जनपद उन्नाव में ब्लाक स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) का नया केन्द्र खोला जाना नितान्त आवश्यक है,** यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर **सफीपुर व मियागंज, जनपद उन्नाव में ब्लाक स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के नये केन्द्र खोले जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।**]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर फण्ड ऐक्ट बनाकर सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक रूप से प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय, अधिवक्ता क्लर्क न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। मा0 उच्च न्यायालय में अधिवक्ता क्लर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ता क्लर्क रूल्स 1997 द्वारा संचालित है। जिसके द्वारा उनका पंजीकरण और कंडक्ट क्रियान्वित होता है। इसी प्रकार से मा0 जिला जज के दफ्तर में काम कर रहे अधिवक्ता क्लर्क अपना पंजीकरण जनरल रूल्स (सिविल) में प्रतिपादित व्यवस्था के अन्तर्गत करते हैं। इस प्रकार से कार्यरत अधिवक्ता क्लर्क अपना सारा जीवन बिना किसी उन्नति की व्यवस्था के संयमित होने से कार्य करता है। अधिवक्ता क्लर्क सामाजिक सुरक्षा पाने के अधिकारी हैं जो कि हमारे संविधान में भी प्रतिपादित हैं। जिस प्रकार से हिमांचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि में एडवोकेट क्लर्क वेल्फेयर फण्ड ऐक्ट बनाकर सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक रूप से प्रदान की गयी है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी बनाने की आवश्यकता है जिससे कि अधिवक्ता क्लर्कों का जीवन सुरक्षित हो सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए एडवोकेट क्लर्क वेल्फेयर फण्ड ऐक्ट बनाकर सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक रूप से प्रदान किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

माननीय विधायकों को विकास हेतु दिये गये 5 करोड़ रुपये के सापेक्ष उनके प्रस्ताव पर विचार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पांच करोड़ रुपये का विकास कार्य हेतु कराये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी थी। लेकिन विपक्ष के विधायकों के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। जबकि सत्ता पक्ष के विधायक के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा रही है। जो भेदभाव पूर्ण है।

अतः इस औचित्यपूर्ण प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।]

जनपद रायबरेली के ब्लाक अमावां के अन्तर्गत जिला पंचायत की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री अदिति सिंह-

[महोदय, अविलम्बनीय एवं तात्कालिक विषय पर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, सदर, जनपद-रायबरेली में जिला पंचायत, रायबरेली के अधीन निर्मित सड़कों में से

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकांश सड़कें वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं। बीते 3-4 वर्ष से इनकी मरम्मत नहीं हुई है, जिससे यहां के निवासियों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। **रायबरेली सदर विधान सभा** के **अमावां ब्लाक** के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा निर्मित निम्नलिखित सड़कें : 1-पूरे गुमान सिंह सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 2.500 कि0मी0, 2-खरसिरवा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.350 कि0मी0, 3-हैवतमऊ से कुमारगंज सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.700 कि0मी0, 4-अहमदपुर मौरई से समरदहा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.00 कि0मी0, 5-फकीरन तकिया होते हुए कुडरा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.300 कि0मी0, 6-अमावा से रूकुनपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.800 कि0मी0, 7-रजवापुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 03.400 कि0मी0 वर्तमान में एकदम जर्जर अवस्था में हैं। इन सड़कों से सैकड़ों गांव के लोग प्रतिदिन आते-जाते हैं। जर्जर होने के कारण आये दिन इन पर दुर्घटनायें हो रही हैं। इन सड़कों के निर्माण में किये गये अनुबन्ध तथा विशिष्टियों की जांच कराकर अधोमानक निर्मित सड़क की जांच कराये जाने, निर्माण में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा मानकानुसार मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र जिला पंचायत, रायबरेली द्वारा कराया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने की कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज को नगर पालिका घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला-आजमगढ़ की मेरी विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड-जहानागंज के अन्तर्गत कस्बा जहानागंज की आबादी लगभग बीस हजार से भी ऊपर है, परन्तु वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अत्यधिक अभाव है, क्षेत्रीय जनता ने स्थानीय प्रशासन से कस्बा जहानागंज को नगर पालिका बनाये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया है, परन्तु अभी तक कस्बा जहानागंज को नगर पालिका घोषित नहीं किया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश है, क्षेत्रीय जनता आये दिन कस्बा जहानागंज को नगर पालिका घोषित किये जाने हेतु घेराव एवं सड़क जाम कर प्रदर्शन करती रहती है, किसी भी दिन कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतएव, आपके माध्यम से सरकार से कस्बा जहानागंज को नगर पालिका घोषित किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद श्रावस्ती में खनन माफियाओं एवं खनन अधिकारियों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद-श्रावस्ती में बालू के अवैध खनन मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड-सिरसिया में भैसाही नाला, मसहा कलां, भौव्वानाला, कौव्वापुर, डगमरा नाला, चैलाही, बरगदवा, भुजंगा, सचौली आदि नालों से अवैध बालू खनन का कार्य रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक किया जा रहा है, इसी प्रकार विकास खण्ड-हरिहरपुर रानी के मुजेहना (मोहम्मदपुर कलां) व कलेक्ट्रेट से मात्र 500मी0 स्टेडियम के पीछे व खैरीगलां आदि जगहों पर तहसील के अधिकारियों से मिली भगत एवं खनन इंस्पेक्टर के सहयोग से प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियों से धन उगाही करते हुए बालू निकाला जा रहा है और जरूरतमन्द लोगों को रु0 4000 प्रति ट्राली में बिक्री किया जा रहा है। मौके पर पकड़े गये ड्राइवर एवं उनके लेबर व गाड़ी मालिकों से पूछ-ताछ की गयी तो उन्होंने अपने बयान से स्पष्ट रूप से कहा कि हमको खनन इंस्पेक्टर व तहसील के अधिकारियों को रु0 2000 प्रति ट्राली देना पड़ता है। जिससे हमारी गाड़ी कभी नहीं पकड़ी जाती है और उन्होंने यह भी बताया कि यह लगभग 8 माह से अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। जनपद-श्रावस्ती के जिलाधिकारी को भी तहसील के अधिकारियों द्वारा यही बताया गया कि मिट्टी निकाली जा रही है, जबकि मौके पर बालू का खनन किया जा रहा है। जिससे राजस्व की भारी हानि हो रही है एवं अवैध खनन माफियाओं एवं अधिकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने पर मेरे एवं मेरे परिवार पर जान माल का खतरा बना हुआ है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त अवैध बालू खनन की उच्चस्तरीय जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के ग्रीन बेल्ट में कालोनाइजरों द्वारा किये गये अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 120-भोजीपुरा, जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली बड़े बाईपास (एन0एच0-24) के किनारे बी0डी0ए0 व एन0एच0आई0 के अधिकारियों की मिली-भगत से ग्रीन बेल्ट में कालोनाइजरों द्वारा अवैध कब्जे किये गये हैं, जिन्हें हटाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर सदर के गांधी राजकीय पॉलीटेक्निक में पेपर टेक्नोलॉजी का नया विषय प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के गांधी राजकीय पॉलीटेक्निक में छात्रहित एवं जनहित में पेपर टेक्नोलॉजी का नया विषय प्रारम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जनपद में बहुत सारे पेपर मिल संचालित हो रहे हैं और आगामी भविष्य में उक्त विषय छात्रों एवं मिलों के हित में होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

लखनऊ मेट्रो रेल सेवा का विस्तार लखनऊ विश्वविद्यालय से ए0के0टी0यू0 परिसर तक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नीरज बोरा-

[महोदय, लखनऊ मेट्रो रेल सेवा के द्वितीय चरण में चारबाग से मुंशी पुलिया तक का निर्माण कार्य चल रहा है। राजधानी के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय नया परिसर, आई0आई0एम0 तथा ए0के0टी0यू0 जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में शिक्षारत हजारों छात्र-छात्राओं तथा दैनिक यात्री मेट्रो रेल सेवा का लाभ उठाने से वंचित रहेंगे। जनहित में लखनऊ मेट्रो रेल सेवा का विस्तार लखनऊ विश्वविद्यालय से ए0के0टी0यू0 परिसर किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के तहत लोक महत्व के इस विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के ग्राम इब्राहिमपुर माजरा में श्मशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

[महोदय, जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के गांव में इब्राहिमपुर माजरा में श्मशान घाट नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात है कि एक सज्जन की मृत्यु हो गयी। गांव में श्मशान न होने के कारण घर में लाश तीन दिन पड़ी रही क्योंकि बरसात के दिन थे। तीन दिनों बाद लाश को खेतों में जलाया गया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः महोदय उपरोक्त हालत को देखते हुए गांव में एक श्मशान घाट की बहुत जरूरत है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय, तात्कालिक विषय पर सदन में चर्चा करवाकर इसका समाधान किया जाये।]

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

एक सूचना दी थी, उसको स्वीकार कर लीजिए, वह महत्वपूर्ण है। ध्यानाकर्षण करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कल दे दीजियेगा। आज ही कहे देते हैं कि कल आपका स्वीकार हो जायेगा।

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

20 सूचनायें हो गयीं।

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

एक ध्यानाकर्षण करा दीजिये। आपको अधिकार है, अध्यक्ष जी। बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष जी। निवेदन कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आगे स्वीकार कर लेंगे। अब घोषित कर दिया।

[01:04] उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का दशम् प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का दशम् प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2011-2012 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम लि0 से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का ग्यारहवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का ग्यारहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-

† छापा नहीं गया।

महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 (वाणिज्यिक), में उल्लिखित दक्षिणांचल विद्युत निगम लि0 से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का बारहवां प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का बारहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2009-2010 (वाणिज्यिक), 2010-2011 (वाणिज्यिक), 2011-2012 (वाणिज्यिक) एवं 2012-2013 (वाणिज्यिक), में उल्लिखित उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन निगम लि0 से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का तेरहवां प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का तेरहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक), 2006-2007 (वाणिज्यिक), 2007-2008 (वाणिज्यिक), 2008-2009 (वाणिज्यिक) एवं 2014-2015 (वाणिज्यिक), में उल्लिखित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का चौदहवां प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का चौदहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 (वाणिज्यिक), 2007-2008 (वाणिज्यिक), 2009-2010 (वाणिज्यिक) एवं 2014-2015 (वाणिज्यिक), में उल्लिखित उ0प्र0 कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लि0 से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-

† छापा नहीं गया।

महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1992-1993 (वाणिज्यिक), में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का सोलहवां प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का सोलहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक) एवं 2006-2007 (वाणिज्यिक), में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य यार्न कम्पनी लि0 से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

(इसी समय 01 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का सत्रहवां प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का सत्रहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997-1998 (वाणिज्यिक) एवं 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टवर्ष 2014-2015 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का उन्नीसवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का उन्नीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-

† छापा नहीं गया।

महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2015-2016 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का बीसवां प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का बीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-1999 (वाणिज्यिक) एवं 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का इक्कीसवां प्रतिवेदन †

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2017-2018) का इक्कीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1980-1981 (वाणिज्यिक), 1994-1995 (वाणिज्यिक) एवं 1996-1997 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

[01:12] उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-2018) का 143वां प्रतिवेदन †

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-2018) का 143वां प्रतिवेदन जो माध्यमिक शिक्षा, नगर विकास, लोक निर्माण, आवास, बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, गृह (पुलिस), खाद्य एवं रसद, पंचायती राज, कार्मिक, सहकारिता तथा मुख्य मंत्री प्रकोष्ठ विभागों के वर्ष 1997 से 2017 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 144वां प्रतिवेदन †

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 144वां प्रतिवेदन जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आवास एवं शहरी नियोजन, कर एवं निबन्धन, खादी एवं ग्रामोद्योग, कृषि विपणन एवं व्यापार, पर्यटन, सिंचाई, ऊर्जा,

† छापा नहीं गया।

परिवहन, समाज कल्याण तथा राज्य सम्पत्ति विभागों के वर्ष 2013 से 2017 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

[01.04] श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित नौ याचिकायें †

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से

(1) जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम बरैंचा से कैमुआ नाला के किनारे ग्राम हटादलेलपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम पचदेवरा से खिरिया रसूलपुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग को डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम मदारीपुर से रामपुर नया गांव तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम हमजापुर से महोलिया तक पक्के जर्जर गड्ढायुक्त मार्ग का निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत लिपोलिक भिंड मार्ग शाहजहांपुर पीलीभीत स्टेट हाई-वे पर निगोही में कैमुआ नाला पर सकरा पुल का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम विरासिन से खलीलपुर गौटिया तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेदपाल मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम हमजापुर व ग्राम डींग के मध्य कैमुआ नाला पर छोटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम रतूली से ग्राम रटी तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर डडिया तिराहे से सुनरा होते हुए भटपुरा तक पक्के जर्जर गड्ढायुक्त मार्ग का निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामा चरन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' के सदन में उपस्थित न होने पर)

[01:17] श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका स्थगित हुई †

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में ग्राम सभा अहिरौलीदान, पिपराघाट, रामपुर बरहन तथा ग्राम सभा-पिपराघाट एहतमाली फल टोला, पो0 पिपराघाट एवं ग्राम सभा तिवारी पट्टी कान्ही टोला, पोस्ट गौरी जगदीश, विकास खण्ड-दुदही, थाना सेवरही के लोगों का घर बाढ़ में विलीन हुए ग्रामवासियों को विस्थापित करने के सम्बन्ध में श्री व्यास कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

यह मद स्थगित रहेगी।

[01:17] श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका †

श्री सत्यवीर त्यागी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम अटौला, ब्लाक खरखोंदा में काली नदी का पानी आने से रास्ता बन्द होने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

† छापी नहीं गयी।

[01:18] श्रीमती लीला तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका †

श्रीमती लीना तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जौनपुर के 370 विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड रामपुर में नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूं।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका †

श्री राम फेरन पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद श्रावस्ती में गिलौला बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार पाठक व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद सं0-23, 24 व 25 में कुछ नहीं है।

भूलवश श्री मनीष असीजा द्वारा अपना संकल्प प्रस्तुत किया जाना

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग में गर्म कांच की भट्टियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अभी मद संख्या-26 लेना है, आप आगे चले गये हैं। अभी मा0 राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। श्री असीजा जी का नम्बर इसके बाद है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, श्री असीजा जी मा0 राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोल रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने अपना प्रस्ताव/संकल्प रखा है, मा0 राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर कहां बोल रहे हैं ? कल सत्ता पक्ष के दो लोग बोल चुके थे, आज विपक्ष का नम्बर था। मा0 राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा आज विपक्ष से शुरू कराइये।

श्री अधिष्ठाता-

श्री वर्मा जी, अब श्री मनीष असीजा जी को बोल लेने दीजिये, उसके बाद आप बोल लीजियेगा।

[01:20] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा †

*** श्री मनीष असीजा-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैंने भूलवश इस संकल्प को पढ़ दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में श्री सुनील शर्मा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री उज्जवल रमण सिंह ने दो-तीन बार आग्रह किया था कि तर्को सहित बात रखी जाये। सामाजिक क्षेत्र के विषय में कुछ तथ्यों पर बोलना चाहता हूं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अन्तर्गत कोई भी सत्ता हो, चाहें वह गांधीवादी/अम्बेडकर/दीनदयाल उपाध्याय या लोहियावादी भाव के हों, अपने आप में सबका एक ही भाव हैं, एक ही रास्ता है, लेकिन इन सबका उद्देश्य है, कमजोर तबकों का कल्याण। सरकार के बहुत सारे कार्यों में परफैक्शन भी है, कानून-व्यवस्था भी है, राजस्व का संग्रहण भी है। इनके साथ-साथ अपने प्रदेश के कमजोर, वंचित, शोषित वर्गो का ध्यान रखना है। पूरा सदन जानता है कि कमजोर, बीमार या किसी कारण से विकसित न हो पाने वाले बच्चे की अपेक्षाकृत पले-पलाये, हट्ठे-कट्ठे बच्चे की परवरिश आसान होती है। हमारे विपक्ष के लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को झूठ का पुलिन्दा कहा, लेकिन एक बात मुझे देखने में लगा कि मा0 नेता विपक्षी दल कहीं न कहीं मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण से पूरी तरह सहमत हैं और सहमत होने के कारण उनका मन ही नहीं करा कि वह कुछ बोलें, लेकिन विपक्ष के साथियों ने उनकी वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखा और जबर्दस्ती श्री उज्जवल रमण सिंह ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की आलोचना की। अगर वह मा0 नेता विपक्षी दल की भावनाओं से सहमत हो जाते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं, जैसाकि श्री उज्जवल रमण सिंह ने कहा था। कोई भी समाज का व्यक्ति अगर कहीं चिकित्सा की सुविधा मिलती है तो वहां जरूर अपनी परेशानी दूर कराने के लिए जाता है। पिछले वर्षों 2015-16 और 2016-17 के समाजवादी पार्टी की सरकार के आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश हेल्थ मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (यू0पी0एच0एम0आई0एस0) के माध्यम से हैं, जिनका हमारे विपक्ष के साथी इसका अध्ययन कर सकते हैं। 11 करोड़ 46 लाख लोग अपना इलाज कराने के लिए 2015-16 में गये थे, 13 करोड़ 25 लाख लोग 2016-17 में गये थे और जैसे ही माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो ये आंकड़ा सीधे-सीधे 14 करोड़ 25 लाख हो गया। अभी फरवरी का महीना भी पूरा नहीं हुआ है, मार्च तक यह संख्या 15 करोड़ तक होने वाली है। अगर आप यह देखें तो समाजवादी पार्टी से डेढ़ गुना लोगों को चिकित्सा सुविधा में फैसिलियेशन हो रहा है। यही आंकड़ा आई.सी.डी. के साथ

---

† दिनांक 06 फरवरी, 2019 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी है जिसमें भर्ती होकर इलाज कराने की स्थिति है। इसमें आप यह समझिये कि 52 लाख 2015-16 में थी और 59 लाख 2016-17 में थी वही आंकड़ा बढ़कर माननीय योगी जी की भा0ज0पा0 नेतृत्व वाली सरकार में 66 लाख 32 हजार हो गयी है और इस वर्ष लगभग 70 लाख होने की स्थिति बन रही है। महोदय, इस स्थिति के साथ ही 'आयुष्मान भारत' की योजना लागू है। 2011 के सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना की सूची के आधार पर, यह जो सूची है यह पिक-एण्ड-चूज की नहीं है। लेकिन अनेक लोग जो बच गये हैं उनकी हम सब लोगों को चिंता थी। तो मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे हमारे सामान्य या गरीब नागरिकों को 'मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना' के लिये हमारी सरकार ने 111 करोड़ रुपये के बजट का भी प्राविधान किया है और इससे मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा रहेगा जहां पर पैसे के अभाव में किसी को भी, चाहे वह किसी भी राजनीतिक, किसी भी जाति-धर्म से सम्बन्ध रखता हो, इलाज से वंचित होना पड़े।

मान्यवर, मैं एक आंकड़ा और रखना चाहता हूं। कोई भी माननीय मुख्य मंत्री होते हैं वह निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में सभी के लिए उदार दृष्टि रखते हैं, ऐसा अपना विचार है। लेकिन कुछ आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से आदरणीय योगी जी ने पिछली सरकार की तुलना में असाध्य रोग से पीड़ित, कैंसर, किडनी, गुर्दा रोग से पीड़ित जो गरीब नागरिक हैं उनके लिए किस प्रकार से मदद की।

मान्यवर, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में 05 साल में 42506 लोगों को माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से इलाज के लिए सहायता मिली थी और यही हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में अभी 01 साल 10 महीने बीते हैं जिसमें मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 28 हजार लोगों को यह मद्द हम दे चुके हैं और 210 करोड़ रुपये की धनराशि इसमें व्यय हुई है। यह इस सरकार की, माननीय मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता है। इसके साथ-साथ जैसा अभी मैं सुन रहा था, एस0सी0/एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के ऊपर भी काफी चर्चा चली। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सामान्य आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं जिससे यह साबित होगा कि जैसाकि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि यहां कहने में और करने में कितना बड़ा अंतर है। 2015-16 में ओ0बी0सी0 श्रेणी में हम लोगों ने 6.5 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति दी। मेरे पास इसके आंकड़े हैं अगर विपक्ष के साथी कहेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। 2015-16 में 10 लाख 44 हजार, 2016-17 में 12 लाख 43 हजार ओ0बी0सी0 की संख्या थी, वह 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मा0 योगी जी के नेतृत्व में सीधे बढ़कर 18 लाख 80 हजार की संख्या हो गयी। इसी प्रकार से अगर हम एस0सी0, एस0टी0 में देखते हैं, माननीय लालजी वर्मा जी यहां बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि एस0सी0 एस0टी0 में 2016-17 में जो

छात्र संख्या थी वह 31 लाख 81 हजार की थी और 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह संख्या बढ़कर 41 लाख 23 हजार 498 हुई। मान्यवर, इसी तरह से जो स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की जो धनराशि है उसकी अगर हम तुलना करें तो 490 करोड़ रुपया अधिक माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन छात्रों के कल्याण के लिए दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस आधी आबादी के लिए आज सब जगह पर चिन्ता है और यह लगातार महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक बातें रखी जाती हैं मैं उसका कुछ आपके सामने हाल रख देता हूं उज्जवल रमण सिंह जी का अनुरोध था कि आंकड़ों सहित रखें, तो मैं आंकड़ों के सहित रखना चाहता हूं। मान्यवर 2015-16 में समाजवादी पार्टी की सरकार में 17 लाख 28 हजार निराश्रित ऐसी महिलायें थीं जिनको विधवा पेंशन की सुविधा दी जा रही थी। जो 2016-17 में 17 लाख 31 हजार थीं, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो यह आंकड़ा बढ़कर 19 लाख 36 हजार और 2018-19 में 21 लाख के आस-पास हो गया। इसी के साथ-साथ आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में, किसी भी विधान सभा में, किसी भी क्षेत्र में, अपना पराया छोड़कर कैंपों के आधार पर उन लोगों का चयन किया जा रहा है। मान्यवर, इसी के साथ-साथ जो वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना जो अभी हाल ही में हमारी सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें एक बेटी को जन्म से लेकर उसके स्वास्थ्य की चिन्ता फिर उसकी बारहवीं कक्षा, फिर उसके ग्रेजुएशन तक 16 हजार रुपया दिए जाने का काम किए जाने वाला है यह अपने आप में बेटियों को बहुत प्रोत्साहित करने वाला है हमारी आधी आबादी को शक्तिशाली बनाने वाला है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर जहां पिछली सरकारों में गरीब बेटियों की शादी के लिए बीस हजार रुपया दिया जाता था सहयोग के लिए, वह राशि 2014-15, 2015-16 में पिछली सरकारों में दी नहीं गई लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में वह राशि बीस हजार से बढ़ाकर 51000 रुपये कर दी गई। जिसमें 33 हजार रुपया सीधे-सीधे बेटी के खाते में जाएगा। दस हजार का उसको सामान मिलेगा और 6000/- रुपया उसके दावत बगैरह में खर्चा होगा। अधिष्ठाता महोदय, दिव्यांग जन, मैं समझता हूं समाज की सबसे अन्तिम सीढ़ी पर, सबसे अधिक आवश्यकता के लिए खड़ा हुआ वर्ग है। पिछली सरकार और हमारी सरकार के आंकड़ें देखें, मैं संक्षिप्त में करता हूं तो 2015-16, 2016-17 की तुलना में, 2017-18 में एक लाख दिव्यांगजनों की पेंशन, पात्रता बढ़ी है उस पेंशन को माननीय योगी जी के नेतृत्व में 300/-रुपये से बढ़ाकर 500/- रुपये कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिए।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह लगातार बातें आती हैं कि हमारी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं या जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बोला जा रहा है वह झूठ का पुलिन्दा है, तो आरोप-प्रत्यारोप के आलोक में हमारे पास केवल एक ही रास्ता रहता है वह है भौतिक स्थिति, तो भौतिक स्थिति के रूप में, मैं आपको एक भूमिहीन या आवासहीन लोगों के लिए किस प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में, किस प्रकार देश के माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में, भूमिहीन और आवासहीन लोगों के लिए काम हुआ है, मैं समझता हूं कि यह शब्द इनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह पहली बार हुआ है। अगर यह आज भी करा हुआ मान लें तो मैं इन सबका बहुत आभार प्रकट करूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं पिछली पांच साल की समाजवादी पार्टी की सरकार में शहरी क्षेत्र में गरीबों के लिए कुल 21 हजार 408 मकान बनाए गए आसरा योजना में और उसमें से 11346 ही आवंटित किए गए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कृपापूर्वक 5 मिनट का और समय चाहता हूं। हमारे बसपा के साथी बैठे हुए हैं, यह जरूर ध्यान देंगे कि 2007 से 2012 तक इनके 5 साल के कार्यकाल में काशीराम आवास 1 लाख 57 हजार सेंक्शन हुए और 1 लाख 34 हजार 822 एलॉटेड हुए। यह भी एक तथ्यात्मक बात है और मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 8 लाख आवास और 1 लाख 28 हजार भूमिहीन आवास कुल साढ़े 9 लाख के आस-पास आवास स्वीकृत हो चुके हैं और पहली किश्त जो 50 हजार की दी जाती है, वह 1 हजार 34 करोड़ रु0 की मद में 2 लाख 6 हजार लोगों को 50 हजार रु0 दी जा चुकी है। इसके साथ-साथ इसकी दूसरी किश्त डेढ़ लाख रुपये की होती है, यह 1 लाख 31 हजार लोगों को 15 सौ 90 करोड़ रु0 सरकार के द्वारा दिया जा चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप बैठ जायें। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तीसरी किस्त में 23 हजार लोगों को 50 हजार रु0 दिये जा चुके हैं। 115 करोड़ और 1 लाख 15 हजार मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे करके

एक साल 10 महीनों के अन्दर दिये जा चुके हैं, जो इन लोगों ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में किया। मैं अपने साथियों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि मैं शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना की आपको एक बानगी देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिर्फ आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहता हूं कि वह जाकर देखें और यदि कहीं न दिखे तो मेरे जनपद फिरोजाबाद में आकर देखें। अगर आप संतुष्ट हो जायेंगे, मेरी बात को सही मानेंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके परिवार के लिए चूड़ियां भेंट करूंगा और इसके साथ-साथ एक बार फिर मुझे इस बात की तीव्र वेदना है। नेता विपक्षी दल सहमत हो रहे थे कि यह अभिभाषण बिल्कुल सत्य है, लेकिन विपक्ष के साथियों ने जबरदस्ती उनसे यह भाषण छीनकर पढ़ा है, उसके लिए भी मैं उनके लिए सहानुभूति रखता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सत्तापक्ष और विपक्ष से अनुरोध है कि यदि आप लोग समय का ध्यान रखेंगे, उस पर जिद नहीं करेंगे तो सभी को बोलने का अवसर मिल सकेगा। अब मैं डॉ0 संग्राम यादव जी को आमंत्रित करता हूं।

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारे नेता विरोधी दल श्री रामगोविन्द सिंह चौधरी द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण जो सरकार चल रही है, जो तत्कालीन सरकार है, उसकी दृष्टि क्या है, उसका विस्तृत दस्तावेज हुआ करता है। इस विशाल उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, पिछड़े, दलित, कमजोर, उपेक्षित तबके के लोगों की निगाहें महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर टिकी हुई थीं। उन्हें उम्मीद थी कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उनकी समस्याओं के बारे में, उसके निदान के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण रखा गया होगा, लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ कि इतने बड़े कृषि प्रधान प्रदेश में, जहां किसानों की हालत पर कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण आज वह किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं जनपद आजमगढ़ से आता हूं, वहां बड़े पैमाने पर गन्ने की पैदावार होती है। वहां पर हमारे नेता मा0 श्री अखिलेश यादव जी ने सहकारी क्षेत्र की बहुत बड़ी चीनी मिल स्थापित की थी। किसानों ने बड़े पैमाने पर वहां गन्ना पैदा करना शुरू किया था, लेकिन आज

हालात इस तरह के व्याप्त हो गये हैं कि किसान पर्ची के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मिल की उदासीनता के कारण आज किसानों के अन्दर क्षोभ है, दर्द है। जब हम क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो किसान बार-बार पर्ची के लिए हम सबसे अनुनय विनय करते हैं जब हम इसकी सूचना ऊपर लेबिल तक देते हैं तो एक आंकड़ा प्रस्तुत करके हमारी समस्याओं को टालने का प्रयास किया जाता है। बड़े पैमाने पर सरकार प्रचारित कर रही है हमें तो इलाहाबाद पढ़ने का भी अवसर मिला, एक लम्बे अन्तराल तक आज भी इलाहाबाद का निवासी हूं कहीं न कहीं वहां पर निवास भी करता हूं मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री बनने का भी अवसर मिला था। लेकिन जो वहां कुंभ है अर्ध कुम्भ है अभी कल ही जब बोल रहे थे सत्ता पक्ष के साथी ग्रहों के मिलने के कारण बृहस्पति से लेकर मकर से लेकर उल्लेख करते, प्रमाणित करते थे। हमारे ऋषियों मुनियों की सदियों की परम्परा निर्मल गंगा स्वच्छ गंगा की परम्परा हमारे नेता और देश के लोग कहते थे कि अजीब देश है, विशाल देश है, गौरवशाली देश है, जहां दो नदियां आपस में मिलती हैं गंगा अपने आपको यमुना में समर्पित करती है और यमुना अपने आपको गंगा में समर्पित करती है बीच से एक धारा पैदा होती है जिसे वहां के लोग कहते हैं कि सरस्वती की धारा है, ज्ञान की धारा है, विद्वता की धारा है तीनों के मिलने पर एक विशाल विहंगम दृश्य उपस्थित होता है। सदियों से युग युगान्तर से लोग उसी गंगा के संगम पर आते हैं और अपने परिवार के लिए मोक्षदायिनी गंगा मां से यह प्रार्थना करते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र और प्रदेश की सरकार उस कुदरत के अनमोल खजाने को ऐसा प्रस्तुत कर रही है जैसे पहली बार धरती पर कुम्भ अवतरित हुआ है। जैसे पहली बार कुंभ का आयोजन हुआ है कुछ सदस्य तो ऐसे कह रहे थे हमें तो लगता था कि जैसे वह पहली बार कुंभ गए हों। अब सब तो न जाने कितनी बार गए आज भी गए मौनी अमावस्या से लेकर जो अभी स्नान हुआ है, मौनी अमावस्या का उसमें जाने का अवसर मिला। आप इतिहास उठाकर देख लें चाहे जिसकी भी सरकार रही हो और हमारे जो पुराण हैं उसमें उल्लेख था कि को कहि सकै प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजन मृदुराऊ। प्रयाग की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। पूरी धरती पूरे आसमान को लेखनी बना दी जाए।

मान्यवर, अजीब विडम्बना है आज जहां बेकारी की चर्चा होती, नौजवानों को रोजगार की चर्चा होती जहां महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात की चर्चा होती कि उत्तर प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कोई ऐसा विश्वविद्यालय बनता जिस विश्वविद्यालय की पूरे देश और दुनियां में चर्चा होती। वहां से निकलकर नौजवान वहां से पढ़ लिखकर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होता और समृद्ध भारत के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता। आज उस पर चर्चा नहीं है। आप चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाते विश्व लेबिल के विश्वविद्यालय बनाते हम उसका स्वागत करते लेकिन मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विश्वविद्यालय देश में स्थान रखते थे आज उनकी दुर्दशा हो रही है। आज वह विश्वविद्यालय और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, लोक सेवा

आयोग हो, उच्च शिक्षा आयोग हो, आज उसके हालात कहां से कहां चले गए। उच्च शिक्षा आयोग के चेयरमैन पालीवाल साहब ने इस्तीफा दे दिया। माध्यमिक आयोग एक भी वैकेंसी नहीं निकाल पाया बड़े दुख के साथ आपके सामने कहना पड़ रहा है जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में कराई गई सारी की सारी परीक्षाओं का पेपर आउट हो गया। एक भी परीक्षा में इण्टरव्यू कराकर नियुक्ति का प्रमाण-पत्र किसी के हाथ में देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं किया गया। आप माध्यमिक आयोग को देख लीजिए हमारे बहुत जिम्मेदार मंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के हालात बद से बदतर हैं। उठाइए आप गोरखपुर विश्वविद्यालय, उठाइए काशी विद्यापीठ, उठाइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उठाइए कानपुर विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों के अन्दर तेरह प्वाइंट रोस्टर बनाकर पिछड़े व दलित नौजवानों को जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते, प्रोफेसर बनते उस शिक्षा के दरवाजे हमेशा-हमेशा के लिये आपकी सरकार में बन्द कर दिये गये। जब हम सब बाते करते हैं तो आप कहते हैं कि 'सबका साथ सबका विकास'। कहां हम सबका साथ ले रहे हैं। हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी आज दर्द महसूस कर रही है। यह बापू का देश है। बापू के देश में आज आप भेदभाव कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमनें स्वच्छता अभियान चला दिया। आपने इलाहाबाद के अन्दर क्या हालात पैदा कर दिये हैं। जो गरीब था, कमजोर था, लाचार था और उसके पुर्खे बरसों-बरस उस गंगा की निर्मल धारा में आते थे, लेकिन आपने उनको 40 किलोमीटर पहले रोक दिया। वह धर्म की तपस्या करने के लिये आते हैं, लेकिन आपने कुछ लोगों को धर्म का इन्ज्वॉय करने के लिये वहां पर टेंट सिटी की स्थापना करा दी और उस टेंट सिटी में 30 हजार, 35 हजार, 19 हजार, 11 हजार और 05 हजार के रेट पर यह कौन से लोग हैं जो उस टेंट सिटी में तपस्या कर रहे हैं। आप जरा उसको भी तो देख लें।

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो मेम्बर नियुक्त किये गये हैं उसमें एक भी मेम्बर पिछड़े और दलित समाज का नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर चाहे वह थाने हों, चाहे वह बड़े-बड़े पद हों, किसी भी बड़े पद पर आज इन वर्गों की घोर उपेक्षा हो रही है। यह बात हम नहीं कहते, आपकी सरकार में केन्द्रीय मंत्री जो दिल्ली में बैठे हैं, उन केन्द्रीय मंत्री ने बनारस के अन्दर प्रेस के सामने कहा कि 50 परसेंट थानों में दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्ति होनी चाहिये। हम यह नहीं कहते, लेकिन आपके कैबिनेट मंत्री ने कल ही प्रेस कांफ्रेंस में कहा चाहे महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बजट भाषण हो, उत्तर प्रदेश के लोग इसमें अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप कौन सी व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं ? अरे, आप बड़ी तेजी से एक्सप्रेस-वे, एक्सप्रेस-वे कहते हैं, लेकिन हमें फक्र है, गर्व है कि इस एक्सप्रेस-वे को बनाने का काम अगर किसी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अन्दर किया है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक का आगरा एक्सप्रेस-वे इस उत्तर प्रदेश ने अपनी खुली

आंखों से देखा था और उस पर लड़ाकू विमान उतार करके 23 महीनों के रिकार्ड समय में वह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित करने का काम किया था और दूसरा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश की विधान सभा में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने हम सब गवाह हैं कि मा0 अखिलेश यादव ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी थी और केवल आधारशिला ही नहीं रखी थी, 80 परसेंट से ज्यादा किसानों के मुआवजे का भुगतान भी करने का वायदा किया था। आज आप गंगा में नहा लो, बराबर नहा लो, पूरी कैबिनेट नहा ले, लेकिन इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता कि इसी उत्तर प्रदेश के अन्दर बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज में मासूम ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करिये।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, ऑक्सीजन के अभाव में मासूम दम तोड़ देता है और नौजवान रोजगार के अभाव में दर-दर ठोकर खाता है। आप चाहे जितना भी प्रचार कर लें, चाहे जितना भी आडम्बर पैदा कर लें, आप कहते हैं, आपकी तरफ के लोग मिलते हैं और कहते हैं गठबन्धन-गठबन्धन। आपको आखिर गठबन्धन से ऐसा कौन सा डर पैदा हो गया है ? कल यह कहा गया कि यह महामिलावट है तो बताएं कि 48 दलों की मिलावट आपने की तो हमें कहीं दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब दो ही दल मिल गए और दिल मिल गए तो आखिर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो गयी ? अगर आप इतने अच्छे थे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें। मा0 हरगोविन्द भार्गव जी, आप बोलना प्रारम्भ करें।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, आप समय देख लें। केवल दो मिनट और बोल लूं उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। अगर आप इतने अच्छे थे और उत्तर प्रदेश के अन्दर आपने इतने ही चमत्कारिक काम कर दिये तो आप गोरखपुर में क्यों हार गये ? आप फूलपुर में क्यों हार गये ? आप कैराना में क्यों हार गये ? मान्यवर, इतना ही नहीं, जहां यह कुम्भ का आयोजन कर रहे हैं वहां भी यह हारे हैं। वहां जो विश्वविद्यालय बना है वहां भी हारे हैं और इनकी हार का सिलसिला अब जीत में बदलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता मा0 अखिलेश यादव का इंतजार कर रही है। हमारा गठबन्धन, यह दलित-पिछड़ों का गठबन्धन, गरीबों का गठबन्धन ऐसे अहंकारी लोगों का आने वाले दिनों में क्या हश्र करेगा, वह आज सर्वविदित है और उससे यह लोग विक्षिप्त हो गये हैं, तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं। मान्यवर, जो 48 दलों से गठबन्धन कर लिए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने दूसरे मा0 सदस्य को बुला लिया है, अब आप बैठिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है और महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण नौजवानों के सपनों को चकनाचूर कर रहा है, किसानों के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है और अटेवा के लोग आज आन्दोलन कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के और सरकार उनके आन्दोलन को पुलिस के बूटों के तले दबाने का प्रयास कर रही है। आज उत्तर प्रदेश और देश के लोग बहुत निराशाजनक वातावरण में अपने को महसूस कर रहे हैं। महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण हमें उम्मीद थी कि कोई आशा का संचार करता लेकिन महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में घोर निराशा है। इसी के साथ मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, कल तो उधर से लोग बहुत बोल रहे थे, बहुत बड़ा समय भी लिया और कुम्भ के बारे में बताया कि वहां एल0ई0डी0 लगी हैं, उसकी लाइट दूधिया है, बड़े प्रेम से सुना गया। लाइट दूधिया तो हो ही जायेगी, एल0ई0डी0 है तो। पहले भी लगता था, बहुत बड़ा लगता था, टेण्ट भी लगता था लेकिन मान्यवर, संगम पर किसी नेता की तस्वीर नहीं लगती थी। पं0 नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने लिखा था कि 'गंगायो दर्शनाय पापं मुक्ति भवः' आज कपड़ा बदलने जाओ तो किसी नेता की तस्वीर, शौचालय जाओ तो किसी नेता की तस्वीर, वहां के खम्भों पर नेता की तस्वीर। कुम्भ को राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसको सनातन हिन्दू कभी भी क्षम्य नहीं करेगा और इलाहाबाद के अन्दर एक कहावत है, 'जिन्होंने कुम्भ के साथ बेईमानी किया है, वह कभी फलते-फूलते नहीं हैं' और मुझे खुशी है कि वहां के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, महन्त श्री नरेन्द्र गिरि ने हमारे नेता श्री अखिलेश यादव को निमंत्रित किया है और वहां के साधु-सन्तों ने निमंत्रण दिया है कि आयें, जो भव्य कुम्भ का आयोजन उन्होंने किया था, उसके लिए उनका अभिनन्दन करना चाहते हैं। मान्यवर, आपको धन्यवाद देते हुए, नेता विरोधी दल, श्री राम गोविन्द चौधरी के रखे हुए संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं, इस शेर के साथ कि 'तुमने समझा नहीं यह हालत बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे उस झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर तक जाते।।', बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, कई लोगों ने श्री राज्यपाल के इस अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बोला है। मान्यवर, कानून-व्यवस्था में सबसे पहली लाइन लिखी है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कि 'प्रदेश की कानून-व्यवस्था में आशातीत सुधार

हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी को कोई भय नहीं है। महिलाओं को रात में भी घर से निकलने में कोई डर नहीं लगता।' मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आपके लखनऊ शहर की घटना है। यह 25 जनवरी, 2019 की घटना है। एक लड़की जो थाना-बक्शी तालाब, ग्राम-भौली की रहने वाली मोहिनी रावत पुत्र मंशाराम रावत, अपने घर से बक्शी तालाब कस्बे सिलाई और कढ़ाई के सर्टीफिकेट लेने आयी थी और वह 2:00 बजे दिन में बक्शी तालाब कस्बे से गायब हो गयी। मान्यवर, क्या यही कानून-व्यवस्था है ? दिन में दो बजे बच्चियां उठायी जा रही हैं, क्या मान्यवर, यही कानून-व्यवस्था है। मान्यवर, दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जनपद लखनऊ की तहसील सरोजनी नगर में एक गांव पड़ता है सिवरी, उस सिवरी गांव में एक अनुसूचित जाति की महिला, श्रीमती मीना कुमारी पत्नी हरिश्चन्द्र ने एक बिस्वा का प्लाट लिया और आज के हालात मान्यवर यह हैं, उसकी सूचना 100 नम्बर पर भी दी गयी, उसकी सूचना एस0ओ0 काकोरी को भी दी गयी और उसकी सूचना एस0डी0एम0 सरोजनी नगर को भी दी गयी, लेकिन माफियाओं के आगे आज भी किसी की चल नहीं रही है। शिवरी गांव के दबंग माफिया मनोज गुप्ता ने उस दलित महिला की जमीन पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाने का प्लान तैयार कर लिया है और एक मंजिल की छत भी डाल दी है। मान्यवर, क्या यही कानून व्यवस्था है कि दलित समाज के लोगों की जमीनों को दंबंग माफिया मनोज गुप्ता जैसे लोग आज भी छीन रहे हैं तो कानून व्यवस्था में परिवर्तन कहां से आ गया है ? पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितनी घटनाएं हम गिना सकते हैं, लेकिन आप हमें उसके लिए समय नहीं देंगे। इसीलिए दूसरे विषय पर हम बात करते हैं। आज हमारे गन्ना मंत्री जी नहीं हैं, नहीं तो मैं पूरी बात उनके सामने रखता। फिलहाल इस सदन के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि गन्ना भुगतान की एक बहुत बड़ी समस्या है। गन्ना भुगतान को छोड़िए। मान्यवर, आज की तारीख में जनपद सीतापुर की सिधौली तहसील में आप किसी भी क्रय केंद्र में चले जाएं तो तीन-तीन दिन तक सर्दी की रातों में किसान अपने गन्ने के साथ क्रय केंद्र पर सोता है कि उसका गन्ना तीसरे दिन ही बिक जाए। मान्यवर, तीन-तीन, चार-चार दिनों तक किसानों का गन्ना खरीद क्रय केंद्र पर नहीं खरीदा जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है ? किसान तो अपना गन्ना लेकर आता है, लेकिन जब उसका गन्ना तीन दिन, चार दिन और पांच दिन तक नहीं बिकता है तो वह गन्ना वहीं पलटकर, वहीं आग लगाकर सरकार को कोसते हुए अपने घर को चला जाता है और गन्ना मिलों पर गन्ना नहीं पहुंचता है। गन्ना मिल मालिकों की अपनी मानमानी है। मैं तो समझता हूं कि सरकार का कोई दबाव नहीं है। गन्ना मिल मालिक जब चाहेंगे तब पेमेंट करेंगे और जब चाहेंगे पेमेंट नहीं करेंगे। अमूमन हमारे कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में किसान गन्ने की फसल काटने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं।

मान्यवर, गेहूं की फसल पर आपको बता दें कि आज अगर किसान खाद लेने जाता है तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 50 किलो की बोरी थी इसमें

सरकार ने कटौती करके 5 किलो और कम कर दिया है। अब 45 किलो की बोरी मिल रही है। फिर भी उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस सरकार की यह सबसे बड़ी नाकामी है और किसानों के प्रति इससे बड़ी संवेदनशीलता और कुछ नहीं हो सकती है। मान्यवर, हम क्वेश्चन ऑवर में देख रहे थे कि विद्युत पर बड़े सवाल लगाए गये। आज विद्युत के हालात यह है कि यहां पर सिधौली 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अगर सिधौली चले जाएं तो वहां पुराने और जर्जर तार तथा लकड़ी की बांस की बल्लियों पर केबिल लटके हुए मिलेंगे। उसको बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां आपको कोई भी लाइन नहीं मिलेगी। किसान अगर आज कनेक्शन लेता है यदि उसने आज अपने निजी ट्यूबवेल के लिए रसीद कटाई तो उससे कह दिया जाता है कि पूरे सीतापुर जनपद में 2500 ट्रांसफार्मर आज भी लम्बित हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। किसान सालों साल बिजली विभाग के चक्कर लगाता है। उसका पैसा भी पेड है, लेकिन उसको ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिस कारण वह सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, क्या किसानों ने सरकार से यही उम्मीदें लगाई थीं। दूसरा स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चर्चा हुईं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जानकारी तो नहीं रखता हूं, लेकिन अपने सीतापुर के बारे में जरूर जानकारी रखता हूं। मैं सिधौली विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और सिधौली विधान सभा क्षेत्र लखनऊ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं कई बार इस बात को सदन में रख चुका हूं कि लखनऊ ट्रॉमा सेंटर से और हमारे सिधौली मुख्यालय तक की दूरी 55 किलोमीटर है और पूरी सिधौली विधान सभा क्षेत्र नेशनल हाई-वे-24 पर बसी हुई है। वहां कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन इस सर्किल के अन्दर एक्सीडेंट न होता हो। मैं 20 बार इस सदन में मांग कर चुका हूं कि सिधौली में ट्रामा सेंटर की व्यवस्था कर दी जाये। लेकिन ट्रामा सेंटर की व्यवस्था आज तक नहीं हुयी तो एक छोटी सी व्यवस्था ही करा दी जाये। अभी हमने अपने सिधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक से पूछा था कि एक हमारा आदमी है उसको कुत्ते ने काट लिया है। उसने कहा कि हमारे यहां इंजेक्शन नहीं है। हमने जिले में सी0एम0ओ0 से बात किया तो उन्होंने कहा कि जिले में भी कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है। उसकी व्यवस्था हो रही है। मान्यवर, जब तक वह व्यवस्था होगी तब तक उस कुत्ते काटने वाले आदमी की क्या दशा होगी। मान्यवर, आप समझ सकते हैं।

मान्यवर, इस सरकार ने शुरू से ही कह दिया था कि हमने इतने लाख सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया। मान्यवर, एक समिति बना दीजिए और हमारे सिधौली भेज दीजिए। अगर सिधौली विधान सभा के अन्दर एक भी गड्ढामुक्त सड़क मिल जाये तो हम मान लेंगे कि आपने लाखों किमी0 की सड़कें गड्ढामुक्त कर दी हैं। हम तो यही मानते हैं कि आपकी गड्ढामुक्त सड़कों की कोरी कल्पना ही कागजों पर चल रही थी। आज आपकी गड्ढामुक्त योजना गड्ढायुक्त में बदल चुकी है। मान्यवर, हमारी तहसील सिधौली में सिंचाई की व्यवस्था यह है कि पिछले साल तो थोड़ा पानी नहरों में आया लेकिन इस साल एक बूंद भी पानी किसी

नहर में नहीं आया। मान्यवर, अगर गेहूं की फसल की सिंचाई करनी हो तो उसके पास नहर के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। टयूबवेल के ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। बिजली की लाइने टूटी पड़ी हैं। एकमात्र सहारा नहर है और नहर में भी पानी नहीं आ रहा है। बताइये आज किसान कैसे गेहूं की फसल की तैयारी करेगा। इस सरकार से कुछ कहो भी तो सरकार तुरन्त अपना कच्चा चिट्ठा दिखा देती है कि इतनी नहरों में इतने क्यूसिक पानी मैंने छोड़ा। इतने ट्यूबवेल पर ट्रांसफार्मर लगा दिये।

मान्यवर, अभी हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर ने एक पत्र के माध्यम से हमको सूचना दिया कि हर तहसील मुख्यालय पर कैम्प लगाकर पात्रों को पेंशन दी जायेगी। उस पत्र को प्राप्त हुये करीब 4-5 महीने हो गये। अभी तक सरकार की तरफ से कोई कैम्प नहीं लगाया गया है और न ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गयी। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को जरा भी किसानों के प्रति गम्भीरता है तो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करा दें, खराब पड़े ट्यूबवेल को ठीक करा दें। खासकर हमारी सिधौली में स्थिति बहुत खराब है। सिधौली की एक बार आप जांच करा लें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

मान्यवर, कितने ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, कितनी नहरों में पानी आया इसकी आप जांच करा लें। मान्यवर, यह इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 विधायक श्री सुनील कुमार शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस सदन के अन्दर विभिन्न विचारधारा के लोग बैठकर अपने-अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। हमारी सरकार ने जिस प्रकार विकास के कार्य और जनकल्याण के कार्य किये हैं वह स्वाभाविक रूप से इनको पसन्द नहीं आ सकते हैं। हमारी सरकार मा0 योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, उस सरकार ने जिस-जिस तरह से आम आदमी के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। वैसे भी हम जिस राजनीतिक विचारधारा से आते हैं वह सामान्य विचारधारा नहीं है। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 52 वर्ष की उम्र में देश के लिए बलिदान

दिया। हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस राजनीतिक विचारधारा को लेकर हम काम कर रहे हैं उसके जनक एकात्म मानववाद के प्रणेता, दीन दयाल जी की भी 52 वर्ष में हत्या कर दी गई। इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की चिता की भस्म से जो ऊर्जा हमें मिली उस ऊर्जा के आधार पर हमने देश के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करना शुरू किया। श्री अटल विहारी बाजपेई जी की 4 पंक्तियां कहकर के अपनी बात शुरू करूंगा।

"कर्म पथ पर इस अनेकों फूल भी हैं !
कोटि जन अनुकूल हैं, पर अल्प जन प्रतिकूल भी हैं !!
किन्तु सुख-दुख में सदा ही एक-सी अभिनन्दना ले !!!
बढ़ रहे हम निरन्तर राष्ट्र जय की कामना ले !!!!

इसी लक्ष्य और उद्देश्य के साथ हम देश और प्रदेश के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। हमारी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समर्पित है। हमारी सरकार ने पंथ के आधार पर नहीं, मजहब के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, लोगों का कल्याण कैसे हो इस भाव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय देने का काम किया है, प्रत्येक व्यक्ति का आवास बनाने का काम किया है, प्रत्येक व्यक्ति को उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस उपलब्ध कराने का काम किया है, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन देने का काम किया है और जिस गरीब ने शायद अपने जीवन में कभी 5 लाख रुपये देखे नहीं होंगे, जिसने 5 लाख रुपये कभी कागज पर लिखे नहीं होंगे, जिसको यह पता नहीं होगा कि 5 लाख रुपये लिखने में कितने जीरो होते हैं उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 5 लाख रुपये की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। जो छोटे-छोटे लाभ हमने लोगों को दिये हैं उसके कारण कितने लोग रोजगार पाये होंगे। राजगीर आपको ढूंढे नहीं मिल रहा होगा, बढ़ई को काम मिला है, पेण्टिंग करने वाले को काम मिला है। अनेक रोजगारों का सृजन इन छोटे-छोटे कामों से हुआ है। मैं अगर बहुत सारी चीजों का उल्लेख करूंगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। सरकार ने लोक-कल्याण के इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने का संकल्प लिया है एकात्म मानववाद के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको जो संदेश एवं विचार दिया था उस विचार के आधार पर हमने अपनी सरकार की कार्यशैली तय की है। यह सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं, मैं जनपद-बाराबंकी से निर्वाचित होकर आता हूं। बाराबंकी जिले में घाघरा नदी की बाढ़ आई हुई थी, प्रत्येक स्थान पर बाढ़ आने से पहले ही सरकार ने चिंता की थी कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ से परेशान न होने पाये, किसी को बाढ़ से कोई कष्ट न होने पाये। प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं अनेक स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने के लिए गये थे। मेरे बाराबंकी जिले में महादेवा नाम का एक स्थान है वहां आडीटोरियम में अहेतुक सहायता वितरण का कार्यक्रम लगा हुआ था। जिस समय सहायता वितरण का कार्यक्रम

होने वाला था उसी से कुछ समय पहले जबरदस्त बारिश हो रही थी। आप सोच सकते हैं कि जो मंच पर पहुंच गये वह मंच से हटने की स्थिति में नहीं थे जो गेस्ट हाउस में पहुंच गये वह गेस्ट हाउस से निकलने की स्थिति में नहीं थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी लेकिन मैं मा0 योगी आदित्यनाथ जी महाराज का साहस आपके सामने बताना चाहता हूं। वह गोण्डा से चल करके आये थे, हेलीकॉप्टर लैण्ड होने की स्थिति में नहीं था। बाद में उन्होंने बताया कि हमारा पायलट कह रहा था कि हेलीकॉप्टर लैण्ड होने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये महादेव की भूमि है, भोलेनाथ का नाम लो और हेलीकॉप्टर लैण्ड करो। हेलीकॉप्टर लैण्ड हुआ और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। मैं बाराबंकी जिले का दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, 2015-16 में ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ था, उन फसलों के नुकसान में, उस समय की समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा 42 लाख रुपये का आवंटन हुआ था। आपको मैं जानकारी दे दूं 42 लाख रुपये के आवंटन में केवल साढ़े नौ लाख रुपये वहां के किसानों को दिया गया, शेष रुपये सरकार को फिर से वापस कर दिया गया, किसान त्राहि-त्राहि करते रह गए, किसान मांग करते रहे, लेकिन संवेदनहीनता के कारण उनके मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं गठबंधन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि गठबंधन का नाम लेने से हमारे मित्र लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं गठबंधन शब्द नहीं कहूंगा। लेकिन अगर मैं एक चीज का वर्णन करूं कि इन सबके द्वारा सारे आरोप आज इस सरकार पर लगाए जा रहे हैं। जितने भी लोगों ने अपनी बात कही है मा0 नेता विरोधी दल से लेकर सारे विपक्ष के लोग हम पर आरोप लगाते हैं। इस विषय में मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में पहली सरकार 26 जनवरी, 1950 को बनी और 1950 के बाद से अगर मैं आंकड़ों का विश्लेषण करूं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्रियों के नेतृत्व में केवल आठ साल सरकार रही है, कुछ सरकारों में हमारा सहयोग रहा है। बाकी सारी की सारी सरकारों का कार्यकाल, आप जो तीनों दल यहां पर बैठे हुए हैं, उन तीनों दलों के मुख्य मंत्रियों के नेतृत्व में रहा है। आपको किसने रोका था कि गरीबों को आवास मत दीजिए, किसने रोका था कि गांव का गलियारा पक्का मत कीजिए, आपको किसने रोका था कि गांव की सड़क पक्की मत कीजिए, आपको किस आदमी ने रोक दिया था कि आप गांव का विकास मत कीजिए, गांव की गरीबी दूर मत कीजिए, अल्पसंख्यकों का विकास मत कीजिए। आपको किसी आदमी ने रोका था क्या ? आपको किसी ने नहीं रोका था किन्तु आपकी सोच नहीं थी लेकिन आप 62 वर्षों का हिसाब देने को तैयार नहीं हैं। गठबंधन तो आप छोटी-छोटी बात पर कर लेते हैं, एक साथ यहां पर हल्ला मचाने लगते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको अयोध्या भी याद नहीं थी। अगर अयोध्या याद भी आयी तो कारसेवकों पर गोली चलवा दिया। आपको मथुरा भी याद नहीं थी, मथुरा में अगर याद आया तो रामवृक्ष यादव के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करा

दिया (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयीं)। आपको वाराणसी भी याद नहीं थी, हमने तो वाराणसी को भी याद किया है। आपको तो वाराणसी की गलियों की भी याद नहीं थी हमने वहां भी काम किया है। हमने वाराणसी में गंगा की आरती भी की है। आपको नैमिषारण्य भी याद नहीं था, आपको बौद्ध परिपथ भी याद नहीं था। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बहुत सारी चीजों का उल्लेख कर सकता हूं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसके कारण इस उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से कि प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू हुई, किसके कार्यकाल में शुरू हुई। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसका श्रेय जाता है जिसके कारण आज पूरे प्रदेश के अन्दर सड़कों का जाल फैला है। इसके पहले की अगर मैं बात करूं, जिस समय मैं बहुत छोटा था, उस समय के हमारे कई वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे उन्हें पता होगा कि जब 1977 में जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी तो काम के बदले खाद्यान्न योजना चली थी। भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ घटक के रूप में, जनता पार्टी की उस सरकार में शामिल था तब पहली बार गांव-गांव तक जाने के लिए कच्ची सड़कों का निर्माण शुरू हुआ था। जब हम सरकार में आए तभी सड़क क्यों बननी शुरू हुई ? आपको किसी ने सड़क बनाने से रोका था क्या ? आपको किसी ने मना किया था कि आप नहरों में पानी मत दीजिए, आपको किसी ने मना किया था कि आप नलकूप मत चलाइए, आपको किसी ने मना किया था कि आप लोगों के कल्याण की योजना मत चलाइए। आपने कभी भी जन-कल्याण की भावना के साथ लोगों का काम करने की कोशिश ही नहीं किया। आपने तो बेटी-बेटी के बीच में भी फर्क कर दिया था। कब्रिस्तान और श्मशान में भी फर्क कर दिया था। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र अपनाया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिए।

(श्री विनय शंकर तिवारी के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा-

आप कुछ कह रहे हैं क्या। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तीन-चार मिनट हुआ है। मैं स्वयं घड़ी देख रहा हूं....

(इस समय 02 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

और ये बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। मान्यवर, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हमने की। इनकी शैली तो ऐसी है कि उस शैली के कारण ये चाहते हैं कि गरीब-गरीब ही बना रहे। अशिक्षित-अशिक्षित ही बना रहे। अगर गरीब पैसे वाला हो जाएगा, अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो इनके बहकावे में नहीं आएगा। अगर इनके बहकावे में नहीं आएगा तो इनके कहने पर वोट नहीं देगा। हमें यह भी याद होना चाहिये कि संविधान सभा में 18 सितम्बर, 1949 को

पंडित कमलापति त्रिपाठी ने बोलते हुए कहा था कि हमें स्मरण होता है कि हमारे नायकों ने हमारे विचारकों ने उस महान राष्ट्र को जन्म दिया था जिसने अपनी संस्कृति को सारे संसार में फैलाया है और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। आज भारत की संस्कृति से अनुप्राणित होकर अगर अयोध्या और प्रयागराज का नाम हम परिवर्तित कर देते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। यह हिन्दुस्तान ऐसा है जिसने आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर अंग्रेजों के द्वारा लोक सभा में बजट प्रस्तुत करने का समय हमने परवर्तित कर दिया। महोदय, दो मिनट का समय और दें बोलने के लिए। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातों का उल्लेख करना यहां सम्भव नही है। मैं समझ रहा हूं कि समय कम है अगर हम अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर सकते हैं तो मुगलों की गुलामी के प्रतीकों को भी हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुम्भ को विश्व ने मान्यता दी है, लेकिन यहां सदन के अन्दर कुछ लोग अगर इसको तमाशा कहने की कोशिश करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि यह कुम्भ का आयोजन है, यह तमाशा नहीं है, तमाशा तो आप करते हो सैफई का महोत्सव क्या हुआ करता था ? सदन में आपको मुम्बई वाला भाषण देने के लिए पसन्द नहीं आता, लेकिन सैफई महोत्सव में आप मुम्बई के किन लोगों को बुलाते थे तमाशा करते थे फिर सम्मानित करते थे इसका भी विचार आपको करने की आवश्यकता है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन प्रश्न विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रथम दिन अभिभाषण हो रहा था, उस समय गोले फेंके जा रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि गोले फेंकने वालों का टारगेट कौन था। क्या 80 साल के राम नाईक जी थे ? या हमारे संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल जी थे ? या फिर विधान सभा के अध्यक्ष जी की पीठ थी ? या निजी तौर पर वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी थे ? अध्यक्ष पीठ पर विराजित पूज्य महात्मा गांधी जी का फोटो लगा है क्या वे टारगेट थे। टारगेट कौन था ? क्या राज्यपाल महोदय के पीछे पगड़ी बांधे हुए जो सिक्ख खड़ा था वह टारगेट था हो सकता है 1984 की याद आ गई हो। आपका टारगेट कौन सा था, आपको बताना चाहिये आपने शायद स्वच्छता अभियान में सहयोग ना करने का संकल्प ले रखा था इसलिए आपने कागज फाड़ करके विधान परिसर को गन्दा करने का काम किया है। मैं हतप्रभ हूं कि आपका टारगेट कौन सा था ? मा0 महोदय, यहां पर तो उस दिन खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे जैसी स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इन लोगों की नीयत है। अगर हम 325 जीत रहे हैं तो इनको लगता है कि ईवीएम खराब है, मान्यवर, अगर ये फूलपुर, गोरखपुर जीत रहे हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी है, चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इनकी नीयत हो गई है। सदन तय करे कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान न हो। मैं आपके माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी, कहना चाहता हूं कि हम सब जिस विचारधारा के हैं वहां हमेशा से गीत गाते चले आए हैं-

पथ का अन्तिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना।
सब समाज को लिये साथ में आगे ही बढ़ते जाना।।

इसी संकल्प भाव के साथ सरकार भी काम कर रही है। मैं आदरणीय सुनील शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

श्री अध्यक्ष-

विनय शंकर तिवारी जी।

श्री विनय शंकर तिवारी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर हमें अपनी बात कहने का मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं नेता बहुजन समाज पार्टी श्री लाल जी वर्मा और विपक्ष के नेता श्री राम गोविन्द चौधरी जी से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

मा0 राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था सरकार ने उसको इस तरह से प्रस्तुत किया कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है लेकिन अगर पूरी बात को देखा जाए तो वह झूठ का पुलिन्दा या जुमलेबाजी का एक ग्रन्थ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से सरकार ने कुम्भ के ऊपर प्रचार-प्रसार करके चार-साढ़े चार हजार करोड़ रुपये से ऊपर जो धन खर्च किया है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में या इस देश में पहली बार कुम्भ लगा है। इस कुम्भ के बारे में मार्क टली जो बी0बी0सी0 के रिपोर्टर थे उनका एक संस्मरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मार्क टली अपने देश वापस गए थे तो वहां पर उन्होंने एक वर्णन किया था कि भारतवर्ष में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा अवसर है कि जहां पर बिना किसी प्रचार-प्रसार के कोई होर्डिंग नहीं लगता, कोई बैनर नहीं लगता, कोई किसी को बताने नहीं जाता है। तब भी वहां पर करोड़ों लोग स्वतः इकट्ठा होने का कार्य करते हैं तो उस समय वहां के लोगों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि वहां पर एक मैगजीन निकलती है जिसे पत्रा कहा जाता है और उस पत्रा में एक जगह लिखा होता है कि फलां तारीख को या फलां समय में कुम्भ का मेला लगेगा, उस दिन करोड़ों-करोड़ लोग उस जगह पर इकट्ठा होने का काम करते हैं। यह जो हमारा देश है इसमें हमारे आदि पूर्वजों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई थी कि हमें कुम्भ में कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन आज सरकार ने कुम्भ को बताने के लिए हर गली-मोहल्ले में पोस्टर लगाए हैं। अपनी उपलब्धि की बात कर रही है लेकिन कुम्भ में जो हमारी आस्था है, वह आस्था गायब हो चुकी है। आज कुम्भ का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। कुम्भ हमारी आस्था का प्रतीक न होकर राजनीति का प्रतीक हो गया है। आज आप कुम्भ में जहां भी जाएं, अब वहां पहले जैसा कुछ नहीं है। हम लोग भी हमारे दादी-बाबा के साथ बचपन में कुम्भ में जाया करते थे। देखते थे कि वहां पर किस तरीके से ऋषियों का प्रवचन होता था, लोग कुम्भ में अपनी आस्था को व्यक्त करते थे। आज वह आस्था समाप्त हो गई है। कुम्भ में आज केवल प्रचार और प्रसार

रह गया है। जहां देखिए चन्द लोगों के बड़े-बड़े पोस्टर और बड़े-बड़े होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। जो आस्था कभी कुम्भ की थी वह आज समाप्त हो गई है।

अभी मा0 राज्यपाल जी ने इन्वेस्टर्स समिट के बारे में कहा। एक जिला एक उत्पाद के बारे में कहा, रक्षा कॉरिडोर के बारे में कहा। अध्यक्ष जी, जो समिट आयोजित की गई उसमें ढेर सारे एम0ओ0यू0 किए गए लेकिन एम0ओ0यू0 का मतलब यह नहीं हुआ कि उसमें धन आ गया। केवल दस्तखत हुए हैं। आज किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज कहीं पर कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, उसमें केवल बड़े-बड़े इवेण्ट किए जा रहे हैं और इवेण्ट में भी बड़े-बड़े घपले और घोटाले हो रहे हैं। इस इवेण्ट से कहीं भी इस देश और प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस प्रदेश की जनता का कोई कल्याण इस इवेण्ट के माध्यम से नहीं हो रहा है। जो इवेण्ट हो रहे हैं, जो एम0ओ0यू0 हो रहे हैं उनसे बेरोजगारों को कोई रोजगार आज भी नहीं मिल रहा है। जहां तक किसान हितैषी सरकार की बात है तो डी0ए0पी0 का दाम आज भी पहले से बढ़ा हुआ है। यदि आप डी0ए0पी0 का दाम देखें तो सरकार बार-बार यह कहती है कि हम किसानों की हितैषी सरकार हैं। लेकिन जब किसानों के हित की बात आती है तो सरकार उस पर संकल्पित नहीं रहती है। आज किसानों की डी0ए0पी0 का दाम बढ़ा हुआ है। सिंचाई का महकमा है, सिंचाई के महकमे में बाढ़ का महकमा है। अध्यक्ष जी, जहां से हम आते हैं उस क्षेत्र को तीन नदियां प्रभावित करती हैं। लेकिन वहां बन्धों के संरक्षण के नाम पर 18 बन्धों पर केवल एक करोड़ रुपये की धनराशि मेण्टीनेन्स के लिए दी जा रही है। यह धनराशि कितनी कम है, अगर यह सरकार किसान हितैषी है तो किसान विरोधी सरकार कैसी होगी। इसलिए यह सरकार पूर्णतया किसान विरोधी सरकार है। साथ ही साथ जब मा0 महामहिम जी ने कानून-व्यवस्था की बात कही थी तो उन्होंने कहा कि आज कोई खौफ नहीं है। लेकिन स्थिति इससे ठीक उल्टा है। मैं जहां से आता हूं वहां अपराध का ग्राफ कितना है। अगर आप मंगाकर देख लें तो आज दिन प्रति दिन महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। छात्रों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। नौजवानों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है और हर तरफ खौफ का माहौल है। अगर जो लोग कहते हैं कि आज जनता बेखौफ है तो अभी बुलन्दशहर में हमारे एक पुलिस इन्स्पेक्टर की हत्या हुई है। वह हत्या अभी ताजा-ताजा हुई है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारा पुलिस इन्स्पेक्टर मार दिया जा रहा है तो हम कैसे बेखौफ होंगे। जब सुरक्षा करने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो सरकार कैसे अपनी यह बात कह सकती है कि नहीं आज सुरक्षा का माहौल है।

मान्यवर, जब अच्छी कानून व्यवस्था की बात होती है तो उसमें एक दृढ़ इच्छाशक्ति का होना आवश्यक होता है, सरकार में दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं है जिससे कि वह कानून व्यवस्था को बरकरार रख सके। इसके साथ ही साथ आज बेरोजगारी की बात होती है जो हमारे कर्मचारी हैं वह आज आंदोलनरत् हैं उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

जब वह बात कह रहे हैं तो उनको जेल में ठूसने की बात कही जा रही है। पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। साथ ही साथ उनके हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हम यह कहना चाहेंगे कि माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उसके प्रस्ताव में यह जोड़ दिया जाये जो कि हमारे क्षेत्र हैं उनमें तमाम ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है कि धुरियापार चीनी मिल को चलाने का काम किया जाये क्योंकि सरकार किसानों की हितैषी होती है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम नयी-नयी चीनी मिलें खोल रहे हैं और जो चीनी मिल चालू है उसको सरकार बंद करने का कार्य कर रही है। इसलिए निश्चित रूप से सरकार किसानों की हितैषी नहीं हो सकती है। हमारे यहां बारानगर कैनाल है जो सरयू कैनाल से निकलती है आज वह कैनाल अपनी जीर्ण-शीर्ण हालत में है उस पर सरकार धन देने का काम नहीं कर रही है। मैं इसमें कितनी बार आपके माध्यम से भी कह चुका हूं उनके मंत्री से भी कह चुका हूं लेकिन बारानगर कैनाल पर धन नहीं दिया जा रहा है। राम जन्म भूमि की बात सरकार करती है जो राम-जानकी मार्ग हमारे चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र से होकर जाता है वह इतनी बुरी हालत में है। जहां राम मंदिर पर करोड़ों रुपये खर्च करने की बात की जा रही है उसको जोड़ने की बात की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, जो सबसे महत्वपूर्ण राम-जानकी मार्ग है जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनकपुर गये थे उस मार्ग की दुर्दशा इतनी है कि उस पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। साथ ही जो कुआनों नदी है दुघरा ग्राम सभा में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, राम-जानकी मार्ग के सम्बन्ध में, उरवा को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में, चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के गोला तहसील में बस स्टेशन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी सूची उसमें है, अब हो गया।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, यह सूची मुझे पूरी कर लेने दीजिए। बड़हलगंज के सरयू नदी पर लेहटा घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में सरयू नदी बारानगर स्थित कालिका मंदिर पर घाट निर्माण कराने और पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के सम्बन्ध में आपके सामने अपनी बात रखता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद।

***श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण के समर्थन में जो प्रस्ताव आया है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे मेरा इरादा बजट पर बोलने का था लेकिन मैंने अभी ट्वीटर पर देखा, एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी कहने का अधिकार रखती है और वह पुरानी पार्टी है भी, जिसको जन्म एक अंग्रेज ने दिया था। दुर्भाग्य इस देश का था कि 1947 की आजादी के बाद उसके हाथ में सत्ता चली गयी लेकिन उनके अन्दर अंग्रेजियत की बू थी। इसी लिहाज से शायद जो मैंने अभी ट्वीटर पर देखा है।

श्री अध्यक्ष-

आप अभिभाषण की कोई बात बताइये ट्वीट का क्यों संज्ञान लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उस राष्ट्रीय पार्टी की एक महासचिव ने ट्वीटर पर लिखा है 'भारत मूर्खों का देश है', जहां सरकार लोगों के पीने के पानी पर नहीं बल्कि ढोंगी और पाखंडियों के शाही स्नान पर करोड़ों का खर्च करती है। इस चीज को पढ़कर इसकी आवश्यकता हुई कि सदन के अन्दर जो लोग भी आस्था में विश्वास करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अभिभाषण पर बोलिये।

(सदन में किसी सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

आने वाले समय में कांग्रेस रहेगी भी नहीं। जो लोग इस तरीके से उत्तर प्रदेश में शाही स्नान को पाखण्डी कहेंगे, साधू-संतों को पाखण्डी कहेंगे, वो इस देश में रहेंगे भी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अभिभाषण पर कुछ कहेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, अब वो यहां पर नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ लोग होंगे वो उन्हें समझा देंगे कि आखिर कुम्भ का महत्व क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

जो नहीं हैं, उन पर क्यों चर्चा करते हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

यह कहना जरूरी था इसमें आ जायेगा, पढ़ लेंगे। अखबार में जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो कहना चाहते हों कह दीजिए।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, उनका ट्वीट कम से कम अखबार में छपेगा। कुम्भ पर्व हिन्दू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैं उसी पर बोल रहा हूं। राज्यपाल जी ने सबसे पहले कुम्भ पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया सरकार का दृश्य रखते हुए। इसलिए मैंने कुम्भ से शुरू किया, अन्यथा मैं शुरू नहीं करता और साथ में यह ट्वीट मुझे मिल गया तो मैंने कहा कि इसको स्पष्ट कर दिया जाय। कुम्भ खासकर आस्था से जुड़ा हुआ है और यह देश आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। आज चाहे जितने लोग इस बात को कहें कि गंगा प्रदूषित है, गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है, गंगा का पानी आचमन करने योग्य नहीं है लेकिन आज भी इस देश के अन्दर करोड़ों-करोड़ लोगों की आस्था है कि अगर जिन्दा रहने में न सही तो मरते वक्त अगर मुंह में दो बूंद गंगाजल डाल दिया जाय तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यह आस्था हमारी है और इस आस्था पर कोई सवाल नहीं कर सकता। इस आस्था के बारे में अगर कोई साधू-संतों को पाखण्डी कहेगा तो मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। मैं आपको एक दूसरा ट्विट दिखा रहा हूं कि क्या हालत है इन लोगों की।

(विपक्ष द्वारा टोका-टाकी किये जाने पर)

आप बोल लीजियेगा। मैं बहुत कम बोलता हूं, परेशान न होइये। आप लोग खूब बोलते हैं, मैं कभी नहीं बोलता हूं। शांत हो जाइये। बैठ जाइये। इस देश की जनता और प्रदेश की जनता आप लोगों के जो क्रिया-कलाप हैं उसको खूब देख रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप अभिभाषण पर बोलिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी मैं यह कह रहा था कि कुम्भ का मेला भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और कुम्भ कोई ऐसा-वैसा स्नान नहीं है इसीलिए प्रदेश सरकार ने कुम्भ के मेले को महत्व

दिया है और सांस्कृतिक धरोहर को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है। विश्व के देशों को बताने का काम किया है कि यह कुम्भ क्या है ? कुम्भ का महत्व क्या है ? किसलिए कुम्भ पर इतना पैसा खर्च किया गया। हमारे योगी संत हैं, उनसे यह देश और प्रदेश अपेक्षा भी करता है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे जो आस्था के केन्द्र हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में वो कार्य भी करेंगे। यह देश भी जानना चाहता है और प्रदेश भी जानना चाहता है। मा0 अध्यक्ष महोदय मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभिभाषण पर कहिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

यहाँ पर पहली बार, मैं अपने इन विपक्ष के भाइयों से पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

उनको नहीं याद है। आप अभिभाषण पर बोलिये। उनसे मतलब नहीं रखिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कभी यह कल्पना आयी थी कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की जाय। आपने कभी ऐसे असंगठित मजदूर जो नाई, धोबी, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम कभी आपने जिन्दगी में किया है। इतने साल आप सत्ता में रहे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो अभिभाषण का भाग है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता के बारे में कई आलोचना होती है। देश के प्रधानमंत्री जब नरेन्द्र भाई मोदी हुए और जब उन्होंने शपथ लिया तो उन्होंने कहा कि गांधी जी का यह सपना था कि स्वच्छता सर्वोपरि रखी जाय और उन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम को एक मिशन के रूप में स्वीकार किया। मैं बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं। मैं आपको लखनऊ की बात बताता हूं कि उस स्वच्छता कार्यक्रम को लखनऊ में सर्वोपरि रख करके यह दिखा दिया कि.....

आज लखनऊ सर्वे में नम्बर एक पर आ गया है। जगह-जगह पर केवल शौचालय ही नहीं, एयर कंडीशन्ड शौचालय बनाये गये हैं मेरे क्षेत्र में आइये, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने अपने क्षेत्र के अन्दर एयर कंडीशन्ड शौचालय बनवाये हैं। हमने ऐसे भी शौचालय बनाये हैं जहां पर दिव्यांग लोगों के लिये रैम्प बना हुआ है, महिलाओं के लिये अलग, पुरुषों के लिये अलग। सबकी व्यवस्था के लिये शौचालय यहां पर निर्माण हुये हैं और तभी लखनऊ सर्वे में नम्बर एक पर आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा। चिकित्सा के क्षेत्र में सैफई में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गयी लेकिन इसके अलावा क्या कभी सोचा गया था कि और जगह पर भी मेडिकल कालेज बने। आज इस सरकार द्वारा आठ नये मेडिकल कालेज देवरिया, सिद्वार्थनगर, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, हरदोई और एटा में निर्मित किये जा रहे हैं। यह लोग जो कहते हैं कि जुमलेबाजी हो रही है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि यह जुमलेबाजी नहीं है बल्कि धरती पर काम हो रहा है। आप जाकर देखो। आवश्यकता इस बात की थी और प्रदेश की जनता को भी यह अपेक्षा थी कि आप अच्छे काम की तारीफ करेंगे लेकिन आपको तो केवल विरोध करना है इसलिये विरोध पक्ष में आप बैठे हुये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रामा सेंटर की बात बताना चाहता हूं कभी इन लोगों ने जाकर ट्रामा सेंटर देखा तक नहीं होगा। इस ट्रामा सेंटर की कल्पना परमश्रद्धेय अटल विहारी बाजपेयी जी ने की थी, उनकी प्रेरणा से लखनऊ का ट्रामा सेंटर बना था और आज वह ट्रामा सेंटर आपके उत्तर प्रदेश में नम्बर एक पर है। यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रामा के मायने ही नहीं मालूम होंगे। उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ट्रामा सेंटर खोलने की आवश्यकता है। आज वह अद्वितीय है। अभी 200 बेड का माननीय राजनाथ सिंह जी ने वहां पर मरीजों के तीमारदारों के लिये रैनबसेरे का इन्तजाम किया है। यह जो पार्टी के लोग बैठे हुये हैं, इनके सांसदों ने या विधायकों ने क्या कभी यह सोचा कि ऐसा भी पुण्य का काम करना चाहिये। मेडिकल कालेज में, ट्रामा सेंटर में जो मरीजों के तीमारदार आते हैं उनके बारे में भी कभी यह सोचते और कोई इन्तजाम करते तो अच्छा होता।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय सुधार हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फ्री-वाईफाई की सुविधा हमारी इस सरकार में प्रत्येक डिग्री कालेज और पोस्टग्रेजुएट कालेज के अन्दर हुयी है और अगर विश्वास न हो तो चलो मैं दिखाता हूं, अपनी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पं0 दीन दयाल उपाध्याय डिग्री कालेज में, जहां पर फ्री-वाईफाई की सुविधा इस सरकार ने की है। अनेक सुविधाओं को शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार द्वारा किया गया है। कौशल विकास के क्षेत्र में तमाम नौजवानों को प्रशिक्षित किया गया है। यह लोग तो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देकर भिखारी बना रहे थे, अकर्मण्य बना रहे थे। हमारी सरकार ने कौशल विकास योजना के अन्तर्गत नौजवानों को रोजगार सिखाया और उनको मालिक बना करके यह कहा कि आप अपने संरक्षण में और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दो। इस प्रकार हमने लोगों को रोजगार देने का काम किया है।

मान्यवर, पेंशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह पहली सरकार है, यह लोग तो कहेंगे कि आप बी0जे0पी0 के हैं इसलिये आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं भी इतने दिन से सदन के अन्दर हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार में डी0एम0 का फोन आता है विधायक के पास। समाज कल्याण अधिकारी का फोन आता है और वह कहते हैं कि आपके क्षेत्र में मैं एक बड़ा कैम्प लगाना चाहता हूं और वह कैम्प लगाते हैं जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग

पेंशन और अनेक जो सरकार की लाभकारी योजनायें हैं, उनके लिये कैम्प लगाया जाता है और इतना ही नहीं, उस कैम्प के अन्दर जो दिव्यांग लोग हैं, उनको सर्टीफिकेट देने के लिये मेडिकल आफिसर भी बैठता है, नगर निगम के लोग बैठते हैं, सारी सुविधायें मिलती हैं और 15 दिन के अन्दर मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार के दो बड़े-बड़े कैम्प लगे हैं।

दिव्यांग विभाग से, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि दिव्यांग विभाग से एक बड़ा कैम्प लगा करके 300 लोगों को ट्राईसाइकिल, जो लोग कान से कम सुनते हैं, उनके लिए मशीन कैलिपर्स, इन सब चीजों को देने का काम किया गया है और इतना ही नहीं, जो लोग उन दिन आये, उनका रजिस्ट्रेशन उस दिन हुआ, उनको भी हमने उपकरण देने का काम किया है। यह सरकार ''सबका साथ, सबका विकास'', जो हमारा मिशन है, उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

और मान्यवर, जिसका पूरा जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किया है, यह सरकार पूर्णतया उसी नक्शे-कदम पर कार्य कर रही है। इसी के साथ में मैं श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय श्री नफीस अहमद जी।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, जो नेता विरोधी दल ने संशोधन रखा है, उससे अपने आप को जोड़ते हुए, अपनी बात को रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जब पांच तारीख को राज्यपाल महोदय जी यहां आये थे तो हमें लगा कि इससे पहले जब हमारी सरकार थी तो माननीय राज्यपाल महोदय, हमेशा सरकार के कामों पर अपनी बातों को रखने का काम करते थे। हमें यह उम्मीद थी कि राज्यपाल जी यहां पर आयेंगे तो वह सच्चाई को सदन के सामने रखेंगे, लेकिन हमें अफसोस हुआ कि राज्यपाल महोदय ने जो कुछ भी कहा, वह हकीकत से बहुत दूर था और उनके अभिभाषण में सिर्फ लफ्फाजी थी।

श्री मुकुट बिहारी-

मान्यवर, यह शब्द उचित नहीं है।

श्री नफीस अहमद-

मान्यवर, अब यह उर्दू का लफ्ज है, आप निकाल दीजिएगा, अगर गलत होगा तो बताइयेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलें।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को इस शेर के साथ शुरू करूंगा-

"लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते,
कभी महलों की रक्काशा को, रानी हम नहीं लिखते,
यही तो बात है तारीख हम पर नाज करती है,
हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते।"

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश के अन्दर जो माहौल है, इस सरकार के अन्दर न किसान खुश है, न यहां का नौजवान खुश है। वादे तो संकल्प-पत्र में इतने बड़े-बड़े किये थे कि सरकार बनने के बाद ऐसा लगता था कि किसानों और नौजवानों की तकदीर और तस्वीर बदल जायेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हालात यह हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। चाहे खाद के दाम बढ़ाये गये हों और साथ ही साथ उससे पांच किलो कम भी कर दिया गया है। मंहगे डीजल और तमाम वह सुविधायें जो किसानों को मिलनी चाहिए थीं, यह सरकार नहीं दे रही है और साथ ही साथ किसान किसी तरीके से अपनी फसल को उगाता है तो छुट्टे जानवर उनकी फसलों को उनकी आंखों के सामने रौंद कर, उनकी मेहनत और उनकी कमाई को बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन इस सरकार के पास कोई ऐसी ठोस नीति नहीं है, जिससे इस प्रदेश का किसान खुशहाल हो, उसको सस्ती खाद मिल सके, बीज मिल सके और उनको उनकी उपज का दाम मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, हम जिस जनपद आजमगढ़ से आते हैं, आजमगढ़ सठियांव चीनी मिल में सबसे ज्यादा गन्ना, मेरी विधान सभा क्षेत्र देवारा में पैदा होता है। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो किसान आये-दिन हमसे शिकायत करते हैं। कई बार हमने माननीय गन्ना मंत्री जी से मिलकर भी यह कहा कि वहां पर किसानों को सही वक्त पर पर्चियां नहीं मिल रही हैं और पर्चियां अगर मिल गईं तो किसान जब चीनी मिल पर जाता है तो उसके गन्ने को कहीं सूखा दिखाकर, कहीं कुछ करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हालात तो यह है कि इस बार गन्ना किसानों ने पैदावार अच्छी की और उनको उम्मीद थी कि उनकी पैदावार को खरीद लिया जायेगा लेकिन जिस तरह से उनको पर्चियां मिल रही हैं जिस तरह से उनके

गन्ने को लिया जा रहा है उससे उम्मीद है कि 30 से 40 प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा रह जायेगा, उनको जलाना पड़ेगा, बर्बाद हो जायेगा।

मा0 अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मा0 राज्यपाल महोदय ने नौजवानों के लिए कहा लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा के संकल्प पत्र में था कि 90 दिनों के अन्दर लाखों नौजवानों को रोजगार मुहैय्या कराया जायेगा और जितनी सीटें सरकारी सेक्टर में खाली हैं उनको भरने का काम किया जायेगा। लेकिन आज हालात यह हैं आप देख लें जो माहौल है प्रदेश के अन्दर कोई भी नई फैक्ट्री नहीं लग रही, कोई ऐसा रोजगार नहीं पैदा किया जा रहा है जिससे नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिलें। प्राइवेट सेक्टरों का यह हाल हो गया है कि नौजवानों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। सरकारी भर्तियों में तमाम ऐसी भर्तियों के आवेदन लिये जा रहे हैं लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, किसी न किसी तरह से उसको रोकने का काम किया जा रहा है। हमारे एक माननीय विधायक जी कह रहे थे कि आपके पीछे बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी की जो तस्वीर लगी है उसको वह चिन्हित करके दिखा रहे थे मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे जो अलीगढ़ के अन्दर महात्मा गांधी की तस्वीर पर गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे वो कौन लोग थे जो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे उनकी क्या मानसिकता थी और सरकार ने क्या कार्रवाई की। सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया लेकिन ऐसे लोगों को उनकी संस्था जो हिन्दू महासभा है उस पर पूरी तरह से पाबन्दी लगनी चाहिए थी। उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एन0एस0ए0 की कार्रवाई होनी चाहिए थी क्योंकि अगर आप बापू का सम्मान नहीं कर सकते तो देश के अन्दर आप किसी गरीब, नौजवान, किसान का भी सम्मान नहीं कर सकते। जिन्होंने पूरे देश को एक करके अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, आज आप चश्मा तो लगाकर बड़े-बड़े वादों का दम्भ भरने का काम करते हैं लेकिन उनके सम्मान के लिए आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसी सोच के लोगों के साथ जो संविधान को जलाते हैं, जो बापू को नहीं मानते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ऐसे संगठनों पर पाबन्दी लगाने का काम करें। मा0 राज्यपाल जी कहते हैं कि हमारी सरकार के राज में कानून-व्यवस्था इतनी चुस्त-दुरुस्त है कि रात के अंधेरों में भी घर की औरतें बाहर निकल सकती हैं। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, पहले तो वह दौरा करते थे आजकल दौरा कम हो गया है। नहीं तो वह जरूर याद करते कि आगरा के अन्दर कैसे एक बच्ची को जिन्दा जला देने की कोशिश की गई। आज पूरे प्रदेश के अन्दर आप उठाकर देख लें कि पुलिस जो जनता की सुरक्षा के लिए लगाई गई है वह आज पुलिस थानों के अन्दर अपनी सुरक्षा की भीख सरकार से मांग रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, लोगों को आधा घण्टा मौका मिला है, हमें भी थोड़ा मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आधा घण्टा नहीं मिला है, सात-आठ मिनट से ज्यादा किसी को समय नहीं मिला है। हमने दलों के मा0 नेताओं को ज्यादा समय दिया था।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, बुलन्दशहर के अन्दर किस तरीके से एक थानाध्यक्ष को सरेआम गोली मारकर उसका वीडियो वायरल किया गया। यह है आपकी कानून व्यवस्था, जब थानाध्यक्ष सुरक्षित नहीं, उसका परिवार सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। आज से पहले यहां पर कहा जाता है कि पहली बार, हमें फख्र है कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने प्रदेश की तरक्की किस रास्ते से गुजर सकती है, कैसे प्रदेश तरक्की कर सकता है वह एक रास्ता बनाकर गये हैं और आज तक आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अपना कोई काम आपने करके नहीं दिखाया है। अगर आप एक्सप्रेस-वे की बात करते हैं तो इस प्रदेश के अन्दर देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे, वह एक्सप्रेस-वे कि देश की सेना को जब जरूरत पड़े तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सके, इसके लिए एक्सप्रेस-वे पर लड़ाकू विमान उतार करके अखिलेश यादव जी ने दिखाया है। उसी तर्ज पर पूर्वांचल में एक्सप्रेस-वे बनना था लेकिन उसके मानकों की कटौती करके रेट को कम करने का काम किया गया। उन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश के अन्दर सारे मुख्यालयों को फोर-लेन से जोड़ा जायेगा और सभी मुख्यालयों को जोड़ने का काम हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया था।

मा0 अध्यक्ष जी, आज हर काम के लिए ये लोग कहते हैं कि पहली बार है। आज आप अस्पताल में चले जाएं, रैबीज के इंजेक्शन नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं। आपने कार्पोरेशन बना दिया, डाक्टर दवाओं की डिमाण्ड्स करते हैं कि हमको क्रोसीन की टेबलेट्स चाहिए, तो आप गैस की टेबलेट्स भिजवा दे रहे हैं। ये हालात हैं सरकार की। हमारी सरकार में आजमगढ़ जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाकर चालू कराया गया था, लेकिन आज वहां के स्टूडेन्ट्स अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। वहां पर जितनी भी मशीनें हैं वह गोरखपुर शिफ्ट की जा रही हैं। वहां पर जितने अच्छे डाक्टर हैं उनको गोरखपुर शिफ्ट किया जा रहा है। यह अच्छी बात है कि आपने तमाम जनपदों का नाम बदल दिया। लखनऊ के चक गजरिया में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, आज वह कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है। सर्वे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े तादाद में कैंसर एवं किडनी फेल्योर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वह इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनको अच्छा इलाज यहां मिल जाता। आप बात करते हैं पहली बार। जो रास्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश

यादव जी ने दिखाया, उसी रास्ते पर आप चल रहे हैं। आप बुराई करके सत्ता में आ गये हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि-

''नग्मे लाजवाल पैदा कर, जज्बे बेमिसाल पैदा कर,
ऐब गैरों में देखने वाले, पहले खुद में कमाल पैदा कर''।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करिये, आपके सब विषय आ गये।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अब अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने बड़े-बड़े वादे किये थे, कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, नई सड़कें बनायेंगे। आज तो हमें कहीं गड्ढा मुक्त सड़कें नजर नहीं आतीं, लेकिन जो सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार में बनवायी गयी थीं, वहां आपके बड़े कट-आउट और बोर्ड लगे हुए हैं। आप काम करने में कम विश्वास करते हो, प्रचार करने में ज्यादा विश्वास करते हो। अगर काम में विश्वास करते, तो हमारे यहां एक सड़क बिलरियागंज से नौगवनापार को जोड़ती है। हमारे तमाम ऐसे किसान भाई, गरीब भाई अपने घर के मृत परिवार को अन्तिम संस्कार के लिए सरयू नदी पर लेकर जाते हैं। वहां पर सड़क गड्ढा मुक्त होना तो दूर की बात है, सड़क के नाम पर कुछ है ही नहीं। मैंने मा0 लोक निर्माण मन्त्री जी को, तमाम अधिकारियों को बार-बार पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कहते हैं ''सबका साथ, सबका विकास''। जब आप विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तब आप जनता के साथ ''सबका साथ, सबका विकास'' की क्या बात करेंगे ? मा0 अध्यक्ष जी, आपके समक्ष हमारे तमाम विधायकगणों ने यह बात रखी कि हम सारे विधायक एक बराबर हैं, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि सत्तापक्ष के विधायकों का प्रस्ताव लेकर मंजूर कर दिया, विपक्ष के विधायकों का प्रस्ताव अगर ले भी लिया, तो उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। यह आपका ''सबका साथ, सबका विकास''। यह सरकार पूरी तरीके से जनता को गुमराह कर रही है और जनता से जो वादे किये हैं, उनको पूरा नहीं कर रही है। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ समाप्त करते हुए कहूंगा कि- ''हो चुका तुमसे गरीबों का भला, रहने दो, अपने संदूक में चांदी का खुदा रहने दो, जाने किस वक्त शराफत का जनाजा निकले, देश की हुकूमत, दरवाजा खुले रहने दो'' जय हिन्द, जय समाजवाद। मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल जी।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

धन्यवाद, मा0 अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 विधायक श्री सुनील शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं यूं ही समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समर्थन कर रहा हूं। चार सौ पचास वर्षों के बाद पूज्य मुख्य मंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से पौराणिक अक्षयवट व सरस्वती कूप का दर्शन करने का सौभाग्य देश के करोड़ों हिन्दुओं को मिला है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, पौराणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैदिक कुम्भ का अविस्मरणीय, अतुलनीय, अकल्पनीय, अभूतपूर्व आयोजन करने के लिए मैं बलिया नगर विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से पूज्य माननीय मुख्य मंत्री जी का हार्दिक वन्दन व अभिनन्दन करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, 88 लाख किसानों के 01 लाख रुपये तक की फसली ऋण माफ करने वाली सरकार के द्वारा रिकार्ड 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर 11 लाख 27 हजार 195 किसानों को 9231.99 करोड़ रुपये की ऑन-लाइन भुगतान करने की मैं सराहना करता हूं। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी का संकल्प है कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के सभी बेघरों को, सभी निराश्रितों को हम पक्का आवास देंगे और उस दिशा में सरकार बहुत द्रुत-गति से आगे बढ़ रही है। मात्र 22 महीने के कार्यकाल में पूज्य मुख्य मंत्री जी ने 10 लाख 09 हजार आवास निर्मित करके प्रधानमंत्री आवास गरीबों को समर्पित किये हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में केवल 63 हजार आवास दिये गये। ये लोग केवल सत्ता के मद में चूर रहे, आम जनता से बिल्कुल कटे हुये अपने पूरे समय में इन लोगों ने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देने का कोई काम नहीं किया।

मान्यवर, प्रधानमंत्री आवास, शहरी और ग्रामीण दोनों योजनायें, 2011 में जो आर्थिक-सामाजिक जनगणना हुई उसके आधार पर जो सूची है उसके अनुसार आवास मिलता है। हम लोगों ने देखा, गांवों में, शहर में, अनेक गलियों-मोहल्लों में, ऐसे लोग जो आजादी के समय से घास-फूस की झोपड़ी में रहते रहे उनका भी नाम उस सूची में नहीं रहा। लेकिन 2011 के बाद, 2011 में प्रदेश में ब0स0पा0 की सरकार थी, केन्द्र में डॉ0 मनमोहन सिंह जी स0पा0-ब0स0पा0 के समर्थन से प्रधानमंत्री थे लेकिन सूचियों के बनाने में भारी फर्जीवाड़ा किया गया और गरीब, मजलूम लोगों को, जो बेघर थे, जो झोपड़ी में रहते थे उनके नाम उन सूचियों में नहीं रखे गये। हम लोग पूज्य मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम सभी विधायकों के आग्रह पर कि माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे लोग जिनका नाम सूची में नहीं है और बेघर हैं, तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक सर्वे करवाया और उसके बाद आवास प्लस एप के माध्यम से गांव-गांव में अभी 30 दिसम्बर तक हर गांवों में बेघर लोगों के फोटो खींचे गये और आवास प्लस एप पर अपलोड कराया गया है जिससे स्वभाविक रूप से सभी का आवास आना शुरू हो जायेगा। मैं इस बात के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 200 करोड़ रुपये से मुख्य मंत्री आवास योजना शुरू की और मैं अपने क्षेत्र बलिया नगर विधान सभा क्षेत्र के हल्दी-बबुरानी की हेमामालिनी राजभर की ओर से अग्निकांड में जिनका घर जल गया, पत्र लिखने पर केवल 04 महीने में हेमामालिनी राजभर के

खाते में 01 लाख 20 हजार रुपया पहुंचा है। हमारे धर्मपुरा गांव के सुरेन्द्र राजभर जो एक रिक्शा चालक थे उनकी मृत्यु होने पर उनकी विधवा को भी मुख्य मंत्री आवास में 01 लाख 20 हजार रुपया पहुंच गया है। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और पूरी सरकार का अभिनन्दन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार ने मां-बहनों के सम्मान में, पूरे उत्तर प्रदेश में 01 करोड़ 71 लाख शौचालय बनाने का काम किया है। स्कूलों में, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय जिससे बालिकाओं का विद्यालय जाने में उत्साह बढ़ा है और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, जो सपना है, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' उस अभियान को भी इस अभियान से बहुत बल प्रदान हुआ है। राजकीय इण्टर कालेजों में जो सहशिक्षा की व्यवस्था की गयी है उससे भी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है मैं उसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उस बात की चर्चा में नहीं जाना चाहूंगा, अनेक हमारे सदस्यों ने चर्चा किया है। किस प्रकार से आदरणीय योगी जी की सरकार बच्चों को स्कूल ड्रेस, किताबें, मोजे, जूते सब कुछ देती है। हमारे बहुत आदरणीय नेता श्री राम गोविन्द चौधरी जी नहीं हैं जो हमारे जनपद में स्व0 चन्द्रशेखर जी के बाद बहुत सम्माननीय नेता हैं, सभी दलों के लोग उनका सम्मान करते हैं लेकिन जब वह बेसिक शिक्षा मंत्री थे तो किस सोच के साथ जिस रंग के कपड़े की चड्ढ़ी अपने घर के बच्चों को नहीं दे सकते हैं। उस रंग का ड्रेस लगा दिया था। उसके बाद भी हमारी सरकार जो काम करती है उस पर उंगली उठाते हैं। इनको ऐसा कोई नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार को पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

उत्तर प्रदेश में कल से यू0पी0 बोर्ड की परीक्षायें प्रारम्भ हुई हैं। एक ऐसा समय था कि उत्तर प्रदेश से जो छात्र इण्टर करने के बाद, हाई स्कूल करने के बाद, दूसरे प्रदेशों में जाया करते थे, उनका सम्मान नहीं रहता था। समाजवादी पार्टी की सरकारें नकल की पर्याय हो गई थीं। लेकिन हमारी सरकार ने और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उप मुख्य मंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा की ऐसी आदरणीय सोच ने इस प्रकार का माहौल दिया है जिससे कि मेधावियों का सम्मान हो रहा है। 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी माननीय मुख्य मंत्री थे और हम लोग विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता के रूप में 2 फरवरी, 1994 को विधान भवन पर धरना प्रदर्शन करने आए थे और यह नारा लगाया था कि 'नकल नहीं हमें ज्ञान चाहिए, शिक्षा का सम्मान चाहिए।' आज योगी जी की सरकार में डॉ0 दिनेश शर्मा जी ने शिक्षा को सम्मान दिया है इसके लिए हम सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार ऐसा हुआ है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोह नहीं हो रहे थे। लेकिन सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोह सम्पन्न हुए हैं और सभी नियमित हुए हैं। मार्च तक सभी परीक्षायें हो रही हैं उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा। रिश्वत विहीन नौकरियां हो रही हैं चाहे वह ग्राम्य विकास अधिकारियों की नियुक्ति हों, पुलिस

कांस्टेबिल की नियुक्ति हो, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हों, गरीब नौजवान जो पैसे के अभाव में नौकरी से वंचित हो रहे थे उनके अन्दर एक विश्वास आया है कि हमारी सरकार आई है और मेधा और प्रतिभा को सम्मान मिल रहा है, मैं इस बात के लिए अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने संवेदनशील मुख्य मंत्री जी को, होमगार्ड के जवानों को, पी0आर0डी0 जवानों को, चौकीदार को असंवेदित क्षेत्र के मजदूरों, आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकत्री की हित चिन्ता के लिए मुख्य मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के क्षेत्र में जो हमारी सरकार, जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने सुधार किए हैं वह क्रान्तिकारी सुधार किए हैं उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 24 घंटे बिजली और 24 घंटे में ट्रांसफार्मर का बदला जाना, अब गांव का वो समय नहीं है जब गांव के लोग चन्दा इकट्ठा करके ट्रालियों और ट्रैक्टरों से ट्रांसफार्मर लेकर आते थे और पैसे देकर ट्रांसफार्मर बदलवाते थे उसमें भी एक महीना लगता था लेकिन सरकार ने जो काम किया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के लोग, अभी एक मांगलिक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता मिल गए जो लोहे का उद्योग करते हैं जिनका लोहे का बहुत बड़ा कारोबार है और सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि मैं आपकी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जबसे आपकी सरकार आई है तबसे हमारा जेनरेटर नहीं चल रहा है। बिजली पर्याप्त आ रही है जेनरेटर का तेल हमारा बच रहा है, बिजली व्यवस्था को उन्होंने भी सराहा है मैं इसके लिए भी पूरी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

माननीय अध्यक्ष जी राशन वितरण प्रणाली, अभी प्रश्नकाल में एक प्रश्न आया था और हमारे मा0 मंत्री जी ने बहुत आदरपूर्वक उत्तर भी दिया था कि दो करोड़ से ज्यादा हमने पात्रों के राशनकार्ड बनवाये हैं। अनेक ऐसे गांव हैं हमारे क्षेत्र में एक घघरौली गांव जो हन्ड्रेड परसेन्ट श्रमिकों का गांव है। बिन्द जाति का गांव है और हम लोगों ने दो बार कैम्प लगा करके साढ़े चार सौ से अधिक परिवारों को राशनकार्ड दिए हैं जो पिछली सरकारों में वंचित रहे हैं पिछली सरकारों में अन्त्योदय कार्ड की एक काल्पनिक लिस्ट बना ली गई। वहां के लोगों के द्वारा एक लिस्ट बना ली गई और उसी आधार पर वहां पर चलता रहा, लेकिन आज शहरों में हर प्रकार की समस्या का समाधान हो गया है। जबसे ई-पास मशीन लगी है। एक सदस्य चर्चा कर रहे थे कि मुखिया बाहर रहता है अंगूठा नहीं लग पाता है। मैं सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि मुखिया के साथ-साथ परिवार के जितने सदस्यों का नाम उसमें होता है सभी का आधार लिंक होता है और उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति जाता है अंगूठा लगाता है तो उसे राशन मिलता है ऐसी संवेदनशील सरकार के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं इस सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बलिया नगर विधान सभा क्षेत्र में रोजगार के लिए उद्योगों की स्थापना हो। अमर शहीद मंगल पाण्डेय की जन्मभूमि होने

के नाते बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को ले जाया जाए। बलिया में त्वरित और उचित चिकित्सा सुविधा के लिए बलिया में मेडिकल कालेज की स्थापना की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे भारत में महर्षि भृगु का मंदिर बलिया में स्थापित है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बलिया के इस भृगु मंदिर को तीर्थ पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा गंगा किनारे हमारा शहर है।

माननीय अध्यक्ष जी, धरनीपुर भरसर से हल्दी भरसौता तक बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए पक्के बांध का निर्माण कराया जाए। सुरहाताल में फुलवरिया से बसन्तपुर तक वर्ष भर जल जमाव रहता है, उसके लिए सरकार किसानों को उससे मुक्ति दिलाए।

श्री अध्यक्ष-

शुक्ला जी अब आप समाप्त करें।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय को भूमि देने के लिए, पद देने के लिए और धन देने के लिए अपनी सरकार का और उच्च शिक्षा मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहूंगा। आम लोगों को, अन्तिम पंक्ति में खड़े लोगों को सेवा देने के लिए यह सरकार जिस प्रकार से लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, उससे घबराकर इन लोगों ने जो गठबंधन किया है, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि यह गठबंधन नहीं यह लोगों के डर से डरबंधन है और जनता को, टिकटार्थियों को ठगने के लिए यह ठगबंधन है। हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा रोज हल्ला मचाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मा0 सदस्य श्री उमाशंकर सिंह जी तो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं। हमारे जिले में किसी भी विधायक के पास 5 करोड़ रुपये नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य उमाशंकर सिंह जी के पास 1 महीने पहले 5 करोड़ रुपया पहुंच गये हैं। मैं चाहूंगा कि आप जानकारी कर लें। मैं प्रमाणिक आधार पर कह रहा हूं। अभी हमारा पैसा नहीं गया है, लेकिन मा0 सदस्य उमाशंकर सिंह जी का पहुंच गया है। यह सरकार भेदभाव करने वाली सरकार नहीं है। इन लोगों ने भेदभाव किया है और आज इनकी वही मानसिकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास में अगर द्रौपदी ने दुर्योधन और दुशासन के साथ समझौता कर लिया होता तो द्रौपदी को इतिहास माफ नहीं करता। अगर माता सीता रावण की हो गयी होती तो माता सीता की आज पूजा नहीं होती, इतिहास माफ नहीं करता। इलाहाबाद और फैजाबाद

का नाम बदले जाने पर इन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि वीर सावरकर की बातों को न मानियेगा, दीनदयाल उपाध्याय की बातों को न मानियेगा, अटल विहारी बाजपेई की बातों को न मानियेगा, लेकिन डॉ0 राम मनोहर लोहिया ने 3 अक्टूबर, 1967 को हैदराबाद में कहा था भारतवर्ष के मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि राम और कृष्ण उनके पूर्वज थे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, गजनी, गौरी, बाबर हमलावर थे, इसलिए उनका अनुकरण नहीं करेंगे। उनके नाम पर कुछ भी स्थापित नहीं करेंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि कुम्भ का राजनीतिकरण किया गया है, अगर सड़कों का चौड़ीकरण करना, अगर चौराहों का सौन्दर्यीकरण करना, अगर मेला क्षेत्र का विस्तार करना, अगर अक्षयवट का दर्शन कराना, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराना, शौचालयों का निर्माण करवाना, अगर यह राजनीति है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ठीक है। मैं कहना चाहूंगा कि आतंकवादियों का समर्थन करना, जातिवाद करना क्या यह राजनीति नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में यह कहते हुए कि मैं मा0 राज्यपाल जी का और अपनी सरकार का बहुत-बहुत समर्थन करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मा0 सदस्या श्रीमती साधना सिंह जी को आमंत्रित करता हूं।

*** श्रीमती साधना सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करती हूं, आपको बधाई देती हूं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं, मा0 वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं। जब सदन चलता है तो हम लोग कुछ सीखने आते हैं और सीखने के बाद कुछ ऐसी बोलचाल की भाषा लेकर जाते हैं जिसको देखने के बाद लगता है कि 5 लाख की जनता ने हमको बात रखने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, जो विकास हो रहा है, उसको बताने के लिए चुनकर भेजा है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों को सच्चाई कहने से डर लगता है। जैसे एक सायर ने कहा ''क्या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गजब डर है मोदी और योगी का, जो एक-दूसरे को बेवफा कहते थे, आज वफाई की कसमें खाते हैं।'' जो शोर मचाते हैं भीड़ में गठबंधन करके, वह ''भीड़ बनकर रह जायेंगे, भीड़ बनकर रह जायेंगे।'' वही लिखेगा इबादत जो खामोशी से अपना काम चलाएगा और हम सब कार्य में विश्वास रखते हैं, विकास में विश्वास रखते हैं और सच्चाई तो सामने है जनता के बीच में यह सच्चाई दिख रही है और दिखेगी भी। एक गठबन्धन जो ठगबन्धन हुआ है यह जनता पूर्ण रूपेण मान रही है कि विकास का विरोध है और किस व्यक्ति को, किस नौजवान को, किस किसान को, किस व्यापारी को, किस मजदूर को, किस अधिवक्ता को, किस डाक्टर को बिजली पानी, रोड, शिक्षा, स्वाथ्य किसको नहीं चाहिए कसम खा लें सबके पास अपना ईष्ट है आप पूर्व और वर्तमान देखें रोडें कैसी थीं आज रोडें चमचमाती हैं, 18 से 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है। किसानों की धान की खरीद हो रही है, नौजवान को रोजगार मिल रहा है बेटियों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है नहीं तो बेटी पैदा होती थी तो घरों में चूल्हे नहीं जलते थे आज बेटियां पैदा हो रही हैं तो उत्सव मनाया जा रहा है उनकी बरही और छठी मनाई जा रही है। उनका जन्म दिन मनाया जा रहा है अब उस मां को डिलीवरी के बाद पीड़ा नहीं सहना है क्योंकि यह सरकार उसकी जन्म से लेकर शिक्षा से लेकर उसके ब्याह की चिन्ता इस सरकार ने किया है हम इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी को बधाई देते हैं, योगी जी को बधाई देते हैं, अपनी सरकार को बधाई देते हैं कि आपने जो भ्रूण हत्या बेटियों का गर्भ में मारा जाता था मां विवश हो जाती थी कि मेरी बेटी पैदा होगी तो कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे हम ब्याह करेंगे उसकी चिन्ता हमारी सरकार ने लिया और हमारी सरकार ने एक विचार रखा सबका साथ सबका विकास के साथ कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आज हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की मां हैं और हम कल्पना करते हैं अपने क्षेत्र में सब माताओं से कि मेरी बहनें आपकी सरकार है आपके लिए बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य सब दे रही है आपकी बेटी की चिन्ता कर रही है। जैसी कि पूर्व की सरकारें दवाई के अभाव में गरीब जनता इतनी मंहगी दवाई, इतना मंहगा इलाज, इतना मंहगा आपरेशन रहता था किसी को हार्ट अटैक होने के बाद इतनी मंहगी दवाई कैंसर के इतने मंहगे इंजेक्शन थे कि गरीब जनता वहां नहीं पहुंच पाती थी आज हमारी सरकार ने दवा इतनी सस्ती कर दी है, इलाज इतना सस्ता कर दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति ब्रेन हैमरेज से नहीं मर सकता, कैंसर से नहीं मर सकता, हार्ट अटैक से नहीं मर सकता क्योंकि तमाम दवाइयां सस्ती हो चुकी हैं और हमारी सरकार ने इतनी अच्छी-अच्छी योजना गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए चलाई है कि अब हमारे क्षेत्र की जनता सहित पूरे प्रदेश की जनता पूरे देश की जनता अपने आपमें राम लहर महसूस कर रही है। हमारे क्षेत्र की महिलाएं आदरणीय अध्यक्ष जी मेरे यहां मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर रखा गया है पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर की बहनें मेरी मातृशक्ति मेरे चंदौली जनपद की माताएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सरकार ने ऐसी योजना चलाई है कि मेरी बहनें आत्म बल

के साथ पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं और रोजगार दे रही हैं गांव में महिलाएं अपने पुत्र और पति के सामने हाथ फैलाए बिना व्यवस्था बना रही है। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिसे हमारी सरकार ने कल्पना किया कि गरीब जनता को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा आज इस योजना का लाभ पूरे प्रदेश के गरीबों को मिल रहा है बुनकरों को अच्छी बिजली मिल रही है नहीं तो बुनकरों को वोट का जो लुभावना देते थे कि आप मेरे हो, लेकिन बिजली नहीं मिलेगी और बिजली न मिलने की वजह से क्षेत्र में बुनकरों के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। आज हमारे क्षेत्र के बुनकर एकदम मजबूती के साथ आबाद हैं, उनको 24 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे बिजली मिल रही है।

हमारा क्षेत्र चन्दौली जनपद 97 में जनपद घोषित हुआ और हम लोगों ने लाठियां खाईं। सपा की सरकार आई और इन लोगों ने जिले को तोड़ दिया। हम लोगों ने आन्दोलन किया और हाईकोर्ट ने जनपद को बहाल रखा। अधिवक्ताओं के ऊपर इन लोगों का ऐसा कहर बरपा कि हमारे क्षेत्र के हमारे चन्दौली जनपद के अधिवक्ताओं को अब जाकर टीन शेड नसीब हुआ है, हमारी सरकार ने अब उनके लिये जगह अलॉट कराई है नहीं तो हमारे चन्दौली जनपद के अधिवक्ताओं ने पिछली सरकार का इतना उत्पीड़न झेला कि आज जनपद बने 17 से 18 साल हो गये, लेकिन उनके लिये कोई स्थान नहीं बना, न मुख्यालय बना, न ही कोई ऑफिस बना। सारे ऑफिस, सारे अधिकारी बनारस में रहते थे और एक-एक रूम में ऑफिस चलता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सारे मुख्यालय बन रहे हैं, सारे क्वार्टर बन रहे हैं, सारे ऑफिस बन रहे हैं। आज हमारा चन्दौली जनपद जगमग-जगमग कर रहा है। अच्छी रोडें मिल गयीं, अच्छी बिजली मिली, धान की अच्छी खरीद हुई, किसानों को खाद मिल रही है और चाणक्य ने कहा है कि जब सारे विरोधी एक तरफ हो जाएं तो समझ लो मुकाबला किसी ईमानदार से है और ईमानदारी दिख रही है। इनमें बौखलाहट है, बेचैनी है, ब्लड प्रेशर हाई है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो गये हैं, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, आप देख रहे हैं कि गोले मारते-मारते अटैक हो जा रहा है, बी0पी0 बढ़ जा रहा है और पता नहीं चल रहा है जमीन धंसक जा रही है। अरे मेरे भाई, हम लोगों ने इतनी अच्छी-अच्छी योजनाएं ही चलाई हैं। आप अपना ब्लड प्रेशर नार्मल कीजिये, डायबिटीज कंट्रोल में कीजिये, अपना इलाज कराईये और सरकार की जो सच्चाई है उसको बताईये।

मा0 अध्यक्ष जी, हम एक गांव की कहावत कहते हैं और आपके बिना कहे ही हम बैठ जायेंगे। एक बुआ और बबुआ की कहावत थी, एक ननद-भौजाई का झगड़ा था तो बुआ को लगा कि भौजाई दुरूस्त तभी होगी जब भाई इनकी औलाद को इनसे दूर करेंगे। तो ननद भौजाई के घर गयी और कहा भाभी हमारी परिस्थिति कुछ खराब है हम आपके घर पर रहकर आपकी सेवा भाव करना चाहते हैं, आपके बच्चों की सेवा करना चाहते हैं। भाभी को लगा कि इतनी अच्छी दाई मिल गयी, इससे बढ़िया क्या है कि दो जून की रोटी मिलेगी और मेरे बच्चों की सेवा करेगी और बुआ ने बबुआ को गोद में उठाया और बबुआ को एक मिनट के लिये भी

जमीन पर न बैठने दिया। बबुआ चलना भूल गया, बबुआ बोलना भूल गया, बबुआ खाना भूल गया, बबुआ दिव्यांग हो गया। स्थिति यह बनी कि जब 05 साल हुआ तो लोग कहे कि का भईया, तोहार लरिकवा चलत नहीं का, तो कहे कि पता नहीं दीदी तो दिनवै भर तोहरा में लदलै रहे लीन, अब बेचारे इतना सेवा करै लिहिन कि हमारे लरिका का कब्बौ जमीन पर उतरे नहीं देहलिन ऐसे लागेला बबुला तो दूसरे पड़ोसिन ने कहा कि तोहार ननद तोहसे बैर खै लीन है तो कहे का, कैसे बैर खै लीन ? तोहरे लरिका का दिव्यांग बना देहलिन। अगर तोहर लरिकवा चलै सीखले रहत तो दौड़त, तोहार लरिका के अपने हाथ से खिलौलिन, अपने पैर से चलौलिन, अपने आंख से तकौलिन और ऐसे तोहार लरिका दिव्यांग हो गईल, तोहार लरिका विकलांग हो गईल। इस नाते उत्तर प्रदेश में बबुआ और बुआ का जो गठबन्धन है वह दिव्यांग का गठबन्धन है। इस नाते उसी तरह से यह बबुआ चलना भी भूल जायेगा, बोलना भी भूल जायेगा, खाना भी भूल जायेगा और जमीन धंसक जायेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ऐतिहासिक मूड में है और उत्तर प्रदेश की जनता आपके विकास की और आपके कार्य की समीक्षा देख रही है। और इनके बाधा डालने का भी कार्य देख रही है, इस नाते ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जनता तैयार है। ये भी आ जायें मैदान में, हम सब भी चलते हैं मैदान में, लोक सभा में आमने-सामने वार होगा, देखना होगा कि किसके बाजुओं में दम है। अध्यक्ष जी, जनता हमारे विकास पर विश्वास कर रही है और इनका ठगबंधन, गठबंधन इनकी बेचैनी साबित करता है, अगर अपने आप में इतना दम होता तो यह गठबन्धन नहीं होता। एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, लॉलीपॉप देख रहे हैं, अरे 'जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।' आपका जो देश और राष्ट्र के प्रति भाव और प्रेम होना चाहिए, वह सब समाप्त हो गया है। आप लोग बढ़िया-बढ़िया बंगले, बढ़िया रहन-सहन के लिए विवश हैं, अच्छी बात तो बताइये, अच्छी बात को समझिए, अगर इतने ताकतवर होते तो सारे लोग इस तरह इकट्ठे नहीं होते। लेकिन वोट तो जनता को देना है, न हमको देना है, न आपको देना है। ए0के0 47 आप लोग चलाते हैं, अध्यक्ष जी, अगर चेकिंग न हो तो ये लोग कागज के गोले नहीं चलाते, 47 चला देते, इस सदन में (हंसी) और हम लोग समाप्त हो जाते। अध्यक्ष जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, जय-हिन्द, जय भारत माता।

(सदस्य, श्री मनोज कुमार पारस और श्री अमिताभ बाजपेई के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी बोलेंगे कि अमिताभ जी ?

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, अमिताभ जी कह रहे कि अध्यक्ष जी यदि सोमवार की सुबह बोलने की अनुमति दे दें तो हम उस दिन बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों लोग आपस में सलाह कर लीजिए, तब तक तीसरे सदस्य बोल लें।

(हंसी)

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया और माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय राम गोविन्द साहब ने अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी वर्तमान सरकार का, चल रही योजनाओं का, आने वाली योजनाओं का एक प्रतिबिम्ब होता है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार जनता के साथ तो छल कर ही रही है, भ्रमित कर ही रही है, धोखा दे ही रही है, झूठे सपने दिखा ही रही है। आप लोगों ने तो माननीय राज्यपाल जी को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी सत्यता से कोसों दूर, जमीनी हकीकत से बिल्कुल विपरीत, झूठे सपने के इस पुलिन्दे को पढ़वाने का काम कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जिस सरकार को इस प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिलाया, उत्तर प्रदेश में भी और हिन्दुस्तान की सरकार में भी, जब आप उन्हीं से झूठ बोल सकते हैं तो आपकी नजर में माननीय राज्यपाल महोदय की भी क्या हैसियत हो सकती है, इस पुलिन्दे से पता चलता है। मान्यवर, आगे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून की क्या व्यवस्था है, यह किसी से छिपी नहीं है, पूरा प्रदेश जानता है। इस प्रदेश का बच्चा-बच्चा आज खौफ के माहौल में जी रहा है, डर के जी रहा है। किस लिये डर के जी रहा है, आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले आगरा में एक घटना हुई, जिसमें दलित समाज की, एक अनुसूचित समाज की बच्ची को जिन्दा जला दिया गया। वह आगरा जो विश्व-विख्यात जगह है, वहां सरेआम, उसी दिन जब वहां पर उत्तर प्रदेश के डी0जी0पी0 महोदय समीक्षा कर रहे थे, मीटिंग ले रहे थे तो शाम को 4:00 बजे वहां के भगवान टॉकीज से सरेआम एक बालिका को अगुवा कर लिया जाता है और सरेआम उसके साथ बलात्कार किया जाता है और माननीय अध्यक्ष जी, यह बात यहीं पर नहीं रुकती। इसी तरह इस क्षेत्र में हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, डकैती, लूट-पाट, अपहरण, ठगी और चोरी की 01 सितम्बर से 01 फरवरी तक 521 घटनाएं घटी हैं और माननीय अध्यक्ष जी, बड़े शर्म की बात है कि आज से 4 साल पहले अगर बलात्कार जैसी शर्मनाक घटनाएं उत्तर प्रदेश में औसतन 4 घटती थी, आज वह औसत बढ़कर 52 हो गया है।

मान्यवर, बुलन्दशहर में सरे आम एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है और उसका वीडिओ वायरल किया जाता है। जब एक इंस्पेक्टर की हत्या सरेआम कर दी जाती है तो प्रदेश की जनता कैसे खुशहाल हो सकती है ? मान्यवर, इस सरकार ने मा0 राज्यपाल जी के

अभिभाषण में यह पढ़वाया कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो रही है। आम आदमी को घर से निकलने में कोई भय नहीं लगता। यह बड़े शर्म की बात है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि यहां विपक्ष और हमारे उत्तर प्रदेश के पत्रकार महोदय उपस्थित हैं। वह सारे लोग आपकी आंखें खोलकर समय पर आपको आईना दिखाना चाहते हैं कि बहुत अच्छा होता अगर कोई ऐसी योजना लाई जाती कि जिससे कि इन अपराधों को रोका जाए और हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध शून्य तक पहुंच जाता तो अच्छा होता, लेकिन यह सरकार तो ठोंको की नीति पर काम कर रही है। पता नहीं यह सरकार किस घमण्ड में काम कर रही है। ऐसे में एक शायर ने कहा है कि-

''सुबह मगरूर को वह शाम कर देता है,
शौहरते छीनकर वह गुमनाम कर देता है।
वक्त से आंख मिलाने की हिमायत न करो,
वक्त इंसान को नीलाम कर देता है।।''

मान्यवर, यह सरकार किसानों की बहुत बड़ी हितैषी है और यह बहुत ढिंढोरा पीट रही है कि किसानों के लिए हमने यह किया, किसानों के लिए हमने वह किया ? आज गरीब किसान ठंड में, तपती हुई धूप में इस धरती मां का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है और आपको, हमारे बच्चों को तथा इस प्रदेश को अन्न खिलाने का काम करता है। आज उसी किसान से झूठ बोलकर उसे झूठे-झूठे सपने दिखाने का काम किया जा रहा है। आज खाद महंगी है, सिंचाई महंगी है और उसकी फसल की लागत भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि इतनी महंगाई में मजदूरी महंगी हो गई है और इस महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मान्यवर, किसान सरकार की नीतियों के कारण अपनी फसल को औने-पौने दामों में दलालों के हाथों बेचने को मजबूर है। खरीदे गये धान को आज तक जिन कम्पनियों ने खरीदा है उसने किसान का पैसा भी नहीं दिया है। आलू का किसान सड़कों पर आलू फेंक रहा है और गन्ने के किसान की क्या स्थिति है ? गन्ने का किसान कितना मजबूर है ? मैं उस जनपद से आता हूं जहां पर गन्ना पैदा होता है जिसे अग्रणी जनपद में गिना जाता है। हमारे यहां 9 चीनी मिलें हैं और उन 9 चीनी मिलों पर पिछले साल का 60 करोड़ रुपया बकाया है। इस वर्ष का भी 510 करोड़ रुपया बकाया है। अभी 3 तारीख की घटना थी कि जब हमारे जिले का किसान अपना पिछला बकाया मांगने के लिए आत्महत्या करने को मजबूर हो गया तो उन्होंने जिला प्रशासन को एक नोटिस दिया कि अगर 3 फरवरी तक हमारा पेमेंट नहीं किया गया तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनकी किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी और किसी ने भी मिल प्रशासन से बात नहीं की और 3 तारीख आ जाती है तो सारे किसान इकट्ठा होते हैं और अपनी चिता में आग लगाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगते हैं तो भी कोई अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए नहीं आता है। उस समय अगर कोई आता है तो वह पुलिस आती है और जो बेजुबान

अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे थे उन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाता है। लाठी चार्ज करने के बाद कम से कम 50 किसान घायल हो जाते हैं। दो किसानों की हड्डी तोड़ दी जाती है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने उन मिल वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की बल्कि कार्रवाई की तो उन गरीब किसानों के खिलाफ की और उसमें दस लोगों को जेल में डाल दिया। मान्यवर, जिस तरह का बजट प्रस्तुत हुआ है और केंद्र सरकार ने भी बजट प्रस्तुत किया है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने 6 हजार रुपये उन लघु किसानों को जिनके पास अधिक से अधिक 25 बीघा जमीन है। उनको 6 हजार रुपये सलाना देने की घोषणा की है। मान्यवर, यह कितने शर्म की बात है ? यह कितने दुख की बात है कि वह अन्नदाता जो सबका पेट भरता हो और सबको रोजी-रोटी देता हो तथा जो सबके बच्चों का पालन-पोषण करने का काम करता हो उस किसान को मात्र 500 रुपये महीना क्योंकि विधवा पेंशन भी मात्र 500 रुपये प्रतिमाह है। निराश्रित महिला पेंशन भी 500 रुपये प्रतिमाह है। दिव्यांगजन पेंशन भी 500 रुपये प्रतिमाह और कितने अच्छी बात है कि अन्नदाता को 500 रुपये प्रतिमाह का सम्मान दिया जाता है, यह आपकी सोच है। क्या आप इसी तरह उत्तर प्रदेश के किसानों का भला करना चाहते हैं ? क्या आपकी यही नीति है ?

मान्यवर, बिजली के क्षेत्र में भी बहुत बड़े-बड़े प्रचार किये जा रहे हैं। मान्यवर, मा0 मंत्री जी बैठे हुए हैं। वह हमारे सम्मानित मंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी भी हैं। वहां पर बहुत प्रचार किया जा रहा है कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया की 94 लाख बिजली कनेक्शन उन्होंने फ्री में दिये हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, 94 लाख विद्युत कनेक्शन फ्री में नहीं दिये। मैं दावे से कह सकता हूं कि दो से तीन हजार रुपये अवैध वसूली तक की गयी है और उस दौरान कनेक्शन में जितने मीटर लगे उन मीटरों की कीमत बिलों में जुड़कर आ रही है और कहा जा रहा है कि फ्री में कनेक्शन देते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यही बिजली हमारी पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय बहन मायावती जी की सरकार में थी। यही बिजली हमारे नेता करोड़ों-करोड़ों लोगों के दिलों की आवाज हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समय में भी यही बिजली थी। आपने बिजली में कोई बदलाव नहीं किया और उस समय जो बिजली मिलती थी तो एक गांव के व्यक्ति को एक किलोवाट के लिए 223 रुपये फिक्स बिल देना पड़ता था। जो कुछ दिनों बाद में बढ़कर 315 हो गया था। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन मीटर गांव में लग जाता है उस किसान पर 840 रुपये का बिल चढ़ जाता है। यह सस्ती की है बिजली। जो किसान मेहनत मजदूरी करके अन्न पैदा करना चाहता है उस पर बिजली की इतनी मार पड़ेगी, डीजल की मार इतनी पड़ेगी तो आखिर वह किसान कहां जायेगा। मान्यवर, 18 से 20 घण्टे बिजली का बहुत प्रचार किया जा रहा है। लेकिन हमारे जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 12 घण्टे बिजली आती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक किरनपुर में छितावर फीडर है। वहां पर रात में मात्र 8-9 घण्टे बिजली आती है और

दिन में मात्र 2-3 घण्टे बिजली आ रही है। कुल मिलाकर मात्र 12 घण्टे बिजली आ रही है। यह हाल बिजली का है।

मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। स्वास्थ्य के बारे में श्री राज्यपाल से स्वास्थ्य के बारे में झूठा जिक्र इस झूठ के पुलिन्दे में कराया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकारों की तुलना में पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 या जिला चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या बढ़ी नहीं है बल्कि मरीजों की संख्या कम हुयी है। आज लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों से उठ रहा है। लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं क्योंकि सरकारी डाक्टर कमीशन के चक्कर में दवा का प्रेस्क्रिप्शन बाहर से लिख देते हैं। और तो और जो कुत्ता काटने के बाद इंजेक्शन लगता है। एंटीरेबीज का इंजेक्शन भी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में नहीं मिलता है। डाक्टरों की भारी कमी है। आवास के बारे में भी कहा जा रहा है कि गरीबों के आवास हेतु सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत, मा0 मुख्य मंत्री योजना के तहत आवास बनवाने का काम कर रही है और मान्यवर, आंकड़ा भी दिया गया है कि 10.09 लाख आवास बन चुके हैं। 9.33 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं। मान्यवर, यह मकान हमें कहीं जमीन पर तो बने हुये दिखायी नहीं देते हैं। मैं अपने जनपद बिजनौर की बात करना चाहता हूं कि जनपद बिजनौर में एक साल से जांच चल रही है। एक लाख 20 हजार रुपये मकान के लिये और जांच के नाम पर 30 हजार रुपये ले लिये। 90 हजार रुपये बच रहे हैं पता नहीं वह भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि मार्च में आचार संहिता लग जायेगी और उसके बाद मुझे अच्छी तरह पता है कि केंद्र में आप लोग नहीं आ रहे हैं। जब आप नहीं आयेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, हमारे बिजनौर में एक कहावत है कि जहां पर जानवर बंधते हैं उसे साल कहा जाता है इस महंगाई के दौर में 90 हजार में तो आज जानवरों की साल नहीं बनती मकान कैसे बनेगा। अगर मकान बनवाना चाहते थे तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी की तरह अपने दिल को बड़ा करें और तीन लाख पच्चीस हजार रुपये से लोहिया आवास बनवाकर उन गरीबों को दें उनका सम्मान करें तो हम भी यह सोचते कि आने वाली सरकार गरीबों के प्रति हमदर्दी रखती है। मान्यवर, मुझे पता है कि आप और ज्यादा बोलने का समय नहीं देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं उस समाज से आता हूं जो सैकड़ों वर्षों से दबाया गया है। मैं अनुसूचित जाति से आता हूं। मान्यवर, उस समाज के उत्थान के लिए श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसी योजना का जिक्र नहीं है। बल्कि इसके विपरीत जो हमारे परमपूज्य बाबा साहब भीम राव आम्बेडकर जी ने हम लोगों को जीने का हक दिया। हम

शोषितों को, वंचितों को यहां लाकर खड़ा करने का, बोलने का मौका दिया। जिनकी वजह से हमारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, डाक्टर, इंजीनियर बनने का काम करते हैं। मान्यवर, आज उसी आरक्षण को खत्म करने के लिए बार-बार कदम उठाये जा रहे हैं, जिसका उदाहरण पांच मेडिकल कालेज हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय सुबह आ चुका है इसको दोहराने की क्या जरूरत है ?

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही तरीका अपनाया जा रहा है क्योंकि एक जिले में इकाइयों के हिसाब से वैकेन्सियां निकाली जाती हैं और वैकेन्सियां निकालने के बाद आरक्षण को शून्य करके भर्तियां कर दी जा रही हैं। गरीब तबके के पढ़े-लिखे लोग जो फोर्थ क्लास श्रेणी में कहीं न कहीं नियुक्त हो जाते थे लेकिन उस आरक्षण को शून्य करने के लिए फोर्थ क्लास श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों को बन्द कर दिया गया है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों की भर्तियां की जा रही हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस झूठ के पुलिन्दे को जिसे राज्यपाल महोदय से पढ़ाया गया उसके विरोध में बोलते हुए मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी के प्रस्ताव को बल देते हुए वर्तमान सरकार का घमण्ड तोड़कर हकीकत से रू-ब-रू होने की सलाह देते हुए अपने गठबंधन की तरफ से एक शेर कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा लेकिन हमारी सम्मानित विधायिका महोदया चली गई हैं। उन्होंने 48 दलों का गठबंधन चलाया और 48 दलों का गठबंधन चला रहे हैं लेकिन इन लोगों के अन्दर 2 दलों के गठबंधन से खौफ एवं डर पैदा हो गया है। इस खौफ एवं डर को देखते हुए एक शेर कहना चाहता हूं कि-

''गुरूर तम्कनत का जोर कम करना भी आता है, गुरूर तम्कनत का जोर कम करना भी आता है, जमीनें संघ की शक्ति को नम करना भी आता है, तेरे सर से हटाकर यह ताज साबित करेंगे हम कि हमें अकड़ी हुई गर्दन को खम करना भी आता है।''

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नरेन्द्र पाल सिंह जी उपस्थित नहीं हैं। श्री ओम कुमार, बिजनौर उपस्थित नहीं हैं। श्री चौधरी उदयभान सिंह जी उपस्थित नहीं हैं। श्री जवाहर लाल राजपूत जी उपस्थित नहीं हैं।

डॉ0 संगीता बलवन्त-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया था लेकिन मैं उस समय उपस्थित नहीं थी कृपया मुझे बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप बोलिए।

डॉ0 संगीता बलवन्त-

मान्यवर, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर मिला इसके लिए सर्वप्रथम मैं विधान सभाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। भारतीय जनता पार्टी के जनकल्याणकारी कार्यों को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है और जब 5 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो वह उससे हताश एवं निराश होकर उन पर कागज के गोले बरसाये। मैं विपक्ष के कारनामों को दो पंक्तियों में कहना चाहूंगी कि-

''जो आये हैं कागज के गोले चलाने, भाजपा सरकार की कमियां बताने, जो आये हैं कागज के गोले चलाने, भाजपा सरकार की कमियां बताने, जिन्होंने लुटाये थे सैफई मंचों पर दौलत, जिन्होंने लुटाये थे सैफई मंचों पर दौलत, चले हैं वह सूरज को दीपक दिखाने, चले हैं वह सूरज को दीपक दिखाने।''

पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का स्वप्न देखा था। उत्तर प्रदेश वनटांगिया, वनवासी एवं मुसहर जैसे उपेक्षित पड़े समाज को जो विकास से कोसों दूर थे, मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे जिनके बारे में अभी तक किसी ने सोचा तक नहीं था उनके गांवों को राजस्व गांवों का दर्जा देकर उन गांवों में विशेष रूप से समस्त शासकीय सुविधाओं को प्रदान किया गया है चाहे वह आवास निर्माण का कार्य हो, चाहे वह शौचालय निर्माण का कार्य हो, चाहे वह विद्युतीकरण करके गांवों में उजाला करने का कार्य हो या बच्चों की प्रगति के सबसे बड़े शस्त्र शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें विद्यालय तक पहुंचाने की मुहिम का कार्य हो। तमाम सुविधाएं वनवासी समाज को प्रदान करने का ऐतिहासिक कार्य योगी सरकार द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 8 नवीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्य करा रही है। देवरिया, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, हरदोई तथा एटा के अलावा मेरे गाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है। जो गाजीपुर जनपद के विकास में मुख्य भूमिका निभाएगा, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पूर्व गरीबों को अपने परिजनों का इलाज जेवर गिरवी रखकर, खेत बेचकर, कर्ज लेकर कराने की विवशता रहती थी लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 13 लाख 81 हजार 720 गोल्डेन कार्ड इस योजना के माध्यम से बनवाये जा चुके हैं तथा 28 हजार 196 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस योजना से सरकार ने यह साबित कर दिया है कि सरकार गरीबों और बेसहारों की है और सरकार पैसे तथा इलाज के अभाव में किसी गरीब को दम तोड़ने नहीं देगी।

किसी क्षेत्र का पूर्ण विकास करने के लिए वहां का औद्योगिक विकास अत्यंत आवश्यक होता है। मैं पूर्वांचल की हूं और पूर्वांचल क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए लखनऊ से गाजीपुर तक लगभग 341 किलोमीटर लम्बाई वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रदेश के वित्तीय स्रोतों से कराया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे से गोरखपुर को जोड़ने के लिए लगभग 91 कि0मी0 लम्बे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं पूर्वांचलवासियों की तरफ से सरकार को बधाई देना चाहती हूं। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर तथा कानपुर हवाई अड्डों पर नियमित वायुसेवा उपलब्ध है इसके अतिरिक्त नए हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। इसमें मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, बरेली के हवाई अड्डे सम्मिलित हैं। रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अन्तर्गत अयोध्या, सहारनपुर, कुशीनगर और मेरे गाजीपुर जिले में हवाई अड्डे का विकास प्रस्तावित है। विकास के इस तोहफे के लिए भी गाजीपुर वासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाजीपुर जैसे पिछड़े जिले में हवाई अड्डे का निर्माण कर असली हवाई जहाज उड़ाकर विकास के नये आयाम खड़े कर रही है और विपक्ष माननीय राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर कागज के गोले और हवाई जहाज फेंककर अमर्यादित कार्य किया है जिसे प्रदेश ही नहीं पूरे देश ने देखा है। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जन-प्रतिनिधियों द्वारा यह हरकत निन्दनीय है। सरकार की प्रत्येक योजना को इतने कम समय में गिनाना सम्भव नहीं है, लेकिन जन-कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को न सिर्फ विकास की पटरी पर उतारा है बल्कि इन दो वर्ष में विकास दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं सदन के माध्यम से जमानिया राष्ट्रीय राजमार्ग से चोचकपुर होते हुए सैदपुर तक स्टेट हाई-वे बनाने की मांग करती हूं। यह मार्ग दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता है, इसकी लम्बाई लगभग 35 कि0मी0 है और अन्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि अपनी जन-कल्याणकारी योजनाओं, 'सबका साथ, सबका विकास' के माध्यम से योगी सरकार उत्तर प्रदेश को हर दिन सुन्दर, समृद्ध और सशक्त बनाने में लगी हुई है। इस सफल कोशिश से वह दूसरे को भी सन्देश देने का कार्य कर रही है और दूसरे प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश का अनुसरण भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने आपको नागरिकों और जनता की सेवा में लगा रही है उसको मैं दो पंक्तियों में कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। पंक्तियां हैं-

सुन्दर से सुन्दर की तलाश करो।
मिल जाए नदी तो समुन्दर की तलाश करो।।
टूट जाते हैं आईने पत्थर की हर चोट से।
टूट जाए पत्थर ऐसे आईने की तलाश करो।।

धन्यवाद जय हिन्द, जय भारत।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आज ही इसको जारी करा दें। मान्यवर, निवेदन यह करना है कि आज शुक्रवार है और बहुत से लोगों के परिवार में तमाम लोगों के यहां शादी विवाह भी है तो आज इसको जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष-

शादी वाली बात संसदीय कार्य मंत्री जी कहां सुनते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इतना बढ़िया शेर हो गया दूसरा कोई इससे अच्छा बोलेगा नहीं। थोड़ा-थोड़ा आज जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी।

*** श्री संजय-**

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। उस पर मैं आपका हृदय से साधुवाद और धन्यवाद प्रकट करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बहुत देर से बैठा-बैठा सदन में सुन रहा था कि तमाम हमारे विपक्ष के साथी किसानों की बात कर रहे थे, गन्ने की बात कर रहे थे, गेहूं की बात कर रहे थे तो मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि जो विपक्ष के साथी गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा अगर चीनी मिलें बन्द हुई हैं तो वह विपक्ष में बहन मायावती जी की सरकार में बन्द हुईं। यह क्या गन्ना किसानों की बात करेंगे, इन्होंने तो गन्ना किसानों को छलने का काम किया, इन्होंने गन्ना किसानों को लूटने का काम किया। दूसरे एक हमारे समाजवादी पार्टी के साथी गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। इनके समय में कितना गन्ना भुगतान हुआ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार ने कितना किया, शायद इनको पता नहीं होगा। गन्ने की पर्ची की बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बी0एस0पी0 की सरकार में किसानों को पर्चियां नहीं मिलती थीं, बल्कि गन्ना दलालों को पर्चियां मिलती थी। किसानों की मेहनत की कमाई का गन्ना, कोयले के दाम में किसान दलालों को बेचते थे। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र पीलीभीत में जहां चार चीनी मिलें हैं, वहां की बात कर रहा हूं कि पीलीभीत के अन्दर गन्ना किसानों की सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में लम्बी कतार खड़ी होती थी। आज कोई भी गन्ना दलाल चीनी मिल के आस-पास नजर नहीं आता। किसानों के लिए हितैषी सरकार है और पूरा का पूरा पेमेण्ट हम गन्ने का अपने पीलीभीत जनपद में लगभग बराबर कर रहे हैं। दूसरी प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही थी कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी और

नोट :-वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औद्योगिक विकास पर चर्चा हो रही थी। मान्यवर, मैं आपको सदन के माध्यम से विपक्ष के साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे जनपद पीलीभीत में बाइस सौ एकड़ जमीन पर इन्हीं के पार्टी के एक मा0 मंत्री जी कब्जा करे हुए बैठे थे। जब बसपा की सरकार थी तो बसपा के मंत्री जी उसको बाइस सौ एकड़ जमीन पर कब्जा करके खेती करते थे और वह जमीन सरकारी जमीन थी। वह जमीन हमारे योगी जी की सरकार ने खाली कराने का काम किया और इससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उस पर अपनी खेती करने का काम किया करते थे। अभी बिजली के क्षेत्र में बात हो रही थी। तो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं मिलता था। आज अगर दूसरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश के अन्दर आओ तो हर गांव में बिजली नजर आती है। हर गांव में बिजली जलती है। 24 घण्टे बिजली शहर में आती है, 18 घण्टे बिजली तहसील में आती है, 18 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में आती है।

मान्यवर, बिजली के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया है। कहते हैं कि खम्भे नहीं बदले, ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले, बिजली के तार लकड़ी के खम्भों पर चल रहे हैं। मान्यवर, अगर थोड़ा-थोड़ा सा काम हमारे इन साथी भाईयों के नेताओं ने किया होता तो शायद ये हमसे यह सवाल नहीं कर रहे होते। इनकी नीयत में खोट था, ये काम करना नहीं चाहते थे। केवल झूठी बातें करना चाहते हैं। इसके अलावा, मैं सर्व शिक्षा अभियान के विषय में बताना चाहता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक डेंगू बुखार चला था और जिससे पूरे प्रदेश में कितने हजारों गरीब नौजवानों की मौत हुई थी। मान्यवर, जबसे योगी जी की सरकार बनी तो डेंगू उत्तर प्रदेश से ही साफ हो गया। आज प्रदेश में कहीं पर डेंगू नहीं है। आज हम बसों की बात करते हैं। मा0 परिवहन मंत्री जी बैठे हैं, पहले बसें कहां चलती थीं। बसें केवल कन्नौज, सैफई, रामपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा में चलती थीं लेकिन आज मा0 परिवहन मंत्री जी ने यदि किसी गांव की आबादी 500 है तो उस गांव को भी बसों के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ दिया है। यह एक बहुत बड़ा काम किया है। मा0 परिवहन मंत्री जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसे ही जितनी प्रशंसा मा0 ऊर्जा मंत्री जी की जाए उतनी कम है।

नीयत जिसकी जिसके इरादे नेक होते हैं, सपने उसी के साकार होते हैं

इरादे भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेक हैं इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने जो सपना देखा है वह सपना आज साकार होता नजर आ रहा है। यह बुआ-भतीजे के गठबन्धन से क्या हुआ कि बुआ जी की दुकान में जनता ने जो अलीगढ़ का ताला डाल दिया था, उस ताले को खोलने की कोशिश भतीजा कर रहा है। जिससे बुआ अपनी दुकान फिर से चला सके नोटों वाली। मान्यवर, यह दुकान चलने वाली नहीं है। जनता बहुत जागरूक है, यह ठग बन्धन, यह गठ बन्धन चलने वाला नहीं है।

श्री सुखेदव राजभर-

थोड़ा कम बोलो, आपने जो शब्द बोले ये उचित नहीं हैं कि बुआ नोटों की दुकान चला रही हैं।

श्री संजय-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ठग बन्धन, गठ बन्धन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना भी जुमलेबाजी कर लें, ये कितने भी भाषण दे लें। यदि एक उंगली हमारी तरफ उठती है।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी एक सेकेण्ड रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, ये बोलें अच्छी बात है, संजय जी अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मैं इनकी उस बात पर आपत्ति कर रहा हूं, जो इन्होंने बोला कि बुआ नोटों की दुकान चला रही हैं, इन शब्दों पर हमारी आपत्ति है। आप इसको निकालें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम इसको देख लेंगे।

श्री संजय-

मान्यवर, नोटों की दुकान चलाने की बात हुई, बुआ तो सबकी हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

तो ये अपनी बुआ को कहेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात कहिए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इनका संकेत कहां है, किस तरफ के लिए है ? इसलिए उसको निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, हम आपकी आपत्ति देख लेंगे।

श्री संजय-

मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने आगरा से लखनऊ तक एक एक्सप्रेस-वे बनाया, ये उसका ढिंढोरा पीटते घूम रहे हैं। मान्यवर, हमारी सरकार को अभी दो साल भी नहीं हुए, 296 किलो मीटर बुन्देलखण्ड का एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे जो

बहुत बड़ा बनने जा रहा है, इसके अलावा 151 किलो मीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बन रहा है। हमने बहुत सारी सड़कों के क्षेत्र में काम किया है। मान्यवर, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

इबादत वो नहीं कि सिर्फ माला घुमा देना,
इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना,
किसी रोते हुए को हंसा देना,
किसी उजड़े हुए को बसा देना।

बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द-जय भारत।

*** श्री अमिताभ बाजपेई-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। नेता विरोधी दल ने जो संशोधन पेश किए हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात हो रही है तो हम कानपुर शहर से आते हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कानपुर के चर्म उद्योग को रखा गया है। कानपुर शहर का चर्म उद्योग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। लेकिन ये कैसी विडम्बना है। कानपुर का चमड़ा उद्योग, आज ही के अखबार में है कि सौ टेनरी वालों ने कलकत्ता में जाकर आज एम0ओ0यू0 साइन किया है। कलकत्ता में जाकर जमीन ली और चर्म उद्योग शिफ्ट हो रहा है जिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप कहते हैं कि चमड़ा उद्योग से, टेनरी से गंगा नदी में प्रदूषण होता है। हम सभी लोग गंगा नदी को उतना ही पूज्य मानते हैं जितना आप मानते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि टेनरी से प्रदूषण नहीं होता क्योंकि टेनरियों के लिए सी0टी0पी0 की व्यवस्था की गयी थी जिसका खर्चा हर महीने टेनरी वाले देते हैं लेकिन सी0टी0पी0 आप नहीं चला पा रहे हैं, आपकी मशीनरी में खोट है, आपके जल निगम में भ्रष्टाचार है। सी0टी0पी0 आप नहीं चलाते और बन्दी टेनरी मालिकों को भुगतनी पड़ती है। बन्दी का भुगतान टेनरी के गरीब मजदूरों, ठेलों वालों को और वहां के गरीबों को करना पड़ता है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें उन व्यापारियों की, आज कानपुर के अन्दर मण्डी का व्यापारी बुरी तरह से आन्दोलित है। वह प्रतिदिन धरना-प्रदर्शन और आन्दोलन कर रहा है। आपने जी0एस0टी0 लगाने के बाद वायदा किया था कि 'एक देश एक कर' की व्यवस्था रहेगी जबकि आपने मण्डी के ऐसे आइटमों पर जो उत्तर प्रदेश में पैदा भी नहीं होता, मसलन मखाना जो पूजा के काम आता है, सुपारी और जीरा जो उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं होता वह प्रदेश के बाहर से आता है उन पर आपने मण्डी शुल्क और सेस लगाने का काम किया है। इसलिए हम आपकी जो व्यापारी

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समर्थक नीति की बात करते हैं वह यह साफ-साफ बताता है कि आप व्यापारी समर्थक नहीं, व्यापारी विरोधी हैं। अभी मैंने बात की पहले बड़े व्यापारी टेनरी वाले परेशान, मध्यम व्यापारी, थोक वाले परेशान और तो और ठेला, पटरी, रेड़ी, गरीब दुकानदार भी आज इस कदर परेशान है कि आप जहां चाहते हैं आपकी पुलिस जाकर लाठी मार कर उनको भगा देने का काम करती है। आप जहां चाहते हैं वहां पर उनसे पैसा वसूल करके ठेला लगवाने का काम करते हैं। ठेले वाला आज डरता रहता है उसे रोज सुबह पता नहीं होता कि मैं ठेला लेकर जा रहा हूं, मैं ठेला लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। मोदी जी कहते हैं पकौड़े का ठेला लगा लो, पकौड़े का ठेला लगाना एक बहुत अच्छा व्यापार है। हमने कई बार पूछा कि हमने पकौड़े का ठेला लगा तो लिया है जरा जगह बता दें कहां। एक कानून है जिसको फेरी नीति कहते हैं। उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता जीविका संरक्षण अधिनियम की धारा-36 में यह प्रावधान है कि ठेले वालों को भी एक प्रॉपर जगह दी जायेगी जहां पर जाकर वह ठेला लगा सकेंगे लेकिन आपकी सरकार फेरी नीति का उल्लंघन कर रही है। आपकी सरकार में गरीब, ठेला, पटरी, रेड़ी, दुकानदार पुलिस के भरोसे पर रोजगार करने को मजबूर हैं। पुलिस जब चाहती है लाठी मार कर उनको भगा देती है और अगर पुलिस को पैसे देते हैं तो ठेला लगा पाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जहां एक तरफ उद्योगपति परेशान, एक तरफ वह मध्यम वर्गीय व्यापारी परेशान, वहीं गरीब ठेले वाला तक परेशान है। इन सबसे मिलकर जो परेशानी पैदा होती है आज गरीब मजदूर परेशान है।

आप अपराध नियंत्रण की बात करते हैं हमारे जिले में 36 हाफ एनकाउन्टर हो गये। यह हाफ एनकाउन्टर शब्द तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं था, पहली बार यह हाफ एनकाउन्टर शब्द आया है। शुरू की आठ घटनाओं में पहले अपराधी भी घायल हुआ और पुलिस वाला भी घायल हुआ। एक दिन एक अधिकारी मिले मैंने उनसे कहा कि भाई अगर अपराधी घायल हो रहा है तो बेचारे पुलिस वाले मासूम को क्यों घायल कर रहे हो ? मान्यवर, यह सच है कि उस दिन के बाद से आज तक कोई पुलिस वाला घायल नहीं हुआ और 36 अपराधी घायल हो गये। न जाने वह कौन-सी कला है कि अपराधी भागता सीधे है और गोली उसके साइड से लग जाती है। कोई गोली हड्डी नहीं पार कर रही, यह गोली कैसे मारी जाती है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। अगर अपराधियों को मार दी जाती तो हमें सुकून होता, 420 का मुल्जिम क्या गोली से मारा जायेगा ? जो डॉक्यूमेंट्री एविडेन्सेस के अपराध हैं वह क्या गोली से मारा जायेगा ? ऐसे अनेक सबूत, अनेक उदाहरण हैं। जब घरों से उठाया गया है और दो दिन तक प्रताड़ित किया गया है, पैसा मांगा गया है और पैसा न दिये जाने पर उसका हाफ एनकाउन्टर कर दिया जाये। आज धमकाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि सुपारी हिटिंग अपराध नियंत्रण के नाम पर हो रही है। अगर पैसा दे दिया तो पाक-साफ, आधा पैसा दीजिए तो हाफ एनकाउन्टर और बिल्कुल मत दीजिए तो फुल एनकाउन्टर। यह एक उद्योग चल रहा है। आपका क्राइम अगर नियंत्रित हो गया होता तो, आदरणीय सतीश महाना जी यहां

सदन में नहीं हैं हमारे शहर में मंत्री की बहू से उन्हीं के यहां के शादी के कार्यक्रम में जिसमें दर्जनों मंत्रियों के प्रोटोकॉल लगे हुए थे उसी कार्यक्रम स्थल के बाहर से उन्हीं की बहू का हार लूट लिया गया। आज गन प्वाइंट पर बाजारों के अन्दर से व्यापारियों से पैसा लूटा जा रहा है। आज दर्जनों लूट की घटनाएं हो रही हैं। अगर ऐसे नीम-हकीमी से अपराध नियंत्रण होना होता तो न जाने कब का हो जाता। इसलिए आपकी अपराध नियंत्रण की, कानून व्यवस्था की बात बेमानी है।

बहुत-सी बातें धान के ऊपर हो रही हैं क्या आपने धान खरीद के रिकार्ड कायम किये। माननीय मुख्य मंत्री जी 15 नवम्बर को हमारे शहर में आए। वह एक धान नियंत्रण केन्द्र में गये और उन्होंने उस धान नियंत्रण केन्द्र को देखा। एक हफ्ते बाद मेरी भी जिज्ञासा बनी कि जिस नियंत्रण केन्द्र को माननीय मुख्य मंत्री देखकर आये थे उसकी असलियत हम भी देख आएं। मान्यवर, उसका मैंने वीडियो बनाया है। उस दिन तक आठ दिन में केवल आठ पर्ची कटी थी और आठ में दो पर्ची उस दिन की थी जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे। उन आठ में से सात पर्चियां जिसकी मूल कॉपी किसान के पास होनी चाहिए थी वह भी उस किताब में लगी हुई है। वह पर्ची फाड़ी नहीं गयी इसका मतलब वह धान बेचने वाला कोई किसान नहीं था वह कोई न कोई बिचौलिया था। केवल धान के किसान का नाम और एकाउण्ट नम्बर इस्तेमाल किया जा रहा था। उसका मैंने वीडियो बनाया, अधिकारियों को अवगत कराया और मीडिया में भी आया लेकिन आज तक इसमें कोई जांच नहीं की गयी। यह इस सरकार की धान खरीद के प्रति जो गम्भीरता है वह दर्शाता है। हम लोग शहर के विधायक हैं। जब हम लोग बड़े-बड़े नाम सुनते हैं, स्मार्ट सिटी हम सुनते हैं, अमृत योजना हम जब सुनते हैं, नमामि गंगे हम सुनते हैं, स्वच्छ भारत मिशन सुनते हैं तो हमारे मन में उम्मीद जग जाती है कि शायद हमारे शहर का कायाकल्प हो जायेगा। हमारे मन में उम्मीद जग जाती है कि शायद हमारा शहर साफ हो जायेगा। लेकिन जहां जाइये कूड़े के अम्बार लगे हैं। कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन की टीम आती है एक-एक हफ्ता रुकती है, जाने कहां घूमा करती है, एक गली साफ नहीं हो पा रही है। कूड़े के अम्बार लगे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। एक कूड़ा घर ऐसा है जिसमें सिर्फ गाय और सांड़ की गोष्ठी होती है। आप किसी टाइम जाइये 100 से 150 गाय और सांड़ उसमें गोष्ठी करते हुए मिल जायेंगे। ऐसे-ऐसे कूड़ाघर हैं जिसमें एक ही कूड़ाघर में गाय, सांड़, सूअर और कुत्ते एक साथ बैठक करते मिल जायेंगे। ऐसे-ऐसे कूड़ाघर आपने बना रखे हैं, साफ करने की कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। शहरों में सीवर बह रहा है।

पेयजल की परियोजनायें पूरी नहीं हो रही हैं। नमामि गंगे के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सीवर का जो चैम्बर हमारा नगर निगम 6,500 में बनाता था वही सीवर का चैम्बर आज नमामि गंगे में 28,500 में बन रहा है, इसकी आप जांच कर सकते हैं। हम लोग बार-बार लिख रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है। इसमें कहीं

न कहीं बड़े स्तर पर मिली-भगत है। पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर बड़ी-बड़ी कम्पनियों को ठेका दिया जा रहा है, उसमें बड़े स्तर पर मिली भगत हो रही है, घाल-मेल हो रहा है। हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं की, ऐसी धोखेबाज योजनाओं की भी जांच करा ली जाय। हम शहरों को अगर शहर न बना सकें तो कम से कम उनका इतना बुरा हाल न बनायें। आज शहरों की सूरत खराब है। हमने एक बच्चे से कह दिया कि कानपुर आये हो तो चिड़ियाघर घूमकर आना, तो उस विदेश से आये हुए बच्चे ने कहा कि यहां तो सड़क पर ही चिड़ियाघर है। जहां से निकलते हैं वहां जानवर दिखायी पड़ जाते हैं, यहां चिड़ियाघर जाने की क्या जरूरत है। कम से कम इतना अपमान मत कराइये। आप लोग शहरों से जीतकर आते हैं। आप शहरों की पार्टी कहे जाते हैं। बड़े-बड़े नारे आपके अभिभाषण में लिखे हुए हैं, शहरों के नाम पर, कुछ तो अमल में लाइये, ज्यादा नहीं थोड़ा ही साफ कर दीजिए। ज्यादा नहीं करिये तो कम से कम जानवर हटा दीजिए। कम से कम गरीब के जीने का सहारा बना दीजिए उसकी रोजी-रोटी पर संकट न बनाइये। आज हम लोग शहर के विधायक लोग एक-एक एल0ई0डी0 लाइट लगवाने के लिए मोहताज हैं। जो सोडियम लाइट 4,500 रुपये की आती थी, आज आपकी एल0ई0डी0 लाइट 15,000 रुपये की आ रही है। हम विधायक हैं और शर्म से कहते हैं कि मैं चाहूं भी तो किसी के घर के बाहर एक एल0ई0डी0 लाइट लगा करके उसके घर के बाहर रोशनी नहीं कर सकते। ये हालत आपने बना दी है। आपके वादे बड़े-बड़े हैं, आपकी बातें बड़ी-बड़ी हैं। कम से कम जमीनी हकीकत को भी स्वीकार करिये। हम लोग विपक्ष के लोगों की रोज जब आलोचना करते हैं तो हमारी नीयत केवल आपको कटघरे में खड़े करने की नहीं होती। हमारी नीयत यह होती है कि हमारे पास अनुभव है हम लोगों ने सरकारें चलाई हैं। हमने अपनी कमियों से सीखा है। अगर हम अपनी कमियों से आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, तो आप भी सीख लीजिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें और आपको कम से कम गाली न दे। ऐसी व्यवस्था हम लोग बना लें। इन्हीं सब बातों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैंनें अपने कानुपर शहर की समस्याओं से जोड़ करके केवल एक बात पर मैं धन्यवाद दे सकता हूं। पिछली बार जो ये कोरे वादों का जो पुलिन्दा था, वह 67 पेज का था और इस बार यह झूठा पुलिन्दा केवल 30 पेज का है। मुझे लगता है कि मा0 राज्यपाल जी ने भी इस पर थोड़ा संकोच किया है। उन्होंने भी कह दिया कि ज्यादा नहीं बोलूँगा झूठ इसलिए 67 पेज से घटकर 30 पेज पर आ गये। इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। बाकी शेष बातों के लिए राम गोविन्द चौधरी, नेता विरोधी दल से सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

चौधरी उदयभान सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बल देने के लिए, समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं और अपनी आवाज समर्थन करने वाले विधायक, श्रीमान् सुनील शर्मा जी के साथ आवाज से आवाज मिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इस बजट में समाज

के प्रत्येक वर्ग को समर्थन भी मिला है और उसकी चिन्ता भी की गयी है। जितनी प्रशंसा इस बजट की कि जाय उतना कम है। मैं जबसे आया हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है, बजट पर अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है।

चौधरी उदयभान सिंह-

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ये हमारे कुछ मित्र जो अपनी बात को केवल आलोचना के रूप में रखना चाहते हैं। मैं गवाह हूं। आज मुझे बड़ी प्रसन्ता हुई थी जब प्रतिपक्ष के नेता हमको शिक्षा दे रहे थे शालीनता और सभ्यता की। मैं गवाह हूं उस समय का जिस समय इस सदन में धुआंधार हिंसा हो रही थी। केशरी नाथ त्रिपाठी जी को जैसे-तैसे मैंने और मेरे अनेक साथियों ने बचाया था। मैं मीराबाई गेस्ट हाउस का प्रत्यक्षदर्शी हूं। जो हिंसा में उतारू थे, आज वे ही लोग हमको सभ्यता की शिक्षा दे रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। चलो आये तो सही, देर से आये लेकिन दुरुस्त आये।

मैं अपने मित्र आदरणीय श्री लाल जी वर्मा से कहना चाहता हूं। मैं फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र से आया हूं। इससे पहले आगरा ग्रामीण क्षेत्र पूर्व का दयालबाग से विधायक रहा था। आज जहां मेरा कृषि फार्म है, जहां इण्टर कालेज है वहीं 18 फरवरी, 2018 को एक प्रकरण लालऊ गांव में हुआ। उसको किस तरीके से गुमराह किया गया। हमारे आदरणीय श्री लाल जी वर्मा ने क्या-क्या कहा, मैं भी घबड़ा गया। इत्तिफाक से 18 तारीख को मैं यहां था। हुआ क्या, जानकारी मिली। मैं पूरे सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हरेन्द्र और केशरी दोनों सगे भाई हैं, मैं वहां का रहने वाला हूं और 50 वर्ष से कृषि फार्म चला रहा हूं, इण्टर कालेज भी चला रहा हूं। 1993 में मैं विधायक भी रहा हूं। दोनों सगे भाई हैं और हरेन्द्र की संजली और केशरी के योगेश और विजय दोनों बेटे हैं। दोनों एक ही घर में रहते हैं। दोनों में भाई-भाई के रिश्ते लेकिन किस तरह से कुत्सित सम्बन्ध बने, शर्मनाक सम्बन्ध बने। इनको भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन पर, शान्ति व्यवस्था कायम करने के नाम थोपा गया। मैं केवल इतना ही कहना नहीं चाहता।

मैं अपनी सरकार की शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और विद्युत के क्षेत्र में भी कहना चाहता हूं। किसी भी क्षेत्र में चले जाइये। शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने कितनी कामयाबी प्राप्त की है। मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से, मैं 1993 का गवाह हूं जिस समय राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिक्षा की नकल पर और शिक्षा की गिरावट पर प्रहार किया गया था। अब जब फिर से भारतीय जनता पार्टी आई है उन्होंने फिर से शिक्षा को ऊपर उठाने के लिये प्रयास शुरू किया है। आज मेरा बेटा, मेरे गांव की औलाद, मेरे गांव का नौजवान केवल आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 बनने की तो बात ही नहीं करते। केवल हाई स्कूल, इण्टर का सर्टीफिकेट मिल जाय, नकल से मिल जाये,

एक हजार रुपये में, पांच हजार रुपये में, दस हजार रुपये में इनके जमाने में अनेक प्रकार की डिग्रियां मिल रही थीं। आज मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद देना चाहता हूं और योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक सदस्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं जिसने शिक्षा के अन्दर ईमानदारी, और योग्य बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। मैं एक चीज के लिये और साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं जिस तरीके से यह गोवंश कट रहा था। जो भी राम और कृष्ण की औलादें, जो भी राम और कृष्ण से अपना सम्बन्ध रखता है, जो राम और कृष्ण को अपना ईष्टदेव समझता है, वह गायों को कटते हुये आह करता था, यह एक कारोबार बन गया था, लेकिन आज उस कारोबार पर प्रहार किया गया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा किया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि न्याय पंचायत के आधार पर गौशाला का निर्माण और अधिक से अधिक होना चाहिये। जितना बजट में दिया गया है वह मैं समझता हूं कि कुछ कम है, इससे ज्यादा न्याय पंचायत के आधार पर और अधिक से अधिक बजट दिया जाय, मैं इसके लिये आपसे गुजारिश करता हूं। मुख्य मंत्री जी ने आंगनबाड़ी, आशा बहुयें, प्रान्तीय रक्षकों को और होमगार्ड आदि का जो गरीब तबका है, उसकी तरफ सोचा है मैं उसके लिये भी साधुवाद देना चाहता हूं। मैं मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन एवं कुष्ठावस्थान एवं मानसिक मंदित आश्रयगृह स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गयी है, उसके लिये भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं फतेहपुर सीकरी से चुनकर आया हूं। फतेहपुर सीकरी का नम्बर पूरे विश्व में आगरा के ताजमहल के बाद आता है।

श्री अध्यक्ष-

तो आप हम सबको ले चलिये कभी वहां।

चौधरी उदयभान सिंह-

मैं कहना चाहता हूं। फतेहपुर सीकरी के बुलन्द दरवाजे के बिल्कुल सामने ग्वालियर गेट के नाम से पत्थर का जो मुगलकालीन गेट है उसके पास सैकड़ों क्यूसेक पानी वर्षों से भरा हुआ है उसके निकलने का कोई माध्यम नजर नहीं आता है। नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करता हूं कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, हो गया ?

चौधरी उदयभान सिंह-

मान्यवर, अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा रह गया है।

श्री अध्यक्ष-

एक पन्ना रह गया है ? वर्मा जी आपसे नाराज हो रहे हैं। (हंसी)

चौधरी उदयभान सिंह-

मान्यवर, मेरे यहां राणा सांगा और बाबर का युद्ध मशहूर है। वहां खांगड़ा के मैदान में सैकड़ों बीघा जमीन जंगल के रूप में पड़ी हुई है। मेरा सुझाव है कि राणा सांगा और बाबर का युद्ध जो दुनिया में प्रसिद्ध है, जिस राणा सांगा ने दांत खट्टे कर दिये थे, वीरता की सबसे अग्रणी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हो गया था, आज उसकी यादगार में, उसकी स्मृति में लाइट और साउण्ड बन करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहां महाराजा सूरजमल, भरतपुर का नरेश जिसने लम्बे समय तक अंग्रेजों और मुगलों के दांत खट्टे किये। तेरामोरी बांध पर उसकी भी स्मृति चिन्ह बनना चाहिए। राजा टोडरमल, जिसने पूरे विश्व में भू-विन्यास मानचित्र बना करके जमीन को नापने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

इसका अभिभाषण से सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी उदयभान सिंह-

मान्यवर, राजा टोडरमल की समाधि फतेहपुर सीकरी के अन्दर है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उस पर भी काम होना चाहिए। बुलन्द दरवाजा, फतेहपुर सीकरी से मात्र 100 मीटर दूर, एक उपलब्ध जमीन है, जहां सौन्दर्यीकरण का काम होना चाहिए। राजमार्ग गुणवत्ता बाजार में ग्रामसभा की बहुमूल्य जमीन पड़ी हुई है, उसका भी सौन्दर्यीकरण होना चाहिए। बैमर विकास खण्ड में, अकोला में श्री गंगाराम एवं बुलाकीदास, जिनका इतिहास लोकोक्तियों में है, उनके भग्नावशेष मौजूद हैं, उनके भग्नावशेष का पुनर्निर्माण होना चाहिए।

(श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

धीरेन्द्र जी क्यों खड़े हैं, बैठ जाइये।

उदयभान जी, अब आप समाप्त करिये।

चौधरी उदयभान सिंह-

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी में जो क्षेत्र पूरे विश्व में जिसके नाम से है, मा0 स्वतंत्र देव सिंह जी से भी मैंने इस सम्बन्ध में 2-4 बार कहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

चौधरी उदयभान सिंह-

मान्यवर, लेकिन वहां से कोई बस नियमित नहीं चलती। मान्यवर, वहां एक बढ़िया राज्य स्तर का अन्तर्राज्यीय एक बस अड्डा बनना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। क्या बरेली के श्री अरूण जी चले गये ?

चौधरी उदयभान सिंह-

मान्यवर, बस दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। फतेहपुर सीकरी में रूनकता, श्रृंग ऋषि और यमुना के पश्चिम भाग में उससे बड़ा कोई दूसरा क्षेत्र बन नहीं सकता। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जहां पर श्रृंग ऋषि ने जन्म लिया, जहां भगवान परशुराम की माता की तपोभूमि रही, जहां श्रृंग ऋषि की तपोभूमि रही, जहां पर द्रौपदी जी को ब्रह्मा जी ने अक्षयपात्र दिया, ऐसी जगह हमारे पास में है और उसका मिल करके समेकित विकास होना चाहिए और इस योजना पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा जारी रहेगी।

अब मद संख्या-27 लेते हैं।

[04:13] भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने विषयक डा0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

इसमें डॉ0 नीरज बोरा जी के संकल्प पर चर्चा है, यह चर्चा जारी रहेगी।

बरेली में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिये उद्योगों की स्थापना कराये जाने विषयक डा0 अरूण कुमार द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प

डॉ0 अरूण कुमार-

मान्यवर, बरेली के अन्दर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एक समय था, लोग कहते थे कि ''एक अनार, सौ बीमार'', लेकिन आज हालत यह है कि 'एक रोजगार, हजार बेरोजगार' और यह हालत हमको विरासत में मिली है। पिछली सरकारों ने हालत इतनी खराब कर दी कि रोजगार देने के बाद भी रोजगार मेले लगते हैं, काफी-काफी लोगों को रोजगार दिये जा रहे हैं, उसके बाद भी रोजगार अभी भी कम हैं। हम चाहते हैं कि बरेली के अन्दर इण्डस्ट्रीज और ज्यादा लगें, हालांकि लगाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां पर और ज्यादा लगें ताकि लोगों को रोजगार मिले, धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

श्री लाल जी वर्मा-

इसे समाप्त मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अरूण जी, फिर यह समाप्त मान लिया जाये।

डॉ0 अरूण कुमार-

जी, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे समाप्त किया जाता है।

जनपद फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग में गर्म कांच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

जनपद-शाहजहांपुर विकास खण्ड-खुदागंज के अन्तर्गत काकोरी काण्ड में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा दरोबस्त में क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प

'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी थी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसको समाप्त कर दिया जाये।

'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, इसको समाप्त कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको समाप्त कर दिया जाता है।

[04:14] जनपद कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधायें प्रदान कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिये स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कराये जाने विषयक प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प प्रिंस वीर विक्रम सिंह जी का है, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प श्री मनीष असीजा जी का है, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

[04:15] जनपद प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना कराये जाने विषयक डा0 आर0के0 वर्मा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प डॉ0 आर0 के0 वर्मा जी का है, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुए पक्का कराये जाने विषयक श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी का है, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना कराये जाने विषयक श्री संजय गर्ग द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

मा0 संजय गर्ग जी आप बतायें इसमें क्या करें ?

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, यदि अनुमति होगी तो आज कह देंगे यदि आप जारी रखना चाहें तो जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

अब आज तो सभी का मूड जाने का हो गया है, हम जबर्दस्ती बैठे हैं, हम खन्ना जी लोकल पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, इनको भी यहीं रहना है और हमें नजदीक जाना है। इस पर चर्चा जारी रहेगी।

[04:16] जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131 कटरा के अन्तर्गत नगर पंचायत कटरा को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रिंस वीर विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प प्रिंस वीर विक्रम सिंह जी का है, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक श्रीमती नीलम करवरिया द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प श्रीमती नीलम करवरिया जी का है, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैंसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैंसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना कराये जाने विषयक श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प श्री मनीष असीजा जी का है, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

[04:17] औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री फतेह बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प श्री फतेह बहादुर सिंह जी का है, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

यह संकल्प श्री जवाहर लाल राजपूत जी का है, इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

[04:17] जनपद सीतापुर के गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु महमूदाबाद सहकारी समिति, सीतापुर द्वारा संचालित रामगढ़ चीनी मिल, रामगढ़, सीतापुर एवं दि सेकसेरिया शुगर फैक्ट्री बिसवां, सीतापुर द्वारा समानुपातिक रूप से गन्ना क्रय किये जाने की नीति निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प

(सदस्य श्री ज्ञान तिवारी के सदन में न उपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री ज्ञान तिवारी जी का संकल्प प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है इसलिए यह समाप्त हो जायेगा।

खेती में प्रयोग किये जा रहे खतरनाक, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से प्राप्त होने वाले भयंकर रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं पक्षाघात की जागरूकता विषयक जानकारी शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

इस सूची में दूसरा संकल्प श्री जवाहर लाल राजपूत जी का है, इन्होंने पत्र भेजा है, इसलिए इसे अगली बार प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उप-मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

तीसरा संकल्प प्रिंस वीर विक्रम सिंह जी का है, आप इसे प्रस्तुत कर दें।

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

मान्यवर, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उप-मण्डी की स्थापना करायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह जारी रहेगा।

(सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू के सदन में उपस्थित न होने पर)

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग के अधीन राज्य योजना के अन्तर्गत चैनेज 150.3 से 174.1 गोड़रिया से तमकुहीराज तक 04 वर्ष से अधूरे पड़े बी0एम0सी0टी0 मार्ग के चौड़ीकरण की कार्यवाही शासन द्वारा शीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

इस सूची में चौथा संकल्प श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी का है, वह उपस्थित नहीं हैं इसलिए यह व्यपगत होगा।

[04:18] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08-02-2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के ए0बी0एस0ए0 और ए0बी0आर0सी0 के कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम अवनपुर में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राकेश सिंह की जनपद रायबरेली के गुरूकबक्सगंज थाने द्वारा किये गये कांजीहाउस के अनधिकृत कब्जे को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अविनाश त्रिवेदी की जनपद हमीरपुर के तहसील मौदहा में निजी भूमि पर खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किये जा रहे अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा छठी सूचना श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में अवैध कालोनी काटे जाने के सम्बन्ध में है जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना डॉ0 जी0एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैंट में दयानन्द कालोनी में देवरी रोड से यादव सिंह के मकान तक नाली एवं सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में विद्युत लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती में सीताद्वार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत संचालित कतिपय माइनर नहरों को जनपद बाराबंकी के नियंत्रण से हटा कर जनपद अयोध्या के नियंत्रण में किये जाने के समबन्ध में है जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री सुरेश राही की जनपद सीतापुर के तहसील लहरपुर में रपटा पुलिया से बाढ़ की उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय ग्रामों में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत कटरा से खुदागंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित रानी लक्ष्मी बाई अस्पताल को माडल चिकित्सालय के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत

सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर में छोटी सरयू नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कृषकों को भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के फरीदपुर नगर में राजकीय राजमार्ग पर ट्रामा सेन्टर का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गईं :-

1-श्री बम्बा लाल,
2-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''
3-श्री सुशील कुमार शाक्य,
4-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,
5-श्रीमती राजबाला,
6-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान,
7-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट,
8-श्री सत्यवीर त्यागी,
9-श्री नाहिद हसन,
10-श्री राकेश प्रताप सिंह,
11-श्री ज्ञान तिवारी,
12-श्री अजय कुमार 'लल्लू',
13-सुश्री अदिति सिंह,
14-श्री मसूद अख्तर,
15-श्री दलवीर सिंह,
16-श्री नरेश सैनी,
17-श्री जवाहर लाल राजपूत,
18-डा0 मंजू शिवाज,
19-श्री सत्यपाल सिंह राठौर,
20-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
21-श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल,
22-श्री विनय शंकर तिवारी,
23-श्री संजय प्रताप जायसवाल,
24-श्री नफीस अहमद,
25-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव
26-इंजी0 बृजेश कठेरिया,
27-श्री मनोज कुमार पारस,
28-श्री अमिताभ बाजपेई,
29-श्री पारसनाथ यादव,
30-श्री सोवरन सिंह यादव,
31-श्री उमाशंकर सिंह,
32-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह,
33-श्री लाल जी वर्मा,
34-श्री सुखदेव राजभर,
35-श्री हाकिम लाल बिन्द,
36-श्री मुजतबा सिद्दीकी,
37-श्री आजाद अरिमर्दन,
38-डा0 हरगोविन्द भार्गव,
39-श्री कपिल देव अग्रवाल,

40-डा0 अरूण कुमार, ''पप्पू भइया''
41-श्री राहुल प्रकाश, 44-डा0 अनिल कुमार मौर्य,
42-श्री हरीराम, 45-डा0 डी0सी0 वर्मा तथा
43-श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य 46-डा0 नीरज बोरा।

जनपद जौनपुर में तहसील मड़ियाहूं में फर्जी निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लीना तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा उल्लिखित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला पंचायत राज अधिकारी, जौनपुर के पत्र ....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 07-02-2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण की जांच उपायुक्त श्रम-रोजगार, जौनपुर से कराई गई। जांचोपरान्त पाई गई दुरुपयोग की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या-3116, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 द्वारा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत-रामपुर निस्फी को नोटिस एवं कार्यालय आदेश संख्या-4768/पंचायत/जांच/2018-19, दिनांक 18 जनवरी, 2019 द्वारा वसूली आदेश पारित किया जा चुका है।]

जनपद अलीगढ़ में कटपुला-रसलगंज जीटी रोड व लल्लामल-बगीची-शाहजमाल के मध्य प्राइवेट बसों का संचालन रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि मार्ग अलीगढ़-खैर-टप्पल जेवर की बसें लगभग पिछले तीन महीनों से खड़ी हुई हैं क्योंकि जिला प्रशासन अलीगढ़ द्वारा 6 सितम्बर, 2018 से .....

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[यू0पी0एस0आर0टी0सी0, अलीगढ़ के अधिकारियों के साथ मिलकर असंवैधानिक नीति विरुद्ध आदेश दिया कि प्राइवेट बसें शहर में नहीं चलेंगी के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जनपद अलीगढ़ के कठपुला रसलगंज, जी0टी0 रोड व लल्लामल-बगीची-शाहजमाल के मध्य प्राइवेट बसों के संचालन के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अलीगढ़ की बैठक दिनांक 31-10-2009 के संकल्प संख्या-6 के पृष्ठ सं0-7 के बिन्दु संख्या-8 पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़ द्वारा ''रसलगंज चौराहा पर (कठपुला के नीचे) से मार्ग पर अत्यन्त सघन यातायात की दृष्टि से मार्ग अलीगढ़-टप्पल-जेवर-बाजना की बसों के खड़े होने से जाम आदि की स्थिति से उत्पन्न होने की समस्या से प्राधिकरण को अवगत कराया गया। सचिव/ सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि पूर्व से ही उक्त मार्ग की एक-एक कर बसें 5 मिनट हेतु इस आशय से खड़ी होती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सिविल कोर्ट तथा कलेक्ट्रेट के कार्य हेतु यात्रियों को इससे सुविधा प्राप्त होगी। उक्त स्थान कठपुला के निकट है, उक्त सुविधा समाप्त होने पर उक्त मार्ग के बस स्वामियों/परमिट धारकों को भी खैर अड्डा (जो कठपुला से 3 कि0मी0 है) से सवारियां उपलब्ध नहीं होंगी। फिलहाल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था न होने तक पूर्व व्यवस्था को जारी रखने पर पुलिस व नगर निगम विभाग विचार कर सकते हैं। इस व्यवस्था को जारी रखने में यदि कोई विधिक व व्यवहारिक बाधा आये तो पुलिस व नगर निगम विभाग इसे समाप्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

2-उल्लेखनीय है कि जनपद अलीगढ़ की शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या, मोटर वाहनों के घनत्व (Trafic Congetion) शहर की जाम की समस्या के दृष्टिगत जनहित में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा बस अड्डों के निर्धारण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में ए0आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन), अलीगढ़, ए0आर0एम0, अलीगढ़, क्षेत्राधिकारी (यातायात), अलीगढ़, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, अलीगढ़ के द्वारा जिलाधकारी, अलीगढ़ को जनपद अलीगढ़ के चारों तरफ के मार्गों पर संचालित होने वाले वाहनों के बस अड्डे निर्धारण के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें अलीगढ़, खैर टप्पल के संचालित बसों के बस अड्डों के निर्धारण का स्थान खेरेश्वर चौराहा (वाजिदपुर नादा गाटा संख्या-98) निर्धारित किया गया।

3-यह भी अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा बैठक दिनांक 05-10-18 में जनपद अलीगढ़ की यातायात व्यवस्था हेतु अलीगढ़-टप्पल-जेवर-बाजना की बसों के संचालन के सम्बन्ध में कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण जो कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई, जिसे सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अलीगढ़

द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-11-18 में रखा गया। प्राधिकरण की उक्त बैठक के संकल्प संख्या-3 पर उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

इस प्रकार बैठक दिनांक 22-11-2018 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अलीगढ़-टप्पल-जेवर मार्ग की सभी बसें संचालित है तथा सरकारी राजस्व की कोई हानि नहीं हो रही है। शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण बस स्टैण्ड नगर के बाहर आर0टी0ए0 द्वारा खेरेश्वर चौराहा पर स्थापित किया गया है, जहां से शहर में जनसामान्य के आवागमन हेतु आटो, टैम्पो, ई-रिक्शा आदि सुविधायें उपलब्ध है।]

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित है।

जनपद अम्बेडकरनगर में दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 को बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं उनके ड्राइवर की हत्या के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अवगत कराना है कि श्री लालजी वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 20-12-2018 को यह सूचना दी गयी कि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री जुरगाम मेंहदी, निवासी ग्राम-नसीराबाद, थाना-हंसवर, जनपद अम्बेडकरनगर आदि ....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[श्री जुरगाम मेंहदी की पत्नी जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। श्री जुरगाम मेंहदी के ऊपर दिनांक 28-04-2015 को भी प्राणघातक हमला किया गया था। श्री जुरगाम मेंहदी द्वारा बार-बार सुरक्षा की मांग की गई, परन्तु प्रशासन द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। हत्या के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करीब 02 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई। कुछ पुलिस कर्मी, उप पुलिस निरीक्षक श्री बृजेश कुमार मिश्रा, हंसवर, थानाध्यक्ष श्री संतोष शुक्ल, उ0नि0 श्री राय का अपराधियों से मिली-भगत होने के कारण श्री जुरगाम मेंहदी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। उनके परिवार के लोगों को भी धमकी मिलती रहती है। उक्त दिन दहाड़े हत्या के कारण क्षेत्र में दहशत का वातावरण बना हुआ है, आम जनता भयभीत है। उक्त घटना पर हत्यारों की गिरफ्तारी एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए सदन में सरकार से वक्तव्य की मांग की गई है।

2-दिनांक 15-10-2018 को वादी श्री फरहान मेंहदी उर्फ आरिफ पुत्र स्व0 जुरगाम मेंहदी, निवासी नसीराबाद, थाना हंसवर, अम्बेडकरनगर के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-129/18, धारा-147/148/149/302/120बी भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट बनाम खान मुबारक व 08-09 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत कराया गया। अभियोग की विवेचना से अभियुक्तगण खान मुबारक आदि 24 नफर प्रकाश में आये। इनमें से अभियुक्त 1-राजमन यादव, 2-रेहान, 3-रिजवान व 4-याहिया को दिनांक 06-11-2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 19-12-2018 को शूटर शहनवाज कुरैशी पुत्र रुस्तम कुरैशी, निवासी जयराजपुर, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़, राजन उर्फ रोहित गुप्ता पुत्र नन्दलाल गुप्ता अभियोग उपरोक्त में 06 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं एवं षड़यंत्र रचने वाले 03 आरोपी जो पूर्व से जेल में थे, उनके विरुद्ध वारण्ट प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अभियुक्त कमरुल जो कि पूर्व से ही जेल में निरुद्ध था, इस अभियोग में रिमाण्ड प्राप्त कर लिया गया है। खान मुबारक जो जिला कारागार लखनऊ में निरुद्ध है, जो इस अभियोग में तलब है किन्तु अभी तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सका है। अभियुक्त 1-जोया खातून, 2-मुमताज, 3-सब्बो उर्फ शबाना, 4-सलमान, 5-अमीर, 6-इरफान, 7-रेहान के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच लखनऊ के द्वारा गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। अभियुक्त 1-रुबीना, 2-वसीम, 3-इम्तियाज, 4-इन्दल का भी प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्त परवेज पुत्र सुबराती के द्वारा मा0 न्यायालय में समर्पण हेतु आवेदन दिया गया है। अभियुक्त प्रमोद गौड़ की सकुनत तस्दीक नहीं हो सकी है। अभियुक्त नीरज सिंह एवं शमसुल के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 83 के लिये आवेदन दिया गया है। अभियुक्त 1-राजभन यादव, 2-रेहान, 3-रिजवान, 4-याहिया, 5-शहनवाज, 6-राजन उर्फ रोहित गुप्ता के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-15, दिनांक 31-01-2019 द्वारा मा0 न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी/कुर्की की कार्यवाही हेतु निरन्तर प्रयास जारी है।

मृतक जुरगाम मेंहदी के पुत्र फरहान मेंहदी निवासी-ग्राम नसीराबाद, थाना हंसवर, जनपद अम्बेडकरनगर के शस्त्र प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के द्वारा रिवाल्वर/पिस्टल का लाइसेंस स्वीकृत किया गया है। जिस पर उनके द्वारा उक्त शस्त्र को

स्वयं के सुरक्षार्थ क्रय किया गया है। इनके जीवन भय एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनपदीय सुरक्षा समिति के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये 01 गनर के अतिरिक्त 01 और गनर दिनांक 05-02-2019 को जनपदीय पुलिस के द्वारा सुरक्षार्थ उपलब्ध कराया गया है। क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम है।]

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा मा0 मन्त्री जी से एक निवेदन है कि हमने आरोप लगाया था इसमें कुछ पुलिस कर्मी भी मिले हुए हैं और जिनके नाम का हमने अपने नोटिस में उल्लेख किया था, उसका इसमें कोई जवाब नही दिया गया है। मैंने श्री बृजेश कुमार मिश्र और कुछ अन्य लोगों का नाम दिया है, और वे लोग वहां आज भी तैनात हैं। मान्यवर, क्या उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्रवाई करने पर विचार करेंगे, जो अपराधियों से मिले हुए हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, उसमें 09 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गयी है और चार्जशीट भी लग गयी है। श्री बृजेश कुमार मिश्रा, डिप्टी एस0पी0 है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, वह डिप्टी एस0पी0 नहीं हैं, सब-इंस्पेक्टर हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 वर्मा जी की जिज्ञासानुसार हम इसकी जांच करा लेते है, तत्पश्चात् सदन को अवगत कराते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र राजपुर मनिहारन के अन्तर्गत सरकारी राशन की दुकानों में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री अतुल गर्ग)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20-12-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि विधान सभा क्षेत्र 06-रामपुर मनिहारन (सहारनपुर) के अन्तर्गत सरकारी राशन दुकानों द्वारा की जा रही घटतौली आदि ....

श्री इकबाल महमूद-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

मा0 मन्त्री जी, मा0 सदस्य निम जी का प्रकरण आप दिखवा लीजियेगा।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों द्वारा उनके क्षेत्र में कार्यरत उचित दर की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण/जांच की जाती है और निरीक्षण में पाई गई कमियों आदि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही भी अमल में लाई जाती है। विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में कार्यरत क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार तहसील रामपुर में अप्रैल, 2017 से दिनांक 24-12-2018 तक कुल 812 निरीक्षण किये गये, 08 उचितदर की दुकानें निलम्बित, 07 उचित दर की दुकानें निरस्त की गईं तथा रु0 76,250/- की धनराशि शासन के पक्ष में जब्त की गई। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, रामपुर मनिहारन की आख्यानुसार हाट शाखा गोदाम से खाद्यान्न का घटतौली कर उठान कराये जाने के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की गई। जांच के समय विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत आने वाले 34 उचित दर विक्रेताओं से खाद्यान्न गोदाम से कम मात्रा एवं घटतौली के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। पूछताछ के समय उनके द्वारा यह लिखित बयान दिये गये कि उन्हें खाद्यान्न गोदाम से सही मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, उन्हें घटतौली कर खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है और न ही घटतौली के सम्बन्ध में कोई शिकायत है। इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के तहसील देवबन्द के ब्लाक नागल में मार्च, 2017 से दिसम्बर, 2018 तक 01 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, 01 उचित दर दुकान निलम्बित की गई, 02 उचित दर की दुकान निरस्त की गई एवं रु0 23000/- की प्रतिभूति शासन के पक्ष में जब्त की गई।

3-जनपद सहानपुर के ब्लाक गोदामों से खाद्यान्न उठान के समय घटतौली रोकने हेतु त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था का अनुपालन कराया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में मार्च, 2017 से 24 दिसम्बर, 2018 तक 812 निरीक्षण किये गये, 01 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गईं, 09 उचित दर की दुकाने निलम्बित की गईं, 09 उचित दर की दुकानें निरस्त की गई तथा रु0 99250/- की धनराशि शासन के पक्ष में जब्त की गई।]

जनपद शाहजहांपुर में दुर्घटना बीमा का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा, श्री मानवेन्द्र सिंह तथा प्रिंस वीर विक्रम सिंह सदस्यगणों द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि श्री रोशन लाल वर्मा जी, श्री मानवेन्द्र सिंह तथा प्रिंस वीर विक्रम सिंह, मा0 सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी कि ''जनपद-शाहजहांपुर में दुर्घटनाओं में जो लोग मृतक/गम्भीर रूप से घायल हुए हैं आदि...

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[विषय पर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 21-11-2018 द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है जो निम्नवत् है :-

1-बीमा कम्पनियों द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2017 से अब तक मृतक/घायल की कुल संख्या-598 है। उसके सापेक्ष कुल 360 लोगों को उक्त बीमा योजना का लाभ दिया गया है।

2-उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से अब तक मृतक/घायल की कुल संख्या 37278 है। उसके सापेक्ष कुल 20151 लोगों को उक्त बीमा योजना का लाभ दिया गया है।

3-मृतक/घायल परिवारों को बीमा योजना के लाभ से वंचित किये जाने के कारण निम्नवत् हैं :-

(क) अधिक/अल्प आयु। (ख) आत्महत्या/प्राकृतिक मृत्यु/दुर्घटना से मृत्यु न होना। (ग) मुखिया/रोटी अर्जक न होना। (घ) पात्रता से अधिक आय। (ङ) दावाकर्ता आश्रित व विधिक उत्तराधिकारी न होना तथा (च) अनुबन्ध के अनुसार आवश्यक कागजातों का न होना।]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह मा0 रोशन लाल वर्मा जी, श्री मानवेन्द्र सिंह तथा प्रिंस वीर विक्रम सिंह जी का प्रश्न है। इसमें बीमा कम्पनियों द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर आदि....

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसमें और कोई सवाल तो नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें केवल वक्तव्य है।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। मुझे जानकारी है ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कम्पनी से टाय-अप कर दिया गया है। किसानों को जैसे पहले बीमा दिया जाता था।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप इसमें क्या चाहते हैं ?

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है, यह गलत सूचना है। एक हजार दुर्घटनाएं हमारे जनपद-शाहजहांपुर में ही हुई हैं, उन्हें बीमा नहीं दिया गया है। यह सूचना इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। यह सूचना सरासर निराधार और गलत है।

श्री अध्यक्ष-

जो उत्तर आया है उसमें तथ्य हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मुझे भी सुनिश्चित जानकारी है कि बीमा कम्पनियों को बीमा न देना पड़े, इसलिए इधर-उधर करके इस तरह का टाल-मटोल करती हैं। कई प्रकरणों में जिलाधिकारी और एस0डी0एम0 के कहने के बावजूद भी, उस समिति के द्वारा पास हो जाने के बावजूद भी बीमा धनराशि का भुगतान नहीं कर रही हैं...

उसके बाद भी बीमा कम्पनियां हीला-हवाली कर रही हैं इसलिए मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। इसका केवल एक जिले से मतलब नहीं है, पूरे प्रदेश के किसानों का हम जो प्रीमियम देते हैं राज्य सरकार द्वारा उसको वहन किया जाता है और प्रीमियम देने के बाद बीमा कम्पनी दुर्घटना होने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करती हैं, 05 लाख रुपया जो मिलना चाहिए वह नहीं देती हैं तो निश्चित रूप से हमारे सरकारी धन का भी अपव्यय हो रहा है और किसान के साथ भी ज्यादती हो रही है। इसलिए मान्यवर, मा0 रोशन लाल वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर फिर से एक कमेटी और बनाकर या अन्य किसी तरीके से, चाहे जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह सुनिश्चित करें जिससे जो वास्तव में इसके पात्र हैं उनको वह धनराशि जरूर मिले जिसके लिए हम राज्य सरकार के मद से प्रीमियम जमा करने का काम करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है मान्यवर, हम इसकी बाकायदा जांच करवा लेंगे।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी मेरा यह निवेदन है कि जो यह सूचना दी गयी है इसमें मात्र 37278 लोगों की सूचना दी गयी है जबकि मेरी जानकारी में है कि पूरे प्रदेश में 80 हजार से ज्यादा लोगों की दुर्घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष-

जब जांच होगी तो उसमें पूरे फीगर आ जायेंगे।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, इसमें पुलिस विभाग से सूचना ली जाये क्योंकि वहां पर एफ0आई0आर0 दर्ज हैं।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज के कतिपय ग्रामों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश से प्राप्त आख्यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के...

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना सूची-2011 में सम्मिलित पात्र लाभार्थियों को ही आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। तत्क्रम में विकास खण्ड-मार्टिनगंज में 63 ग्राम पंचायतों में सेक-2011 की सर्वेक्षण सूची में कुल 3062 पात्र लाभार्थी पाये गये थे। ग्रामवार आवासों के आवंटन हेतु फार्मूला शासनादेश संख्या-49/2016/1987/38-4-16-14 (विविध)/2016 टी0सी0, दिनांक 28-11-2016 में निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर ग्रामवार आवासों का आवंटन किया गया है। उक्त फार्मूले के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों में सेक सूची-2011 में अधिकतम लाभार्थी चिन्हित एवं पात्र थे, उन ग्राम पंचायतों में अधिक आवास आवंटित किये गये हैं तथा जिन ग्राम पंचायतों में सेक सूची-2011 में चिन्हित कम लाभार्थी पात्र थे, उन ग्राम पंचायतों में न्यूनतम आवास आवंटित किये गये हैं। इस प्रकार विकास खण्ड-मार्टिनगंज में वर्ष 2016-17 में 602 आवास, वर्ष 2017-18 में 356 आवास एवं वर्ष 2018-19 में 553 आवासों का आवंटन किया गया है। अवशेष 09 ग्राम पंचायतें जो राजस्व ग्राम से ग्राम पंचायत के अस्तित्व में आई हैं, उनके लाभार्थी सेक सूची-2011 में नाम सम्मिलित न होने के कारण आवास की वेबसाइट पर प्रदर्शित न होने से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया है। उक्त ग्रामों को आवास साफ्ट/आवास ऐप

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु आयुक्त, ग्राम विकास, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2559/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2018, दिनांक 06-12-2018 एवं पत्र संख्या-97-ए/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2016, दिनांक 16-01-2019 द्वारा निदेशक, (ग्रामीण आवास) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा आवास साफ्ट/आवास ऐप पर लाभार्थियों का विवरण प्रदर्शित होने एवं आवास का लक्ष्य प्राप्त होने पर लाभार्थियों को आवास की सुविधा प्रदान किया जाना निर्भर करता है।]

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी वैसे तो यह केवल वक्तव्य के लिये है इसमें स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मान्यवर, केवल वक्तव्य में भी कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, हम तो केवल वक्तव्य में भी अनुमति देते हैं, अभी पहले वाला केवल वक्तव्य ही था जिसमें मा0 श्री लालजी वर्मा और कई विधायक बोले।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी की दो बहुत महत्वपूर्ण योजनायें चल रही हैं एक आवास योजना और दूसरा शौचालय योजना। इस नियम-51 की सूचना के माध्यम से मैंने पूछा था कि इस ब्लाक में कितने-कितने गांव आच्छादित हो गये हैं। इसके उत्तर में यह बताया गया है कि 09 गांवों को न तो आवास मिला है, न ही यहां पर शौचालय बना है। 09 गांव इन दोनों योजनाओं से वंचित हो जा रहे हैं ? क्यों वंचित हो जा रहे हैं, बेबसाइट पर शो नहीं कर रहा है। अब उन्होंने कहा है कि न वहां पर शौचालय बनेगा, न ही आवास बनेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये 09 गांव वंचित न रह जायें वहां भी प्रधानमंत्री आवास और शौचालय बने। ये 09 गांव ऐसे हैं जो राजस्व गांव दूसरे ग्राम पंचायत में सम्मिलित थे, अब वहां से अलग कर दिये गये और अब सेपरेट ग्राम पंचायत हैं और ये आवास व शौचालय से वंचित हो गये हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह दें कि मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जरूर इसको दिखवा लेंगे।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लीना तिवारी द्वारा नियम-51 में दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

डा0 लीना तिवारी, मा0 सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0 द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत जनपद जौनपुर स्थित मडियांहू स्नातकोत्तर महाविद्यालय....

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[के सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र दिनांक 07-02-2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त महाविद्यालय में शासन द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष सम्बन्धित विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त सभी कर्मचारियों वेतन संदाय से वेतन भुगतान किया जा रहा है। बी0एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पद शासन द्वारा अनुदान सूची पर नहीं लिये जाने के कारण प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा अपने निजी स्रोतों से वेतन भुगतान किया जाता है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम दिनांक 11 फरवरी, 2019 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 04 बजकर 27 मिनट पर सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक : 08 फरवरी, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर पीछे पृष्ठ-38 पर)

Directorate of Geology & Mining

5 Years Lease Details of Sand/Morrum

S.No	NAME	DISTRICT	NO OF LEASES	ALLOTMENT DATE	EXPIRY DATE	EC QUANTITY (m3)	Despatched Quantity as on 5 Feb 2019
1	DOLI GARG MS MAHAKALI CONSTRUCTION	AGRA	4	1/31/2018	30/01/2023	121400	95766
2	Arun Kumar Rishabh Herbal Pvt Ltd			23/05/2018	22/05/2023	161800	29357
3	Harvansh Jal			20/06/2018	19/06/2023	121400	17260
4	Ramgopal Chaudhary			15/06/2018	14/06/2023	121400	16539
5	Jitendra Washardeya	ALIGARH	2	21/05/2018	20/05/2023	180000	81687
6	Manjeet Chawla			26/09/2018	25/09/2023	240000	59838
7	Abhishek Dubey Ms Mahadev Enterprises	PRAYAGRAJ	35	30/05/2018	29/05/2023	100000	37357
8	Ajay Kumar Singh Ms Ajay Forwarding			2/15/2018	14/02/2023	60000	8777
9	AJAY LAL			4/11/2018	10/4/2023	110000	46424
10	Anand Kumar Nishad Ms SS Brothers And Company			5/8/2018	7/5/2023	160000	97703
11	Ashish Kumar Patel			1/17/2018	16-01-2023	40000	6585
12	Chandrika Prasad Ms Shiv Traders			1/17/2018	16-01-2023	40000	10001
13	Dhirendra Kumar Diwedi Ms Shanti Construction			3/26/2018	25-03-2023	84000	9916
14	Hausla Prasad Ms Shweta Enterprises			1/12/2018	11/1/2023	40000	0
15	Jai Prakash Keshri Ms J P Construction			1/12/2018	11/1/2023	75000	29955
16	Kamal Kumar Shukla			2/17/2018	16-02-2023	75000	30056
17	MANISH OJHA			1/25/2018	24-01-2023	80000	23393
18	PANKAJ KUMAR TRIPATHI Ms Anushree Associate			1/12/2018	11/1/2023	75000	7513
19	rambhawan singh and ajay singh			2/8/2018	7/1/2023	60000	21193
20	Ramesh Kumar Singh Ms Abhay Enterprises			1/27/2018	26-01-2023	80000	6290
21	Ravindra Kumar Pandey Ms Bajrang Construction			3/11/2018	02/11/2023	90000	4406
22	Sanjeev Kumar Gupta Ms CL Gupta and sons			2/27/2018	26-02-2023	160000	107280
23	SARVESH KUMAR PATHAK			2/21/2018	20-02-2023	160000	133403
24	Smita Jaiswal Ms Smita Enterprises			1/17/2018	16-01-2023	40000	25921
25	Suketa Nishad			12/1/2018	11/1/2023	100000	53840
26	SUNIL RAJAK			20/2/2018	19-02-2023	160000	101584
27	SUNITA SINGH			2/20/2018	19-02-2023	200000	78307
28	Vidyabhusan Singh Ms Friends Group			2/20/2018	19-02-2023	160000	85970
29	Vijay Kumar Nishad Ms Vijay Enterprises			1/12/2018	11/1/2023	60000	42215
30	Vivek Dwivedi Ms Mahakal Enterprises			1/12/2018	11/1/2023	60000	7137
31	Abhishek Singh Ms LM Interprises			2/5/2018	4/2/2023	100000	19694
32	Anjani Kumar Pandey Ms Shreya Enterprises			1/12/2018	11/1/2023	100000	29105
33	Arunendra Yadav Ms Arunaditya			2/5/2018	4/2/2023	80000	20000
34	Babban Singh			12/1/2018	11/1/2023	80000	24562
35	Brijesh Kumar Singh Ms Sudhistbrahm Construction			1/19/2018	18-01-2023	100000	21824
36	Dinesh Chandra Nishad Ms Laxmi Construction			2/5/2018	4/2/2023	100000	24299
37	Hausla Prasad Ms Shweta Enterprises			20/06/2018	19/06/2023	60000	21337
38	Kamal Kumar Shukla			1/17/2018	16-01-2023	100000	70296
39	KOSHLESH KUMAR			1/19/2018	18-01-2023	100000	22462
40	Prakash Chandra Shukla Ms Prakash Enterprises			29/11/2018	28/11/2023	100000	1912
41	RAJ KUMAR SINGH MS R K CONSTRUCTION			19/1/2018	18-01-2023	100000	54145
42	Aditya Singh	AMBEDKARNAGAR	7	1/31/2018	30-01-2023	126288	109889
43	Ajay Kumar			19/12/2018	18/12/2023	112500	4246
44	Ashish Kumar Jaiswal			14/11/2018	13/11/2023	157500	6631
45	Neelam Singh			1/18/2018	17-01-2023	180000	39232
46	Ram Bahadur			1/27/2018	26-01-2023	121200	103369

47	Shimpi Singh			27/11/2018	26/11/2023	126000	30118
48	Shiv Prasad Chowdhary			3/1/2019	02/01/2024	93500	755
49	Alok Kumar Tripathi Pandey and Pandey Brothers	AURIYA	2	1/29/2018	28-01-2023	268875	193592
50	ALOK KUMAR TRIPATHI PANDEY AND PANDEY BRO			19/12/2018	18/12/2023	242943	17258
51	Surendra Tiwari	AZAMGARH	1	22/05/2018	21-05-2023	51100	14230
52	Ajit Singh Malhotra HSM Holdings	BAGHPAT	5	5/15/2018	14-05-2023	310720	70573
53	Mangal Infra Reality Pvt Ltd			2/19/2018	18-02-2023	224358	118423
54	Manish Chauhan			2/21/2018	20-02-2023	97124	88081
55	Manulla Mehbullah Kanchwala Apollo			18/06/2018	17/06/2023	323749	44189
56	MHG LAND STOCKIST Pvt Ltd			2/21/2018	20-02-2023	256084	127990
57	AJAY SINGH	BAHRAICH	4	1/30/2018	29-01-2023	202300	199675
58	Manoj Singh			1/15/2018	14-01-2023	109242	57664
59	Manoj Singh			4/16/2018	15-04-2023	97104	59080
60	Praveen Kumar			1/31/2018	30-01-2023	97876	96863
61	Dadan Khan	BALIA	1	3/16/2018	15-03-2023	119000	57648
62	MADHUBALA	BALRAMPUR	2	15/11/2018	14/11/2023	21000	1628
63	Vinay Singh			2/3/2018	2/2/2023	80000	42599
64	Ajit Singh Jadaun Ms R S I Stone World Pvt ltd	BANDA	22	28/11/2018	27/11/2023	660000	103310
65	Alok Kumar Shukla Ms Falgun Giri			1/12/2018	30/11/2023	78000	25277
66	ATIK ULLAH			1/22/2018	21-01-2023	364200	182566
67	Balkrishna Sharma Ms Chaudhary Eent Udyog			10/12/2018	09/12/2023	260000	48198
68	Devbrat Singh Silverline Automobiles			18/12/2018	17/12/2023	920000	21496
69	Devesh Mishra Starnet Marketing pvt ltd			2/16/2018	15-02-2023	400000	144190
70	DILEEP PUROHIT DIJIYANA MINING CORPORATION			2/26/2018	25-02-2023	100000	77727
71	DILEEP PUROHIT DIJIYANA MINING CORPORATION			1/25/2018	24-01-2023	229400	108578
72	DILEEP PUROHIT DIJIYANA MINING CORPORATION			1/25/2018	24-01-2023	170000	86014
73	DILEEP PUROHIT DIJIYANA MINING CORPORATION			1/25/2018	24-01-2023	400000	144190
74	Giriraj Kumar Sharma Ms Chaudhari Traders			10/12/2018	09/12/2023	505800	69046
75	Manish Kumar Gupta Ms Maa Jayanti Infrastructure			16/11/2018	15/11/2023	640000	162429
76	RAJ KUMAR GUPTA			6/12/2018	05/12/2023	540000	75417
77	Ramnaresh Sharma Jai Ambe Construction			2/7/2018	6/2/2023	372000	277340
78	RANJEET SINGH			1/22/2018	21-01-2023	149200	118599
79	Shiv Chandra Tripathi Tripathi Construction			30/10/2018	29/10/2023	93400	24272
80	Sumant Gupta Ms Mallikarjun Associate			01/12/2018	30/11/2023	210000	38008
81	Tej Bahadur Mishra PK Tradersand Suppliers			2/6/2018	5/2/2023	360000	107789
82	Upendra Kumar Gupta Ms Vamdev Glover Pvt Ltd			29/11/2018	28/11/2023	200000	19000
83	Vasudev Sharma Ms Vasudev Amar Ujala			10/12/2018	09/12/2023	280000	20122
84	Vijay Kumar Singh Ashish Enterprises			3/9/2018	8/3/2023	480000	291751
85	Vipul Tyagi			30/10/2018	29/10/2023	160000	28213
86	Anand Kumar	BARABANKI	2	10/10/2018	09/10/2023	47142	9309
87	Arvind Kumar Singh			15/12/2018	14/12/2023	66447	3304
88	Gurpal Singh MS Book Smart Truck LLP	BAREILLY	3	15/11/2018	14/11/2023	17712	2581
89	Sandeep Kumar Gupta Ms Krishna Traders			20/12/2018	19/12/2023	20976	592
90	Vikas			21/06/2018	20/06/2023	25500	4672
91	NAVI HUSAIN	BASTI	4	1/19/2018	18-01-2023	125860	32798
92	Ram Naresh Chowdhary			1/4/2018	3/1/2023	109340	100794
93	Sher Khan			05/12/2018	4/12/2023	293625	20779
94	Syed Sahil Ali			2/22/2018	21-02-2023	275000	74531

95	Roopa Mishra Ms Lalira Buildcon Pvt Ltd	BHADOHI	2	1/10/2018	9/1/2022	60690	I Yr (60690)+ II Yr(2400) =63090
96	Roopa Mishra Ms Lalira Buildcon Pvt Ltd			1/10/2018	30/09/2023	121410	15385
97	Jitendra Kumar	BADAUN	2	4/25/2018	24-04-2023	86970	23627
98	MOR SINGH YADAV			4/24/2018	23-04-2023	255015	101503
99	MOHD ALI	BULANDSAHAR	1	3/1/2019	1/1/2024	114240	1596
100	AJAY KUMAR SINGH	CHANDAULI	2	1/19/2018	18-01-2023	485600	202449
101	RAJESH PRASHAD YADAV			1/19/2018	18-01-2023	202400	173566
102	Ajayraj Dwivedi	CHITRAKOOT	14	1/29/2018	28-01-2023	228510	142347
103	Anand Kumar Tripathi Ms Tripathi Construction			1/3/2018	2/1/2023	23240	11473
104	Archana Devi			9/1/2019	8/1/2024	54852	2632
105	Arpit Aggrawal Ms Falgun giri mines			1/18/2018	17-01-2023	140280	94247
106	BRAJESH SHAHU Ms G SITARAM			1/20/2018	19-01-2023	124600	15058
107	HIMANSHU SHIV AND COMPANY			1/31/2018	30-01-2023	336140	134971
108	HIMANSHU SHIV AND COMPANY			5/11/2018	10/5/2023	169960	63319
109	Jimmy Singh			2/21/2018	20-02-2023	48600	19494
110	Kamal Pathak Ms Sharda Buildwell Pvt Ltd			4/11/2018	10/4/2023	57820	15364
111	Kavach Kumar Nirmal Ms Prime Vision			9/1/2019	08/01/2024	616095	9597
112	MADHUBALA			1/4/2019	3/1/2023	57015	14414
113	RamaKant			19/11/2018	18/11/2023	101920	10260
114	Shiv Chandra Tripathi Tripathi Construction			6/11/2018	05/11/2023	31864	9979
115	Sumant Gupta Ms Mallikarjun Associate			4/11/2018	10/4/2023	136770	120526
116	Sunil Kumar Ms Ji Construction	ETAWAH	1	2/27/2018	26/02/2023	150546	149525
117	Preeti Singh	FAIZABAD	2	04/01/2018	03/01/2023	61700	19741
118	Sher Khan			20/02/2018	19/02/2023	90000	4220
119	SUBODH SHUKLA MS RC CONSTRUCTION	FARRUKHABAD	2	24/05/2018	23/05/2023	71940	16263
120	Suresh Chandra Dani			12/10/2018	11/10/2023	73660	15786
121	Sudhakar Katiyar	FATEHPUR	9	20/11/2018	19/11/2023	240000	7845
122	Manoj Kumar Yadav Ms Classic Infraventures LLP			31/01/2019	30/01/2024	309600	517
123	Ms Rajesh Mishra Construction and Suppliers			22/03/2018	21-03-2023	251700	135665
124	Sanjay Tyagi Ms Devyash Projects			1/1/2019	31/12/2023	696200	32538
125	Santosh Kumar Yadav Ms Pragya Interprises			4/4/2018	3/4/2023	186200	47278
126	Shiv Pratap Singh Jai Shakti Realcon Pvt Ltd			29/11/2018	28/11/2023	607200	35078
127	Upendra Kumar Gupta Vamdev Glover Pvt Ltd			18/01/2019	17/01/2024	106950	1490
128	Upendra Kumar Gupta Vamdev Glover Pvt Ltd			3/1/2019	02/01/2024	475000	16960
129	vishun singh			5/1/2019	4/1/2024	473550	9564
130	Ajay Pal Singh	FIROZABAD	5	6/10/2018	5/10/2023	104000	8257
131	Arwind Singh Rathore			23/04/2018	22-04-2023	162000	30754
132	Rajesh Sharma			23/04/2018	22-04-2023	169140	36771
133	Sukhveer Singh			21/04/2018	20-04-2023	112000	19587
134	Trilokachand Kushwaha Ms T C Builders			12/04/2018	11/4/2023	160000	47934
135	NAVEEN KUMAR PANDEY MS BALAJI INTERPRISES	GAUTAMBUDDHA NAGAR	3	16/02/2018	15-02-2023	257532	126886
136	Raghvendra Dubey Ms Grit and Moxi Infra Pvt Ltd			25/04/2018	24-04-2023	190200	18886
137	Suyash Jaiswal			17/12/2018	16/12/2023	107700	4023
138	Poonam Chauhan Ms Omkar Laxmi Shubham Pvt Ltd	GHAZIABAD	2	5/11/2018	04/11/2023	45243	15535
139	Vinay Kumar			5/6/2018	04/06/2023	145687	42730
140	Amrita Shailesh Chaturvedi	GHAZIPUR	2	8/2/2018	7/2/2023	110000	59363
141	Rajiv Kumar Pandey			01/02/2018	31-01-2023	150000	39638
142	Ajay Kumar Singh Aradhya Enterprises			1/5/2018	30-04-2023	144000	9324

143	Bheem Singh Kumar Construction Company	GONDA	4	1/5/2018	30-04-2023	144000	12296
144	Karan Bhushan Sharan Singh Nandini Infrastructure			15/05/2018	14-05-2023	576000	173766
145	Mayapati Pandey APM Mining			19/04/2018	18-04-2023	263520	79253
146	Amrendra Sahi	GORAKHPUR	10	3/4/2018	2/4/2023	25000	20368
147	Arvind Singh			3/4/2018	2/4/2023	25000	7989
148	Bindu Pal			06/04/2018	5/4/2023	25000	13222
149	Gauri Shankar Singh			3/4/2018	2/4/2023	25000	10482
150	Laisa Devi			18/04/2018	17-04-2023	25000	5055
151	Meghnath			18/04/2018	17-04-2023	25000	11517
152	Manish Kumar Mishra			21/03/2018	20-03-2023	25000	10629
153	Manoj Kumar Rai			27/03/2018	26-03-2023	25000	17949
154	Rohan Chowdhary Reliable Infrabuild			8/5/2018	7/5/2023	25000	16079
155	Sheela Chand			18/04/2018	17-04-2023	25000	19573
156	Ajay Raj Sunil Sanjay Vaibhav Mahendra Samar	HAMIRPUR	40	28/05/2018	27/05/2023	194304	126310
157	Ajit Singh Malhotra Saurabh Purohit HSM Holdings			14/05/2018	13-05-2023	388608	321406
158	Anil Dixit Ms Kanha Construction Company			7/12/2018	06/12/2023	194304	28726
159	Arun Kumar Rishabh Herbal Pvt Ltd			15/01/2019	14/01/2024	145728	0
160	Atulendra Singh Tomar Ms Shri Construction			07/12/2018	06/12/2023	582912	25112
161	Awadhesh Kumar Ms Yadav and Sons			11/12/2018	10/12/2023	194304	25409
162	BRAJESH SHAHU Ms G SITARAM			21/03/2018	20-03-2023	194304	97376
163	Brijesh Chandra Ms Baba Bhole Nath Traders			4/12/2018	03/12/2023	194304	25384
164	Brijesh Singh Ms New Mirzapur sand stone			17/11/2018	16/11/2023	194304	6906
165	CHANDRABHAN SINGH			7/12/2018	6/12/2023	194304	30830
166	Deepak Sehgal Ms MT International			15/01/2019	14/01/2024	399945	11484
167	Devendra Bhandari Ms AD Agro Foods PVT LTD			7/12/2018	06/12/2023	466330	32203
168	Devendra Bhandari Ms AD Agro Foods PVT LTD			1/12/2018	30/11/2023	194304	24735
169	Dharmendra Singh Tomar Ms New Eon Associate			4/12/2018	03/12/2023	485747	40198
170	Giriraj Kumar Sharma Ms Chaudhari Traders			02/04/2018	1/4/2023	388608	218385
171	Kailash Singh Yadav Ms Pahalwan Traders			8/12/2018	07/12/2023	194304	35446
172	Manju Singh Ms JKS Mining Services pvt ltd			27/11/2018	26/11/2023	388608	50329
173	Mohammad Ashfaq Ms Disha Enterprises			06/12/2018	05/12/2023	728640	56164
174	Navneet Kumar Pandey Ms Balaji Enterprises			19/01/2019	18/01/2024	194304	8080
175	Prashant Malviya Ms Silver Mist Retail Pvt Ltd			03/04/2018	2/4/2023	194304	140027
176	Prashant Malviya Ms Silver Mist Retail Pvt Ltd			3/4/2018	2/4/2023	194304	187277
177	Prashant Malviya Ms Silver Mist Retail Propriter			6/12/2018	05/12/2023	582912	95973
178	PRATAP SINGH TOMAR MS PRATAP CORPORATION			7/12/2018	06/12/2023	388583	26712
179	Prem Shankar Ojha Ms Shark Infracom India Ltd			16/10/2018	15/10/2023	485747	23047
180	Priyesh Gangele Ms Kamtanath Enterprises			7/12/2018	06/12/2023	582912	31384
181	Rahul Gupta			25/01/2019	24/01/2024	582912	4046
182	Ramesh Chandra Mishra Ms Sanevin Infrastructure Pvt Ltd			15/01/2019	14/01/2024	728640	3080
183	Santosh Kumar Sachan			4/12/2018	03/12/2023	323840	22486
184	Sateyendra Kumar Sharma Gyan Infrabuild			1/12/2018	30/11/2023	581912	27666
185	Satish Kumar Gupta Ms Esteem Infrabuild Pvt Ltd			18/12/2018	17/12/2023	728640	38997
186	Saurabh Gupta Ms Satyam Construction			12/12/2018	11/12/2023	219970	18009
187	Suman Devi Ms D V Construction			28/11/2018	27/11/2023	388608	52707
188	Suresh Chandra Gupta			16/10/2018	15/10/2023	194304	23772
189	Sushil Chandra Ms Awasthi Traders			27/11/2018	26/11/2023	194304	30627
190	Umesh Chandra Bansal Ms Kanahiya lal and Sons			1/12/2018	30/11/2023	472806	38243

191	Vikas Parmani Ms Indus Mines and Minerals			21/02/2018	20-02-2023	194304	191075
192	Vikas Parmani Ms Indus Mines and Minerals			17/12/2018	16/12/2023	278502	48494
193	Vikas Sachan Ms Vikas Enterprises			4/12/2018	3/12/2023	728640	69529
194	Virendra Bahadur Singh Ms APM Mining and Infra			15/01/2019	14/01/2024	194304	9756
195	Virendra Singh Ms Rama Traders			4/12/2018	3/12/2023	492236	20953
196	Dharmveer Gupta	HARDOI	2	20/02/2018	19-02-2023	350000	60786
197	SUNITA SINGH			16/02/2018	1/10/2022	199088	87918
198	Ajay Kumar Katiyar Ms New Puja Construction			28/05/2018	27/05/2023	89060	40896
199	Anand Kumar Gupta			3/12/2018	2/12/2023	303630	110309
200	ANKIT GUPTA MAA RAKT DANTIKA CONTRACTOR			16/03/2018	15-03-2023	303630	295644
201	Chandrashekhar Chaurasiya Eureka Mines			3/12/2018	02/12/2023	323880	89163
202	Devendra Gupta			28/05/2018	27/05/2023	202420	170722
203	Karan Singh Rathore Kuber Kamana Marbles Pvt Ltd			3/12/2018	02/12/2023	242910	42063
204	Mahip Kumar Ojha Ms Bindu and Ram Construction			5/1/2019	04/01/2024	303630	32474
205	Nikhil Sharma Ms Khajuraho Motors Pvt Ltd	JALAUN	15	21/01/2019	20/01/2024	303630	7474
206	Raghvendra Singh			16/05/2018	15-05-2023	202420	133189
207	Ramesh Chandra Mishra			28/11/2018	27/11/2023	412950	70706
208	Rupesh kumar chauhan			23/03/2018	22-03-2023	182175	181444
209	Sharif Khan Ms Esteem Infravuled			5/4/2018	4/4/2023	68820	42041
210	Umesh Chandra Bansal Ms Kanahiya lal and Sons			14/05/2018	13-05-2023	8906	8185
211	Vikas Gupta Ms Suresh Chandra Gupta			19/03/2018	18-03-2023	242910	242731
212	Vikas Gupta Ms Suresh Chandra Gupta			04/10/2018	03/10/2023	303630	82726
213	Amandeep Singh Ms AD Agro Foods Pvt Ltd			19/02/2018	18-02-2023	304000	236124
214	ASHISH KUMAR RAI MAA BETAWA TRADING COMPANY			8/2/2018	7/2/2023	203000	124717
215	Ashish Yadav			4/4/2018	3/4/2023	183000	75401
216	Ashish Yadav			16/04/2018	15-04-2023	162000	92068
217	Jagat Vikram Singh Vikram Construction Company			19/03/2018	18-03-2023	195000	184800
218	Kailash Chandra Gupta R S I Stone World Pvt Ltd			19/02/2018	18-03-2023	211000	159999
219	Mayank Tomar	JHANSI	14	7/4/2018	6/4/2023	122000	101951
220	Ramveer Singh Kuber Kamna Marbels Pvt Ltd			14/05/2018	13-05-2023	71000	23057
221	Ramveer Singh Ms Ambe SuppliersPvt Ltd			10/12/2018	09/12/2023	203000	30902
222	Saurabh Kumar Gupta Rising India			20/02/2018	19-02-2023	85000	51799
223	shailendra yadav			7/4/2018	6/4/2023	122000	90147
224	shailendra yadav			7/4/2018	6/4/2023	122000	91459
225	Sharad Pratap Singh Ms Sharad Enterprises			19/02/2018	18-02-2023	90000	21923
226	Shresth Kumar Sahu Ms Vardaan Construction Company			15/05/2018	14-05-2023	183000	85158
227	Anurag Tiwari			4/12/2017	3/12/2022	72000	71512
228	Anurag Tiwari			28/11/2017	27-11-2022	90000	89992
229	BRIJESH KUMAR YADAV	KANNAUJ	5	28/11/2017	27-11-2022	70000	66790
230	Sachin Kumar Maurya			28/02/2018	27-02-2023	92000	41735
231	Suryakant Dixit			30/11/2017	29-11-2022	90000	42249
232	ANKIT GUPTA MAA RAKT DANTIKA CONTRACTOR			21/03/2018	20-03-2023	53757	52611
233	Basant Chaturvedi Ms Parth Constructions			6/12/2018	5/12/2023	198960	13046
234	Ram Avatar Singh Ms Harihar Minerals LLP	KANPUR DEHAT	5	3/1/2019	2/1/2024	274950	14546
235	shailendra yadav			11/04/2018	10/4/2023	194400	50690
236	vishun singh			26/03/2018	25-03-2023	242400	216279
237	Chandrashekhar Chaurasiya Ms Eureka Mines	KANPUR NAGAR	2	4/1/2019	03/01/2024	550000	749
238	Nagendra Singh Ms Vaishnavi Enterprises			7/4/2018	6/4/2023	210000	65584

239	Arwind Singh Rathore	KASGANJ	1	1/1/2019	31/12/2023	180000	1405
240	ABDUL SAMAD	KAUSHAMBI	15	5/2/2018	4/2/2023	360000	135928
241	Arun Kumar Rishabh Herbal Pvt Ltd			11/4/2018	10/4/2023	360000	162737
242	Asif Usmani Bharat Earth Movers			8/1/2019	7/1/2024	360000	12325
243	Jaspal Singh			16/05/2018	15-05-2023	360000	211239
244	KALPANA KARWARIYA KK ASSOCIATES			22/02/2018	21-02-2023	400000	225077
245	Keshari Nandan Singh			20/12/2018	19/12/2023	281400	16769
246	MANISH OJHA			4/1/2019	03/01/2024	360000	9890
247	Nafis Ahmed Ms Kunwar Infradeveloper pvt ltd			15/01/2019	14/01/2024	728000	13924
248	Neelam Singh			17/01/2019	16/01/2024	485000	1241
249	Rajesh Kushwaha Rajesh Enterprises			15/01/2019	14/01/2024	360000	9368
250	Rajesh Sharma			19/02/2018	18-02-2023	480000	203422
251	SRIMANI GUPTA			5/2/2018	4/2/2023	360000	156718
252	Sunil Kumar Pandey Harsh Enterprises			9/4/2018	8/4/2023	360000	289352
253	Syed Sahil Ali			7/3/2019	6/3/2023	360000	159322
254	RAJESH KUMAR SINGH MS R A AND SONS			11/10/2018	10/10/2023	485000	39254
255	Arvind Kumar	KHERI	2	23/05/2018	22-05-2023	22795	6194
256	Pawandeep Singh			24/05/2018	23-05-2023	11758	573
257	Dharmendra Kumar Soni Ms Sadhna Jwellers	KUSHI NAGAR	4	29/05/2018	28/05/2023	9430	4752
258	ms suprayas costruction pro navnath kushwaha			25/01/2018	24-01-2023	60690	1101
259	Rohan Chowdhary Reliable Infrabuild			25/01/2018	24-01-2023	60690	0
260	Syed Sahil Ali			25/01/2018	24-01-2023	19050	0
261	Mahesh Kushwaha Ms Harshal Iron and Steel Company	LALITPUR	9	14/06/2018	13/06/2023	15150	4633
262	ms satyug food amandeep singh			21/05/2018	20/05/2023	12138	0
263	Naresh Kumar Pathak			30/01/2018	29-01-2023	7284	6678
264	Naresh Kumar Pathak			30/01/2018	29-01-2023	12138	1800
265	Naresh Kumar Pathak			22/10/2018	21/10/2023	12144	3
266	Shishir Jaiswal MS Jaiswal Enterprises			13/06/2018	12/6/2023	8496	8494
267	Sukh Sahab Singh			17/04/2018	16-04-2023	6069	1924
268	UMASHANKAR MISHRA			07/02/2018	6/2/2023	12138	5364
269	Mithilesh Kumar Mali Ms Ayushi Construction			15/09/2018	14/09/2023	9714	1495
270	Ms Gadpati Traders	MAHARAJGANJ	3	3/1/2019	02/01/2024	93040	0
271	Rekha Devi			15/12/2018	14/12/2023	54630	3732
272	Sanjay Kumar Madheshia			4/1/2019	03/01/2024	59290	5745
273	Arvind Kumar	MAHOBA	4	8/10/2018	7/10/2023	27000	2130
274	harishankar rajput			8/10/2018	7/10/2023	49500	1956
275	Manish Tiwari Uma Builders			30/10/2018	29/10/2023	36000	141
276	Neelam Tiwari			8/10/2018	7/10/2023	38000	2419
277	Manoj Kumar Sharma	MAINPURI	4	2/6/2018	01/06/2023	2268	708
278	Manoj Kumar Sharma			02/06/2018	01/06/2023	10192	2244
279	Ved Prakash Pathak Ms Vedbhai Associates			2/6/2018	1/6/2023	1078	675
280	Ved Prakash Pathak Ms Vedbhai Associates			2/6/2018	1/6/2023	14756	4851
281	Achal Kumar Sharma Ms Cams Infra Developers	MATHURA	3	23/05/2018	22-05-2023	200000	39603
282	Dheer Singh			05/02/2018	4/2/2023	114940	64578
283	Harvindra Singh Ms SatjugFoods Pvt Ltd			11/12/2018	10/12/2023	82000	0
284	Asharam Ms Asharam Contractors			01/02/2018	31-01-2023	100000	73487
285	Dayashankar Upadhyay Ms Krishna Enterprises			21/05/2018	20/05/2023	100000	41372
286	Gajendra Pratap Singh Ms Vindhya green			5/11/2018	4/11/2023	75000	710

287	Krishna Mohan Tiwari	MIRZAPUR	16	1/1/2018	31-12-2022	80000	45593
288	Krishna Mohan Tiwari			01/01/2018	31-12-2022	100000	10827
289	Kunwar Pal Singh Ms Kunwar enterprises Pvt Ltd			10/4/2018	9/4/2023	100000	58167
290	Kunwar Pal Singh Ms Kunwar enterprises Pvt Ltd			10/04/2018	9/4/2023	100000	86906
291	Rajesh Kumar Tripathi Ms Bol Bam Eet Bhatta			1/1/2018	31-12-2022	100000	98594
292	Rajesh Kumar Tripathi Ms Bol Bam Eet Bhatta			1/1/2018	31-12-2022	100000	96487
293	Ram Gopal Singh Ms Shri Sai Baba Infra Pvt Ltd			1/1/2018	31-12-2022	100000	47110
294	Roopa Mishra Ms Lalira Buildcon Pvt Ltd			1/1/2018	31-12-2022	100000	51645
295	Tilakraj Singh Ms Sumit Ent Bhatta			5/11/2018	04/11/2023	75000	3177
296	Vishnu Kumar Mishra Ms Nav Nirman Infrahieghts			13/02/2018	12/2/2023	100000	28216
297	Vishnu Kumar Mishra Ms Nav Nirman Infrahieghts			13/02/2018	12/2/2023	100000	40087
298	Vishnu Kumar Mishra Ms Nav Nirman Infrahieghts			13/02/2018	12/2/2023	100000	64898
299	Vishnu Kumar Mishra Ms Nav Nirman Infrahieghts			13/02/2018	12/2/2023	100000	53687
300	Neelam Mathur Ms Krishna Construction	MORADABAD	2	24/03/2018	23-03-2023	81930	75580
301	Neelam Mathur Ms Krishna Construction			4/4/2018	3/4/2023	150624	95574
302	Anil Kumar Aggrawal	PILIBHIT	5	22/03/2018	21-03-2023	43911	32335
303	Dharmendra Pratap Singh Ms Earth and Space			28/03/2018	27-03-2023	7380	3708
304	Dushyant Kumar Ms D S Contractor and Builders			22/03/2018	21-03-2023	26280	24705
305	ms satyug food amandeep singh			6/3/2018	5/3/2023	48552	38849
306	ms satyug food amandeep singh			26/04/2018	25-04-2023	21852	14048
307	Shivbhawan Singh	RAE BARELI	1	15/10/2018	14/10/2023	67920	4593
308	Asha Singh	RAMPUR	5	21/02/2018	20-02-2023	24600	18
309	Jitendra Kumar			19/02/2018	18-02-2023	56000	36639
310	Jitendra Singh Bhist			18/04/2018	17-04-2023	26400	20001
311	Rupesh kumar chauhan			18/04/2018	17-04-2023	34600	6345
312	Sharda Devi			17/02/2018	16-02-2023	50000	49878
313	Ashok Rai Ms Rai Constructions	SANT KABIR NAGAR	3	7/4/2018	6/4/2023	250000	125413
314	BALIRAM YADAV			25/01/2018	24-01-2023	73200	24025
315	BALIRAM YADAV			2/1/2019	01/01/2024	105850	2903
316	Ms Virat Construction	SHAHJAHANPUR	1	15/02/2018	14-02-2023	109245	67466
317	Manjeet Kumar Ms MM Traders	SHAMLI	2	16/01/2019	15/01/2024	237270	457
318	Saharyaar Husain			4/1/2018	3/1/2023	96048	97601
319	Nirmal Kumar Pandey	SHRAVASTI	2	18/04/2018	17-04-2023	112000	72433
320	Ram Bahadur			17/02/2018	16-02-2023	51000	13648
321	Shrichandra Chowdhary	SIDDHARTH NAGAR	2	07/12/2018	06/12/2023	48400	4396
322	Suyash Jaiswal			15/10/2018	14/10/2023	80800	18132
323	Amit Kumar Singh	SITAPUR	6	7/4/2018	6/4/2023	44050	20207
324	Dharmendra Kumar Sharma Ms Bharat Construtions			11/10/2018	10/10/2023	92100	15846
325	Dheeraj Verma Ms Radhe construction			29/01/2018	28-01-2023	102708	25598
326	Kailash Saini Ms Saini Traders			20/01/2018	19-01-2023	108000	67371
327	Mukesh Kumar Singh			1/1/2019	31/12/2023	135000	0
328	Tripurari Ms Kamal Enterprises			2/2/2018	1/2/2023	182376	53690
329	Akhilesh Paul	SONBHADRA	3	23/03/2018	22-03-2023	243000	243000
330	Ashish Khemka			3/4/2018	2/4/2023	226800	176134
331	Praveen Kumar			2/4/2018	1/4/2023	243000	227653
332	Ramesh Chandra Yadav Ms RC Builders	UNNAO	1	15/11/2018	14/11/2023	108360	651
	TOTAL		332			56309028	18365803

पी0एस0यू0पी0-एल0 337 विधान सभा (574)-18-03-2020-631 प्रतियां-कम्प्यूटर।